रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

Aug. - SEPT. 1972

सं० 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 5, 1972/श्रावण 14, 1894
No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 5, 1972/SRAVANA 14, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ क्षेत्र प्रशासन को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकरणों द्वारा जारी किये गए विधिक आदेश और अधिसूचनाएं।

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories.)

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture)

New Delhi, the 10th May 1972

S.O. 1912.—In pursuance of clauses (i) and (k) of rule 4 of the General Grading and Marking Rules, 1937, the Central Government hereby fixes, with effect from the date of publication of this notification, the charges of Agmark labels to be affixed on the containers of seedless Tamarind graded under Agmark, at rupee one per quintal.

[No. F. 13/13/71-C&M.]

T. D. MAKHIJANI, Under Secy.

कृषि मंत्रालय
(कृषि विभाग)

नई दिल्ली 10 मई, 1972

का० आ० 1912.—साधारण श्रेणीकरण तथा चिह्नन नियम, 1937 के नियम 4 के खण्ड (ख) और (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से, ऐगमार्क के अधीन श्रेणीकृत बीज रहित इमली के आधानों पर लगाये जाने वाले ऐगमार्क लेबलों का प्रभार 1.00 रु० प्रति क्विंटल नियत करती है।

[सं० फा० 13/37/-सी० एण्ड एम०]

टी० डी० माखीजानी, अवर सचिव।

(Indian Council of Agricultural Research)

New Delhi, the 27th April 1972

S.O. 1913.—In pursuance of Regulation 2(iv) of the Standing Finance Committee Regulations, the following members of the Governing Body of the Indian Council of Agricultural Research have been elected by that Body to be members of the Standing Finance Committee for a period upto 4th August, 1972 or for a period of one year with effect from 28th March, 1972 if they are re-appointed as member of the Governing Body of the Indian Council of Agricultural Research after 4th August, 1972 or in the latter case till such time as their successors are duly elected by that Body whichever is later:—

(1) Shri Shantilal B. Pandya, Pandya Farm, Dohad (Gujarat).

(2) Rani Yadunandan Kumari, Bir Kauli Farms, V. & P.O. Kauli, Patiala.

(3) Shri Sailendra Narayan Bhanja Deo, Kanika Rajbati, Cuttack.

(4) Dr. N. K. Panikkar, Director, National Institute of Oceanography, Panaji (Goa).

(5) Dr. A. S. Paintal, Director, Patel Chest Institute, University of Delhi, Delhi.

(6) Shri Bhanu Pratap Singh, Secretary, Sardar Vallabhai Patel College, Buabua District Sahabad, (Bihar).

2. Shri Z. M. Kahandole, Member Lok Sabha Mateu Chaya, Tilakwadi, Nasik (Maharashtra) has also been elected a member of the Standing Finance Committee for a period of 1 year with effect from 20th April,

1972 or till such time as his successor is duly elected whichever is later.

[No. 35(1)/71-CDN(I).]

T. S. PRUTHI, Under Secy.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1972

एस० ओ० 1913.—स्थायी वित्त समिति की नियमावली के नियम 2 (IV) के अनुसरण में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की शासी निकाय के निम्नलिखित सदस्यों को 4 अगस्त, 1972 तक की अवधि या यदि वे 4 अगस्त, 1972 के बाद भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की शासी निकाय के सदस्य पुनः नियुक्त हो जाते हैं तो दिनांक 28 मार्च, 1972 से एक वर्ष की अवधि के लिये या दूसरी स्थिति में उनके उत्तराधिकारियों के विधिवत् चुने जाने तक, जो भी बाद में हो, शासी निकाय द्वारा स्थायी वित्त समिति के सदस्य चुन लिया गया है :—

1. श्री शान्तिलाल बी पण्ड्या, पण्ड्या फार्म, दोहाद (गुजरात)
2. रानी यदुनन्दन कुमारी, बीर कौली फार्म, ग्रा० एवं डा० घ० कौली, पटियाला।
3. श्री शलेन्द्र नारायण भंजदेव, कनिका राजवती, कटक
4. डा० एन०के० पनिकर, निदेशक, राष्ट्रीय समुद्र-विज्ञान संस्थान, पनजी (गोवा)
5. डा० ए०एस० पेन्टल, निदेशक, पटेल चेस्ट इन्स्टीट्यूट, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
6. श्री भानु प्रतापसिंह, सचिव, सरदार वल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय बुआजुआ, जिला शाहबाद, (बिहार)

2. श्री जैड०एम० खण्डोले, लोक सभा सदस्य मेल्यू छाया, तिलकवादी, नासिक (महाराष्ट्र) को भी दिनांक 20 अप्रैल, 1972 से एक वर्ष की अवधि के लिए या उनके उत्तराधिकारी के विधिवत चुन लिये जाने तक, जो भी बाद में हो, स्थायी वित्त समिति का सदस्य चुन लिया गया है।

[सं० 35(1)/71-सी० डी० एन० (1)]

तेजा सिंह प्रथी, अवर सचिव।

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

(MERCHANT SHIPPING)

New Delhi, the 27th April 1972

S.O. 1914.—In pursuance of rule 5 of the Indian Merchant Shipping (Seamen's Employment Office, Calcutta) Rules, 1954, the Central Government hereby appoints Shri T. Bagchi as a member of the Seamen's Employment Board (Foreign-going) at the port of Calcutta to represent the Shipowners for the remaining term of office of Shri R. N. Ghosal, resigned, and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) S.O. No. 2027, dated the 28th May, 1970, namely:—

In the said notification, in Serial No. 9 for the entry 'Shri R. N. Ghosal', the entry 'Shri T. Bagchi' shall be substituted.

[No. 15-MT(2)/69.]

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

व्यापार नौवहन

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1972

सा० आ० 1914.—भारतीय व्यापार पोत (नाविक रोजगार कार्यालय, कलकत्ता) नियम, 1954 के नियम 5 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री टी० बागची को श्री आर०एन० घोसाल, जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया है, के शेष कार्य काल के लिए, पोतमालिकों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कलकत्ता पत्तन पर नाविक रोजगार बोर्ड (विदेशगामी) का सदस्य नियुक्त करती है और नौवहन और परिवहन मन्त्रालय (परिवहन पक्ष) में भारत सरकार की अधिसूचना सा०आ०सं० 2027 दिनांक 28-5-70 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम सं० 9 में प्रविष्टि "श्री आर०एन० घोसाल" के स्थान पर, प्रविष्टि "श्री टी० बागची" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं० 15-एम०टी०(2)/69)]

ORDER

MERCHANT SHIPPING

New Delhi, the 19th May 1972

S.O. 1915.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby directs that the power exercisable by it under sub-section (3) of section 114 of the said Act (fixing of the amount for which a bond has to be given by the master of a ship under the said sub-section) shall be exercisable also by the Director General of Shipping.

[No. F.19-MT(1)/69.]

A. R. BANERJEE, Under Secy.

आदेश

व्यापार नौवहन

नई दिल्ली, 19 मई, 1972

का० आ० 1915.—व्यापार नौवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 7 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 114 की उपधारा (3) (उस राशि का निर्धारण करना जिस के लिए उक्त उपधारा के अन्तर्गत जहाज के मास्टर द्वारा बांड देना होता है) के अन्तर्गत इसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां का नौवहन महानिदेशक भी प्रयोग कर सकेगा।

[सं० 19-एम० टी० (1)/69]

ए० आर० बनर्जी, अवर सचिव।

(Transport Wing)

New Delhi, the 2nd May 1972

S.O. 1916.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Merchant Shipping Act, 1958, (44 of 1958), read with sub-rucl (2) of rulc 4 of the National Shipping Board Rules, 1960, the Central Government hereby appoints Shri H. M. Trivedi, Member of Parliament, as a member of the National Shipping Board in place of late Shri M. H. Samuel, and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 600 dated the 24th January, 1972, namely:—

In the said notification in the entry against Serial No. 6, for the words "Shri M. H. Samuel" the words "Shri H. M. Trivedi", shall be substituted.

[No. 37-MD(1)/72.]

B. K. SAHI, Under Secy.

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 2 मई, 1972

का० आ० 1916.—राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड नियम 1960 के नियम 4 के उपनियम (2) के साथ पठित व्यापार पोत अधिनियम 1958 (1958 का 44) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा स्वर्गीय श्री एम० एच० सेमुवल के स्थान पर श्री एच० एम० त्रिवेदी, संसद सदस्य का राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त करती है, और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सा०आ० 600 तारीख 24 जनवरी, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्र० सं० 6 के सामने की प्रविष्टि में 'श्री एम० एच० सेमुवल' शब्दों के स्थान पर श्री एच० एम० त्रिवेदी' शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[सं० फा० 37-एम०डी०(1)/72]

बी० के० साही, अवर सचिव।

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

(Department of Tourism)

New Delhi, the 5th April 1972

S.O. 1917.—In pursuance of sub-clause (b) of clause 2 of the Imported Tourist Cars (Control) Order, 1961 and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Department of Tourism) No. S.O. 3342 dated 23rd September, 1967 the Central Government hereby appoints Shri B. N. Raman, Additional Director General, Ministry of Tourism and Civil Aviation, Government of India, to be the Controller of Imported Tourist Cars for the purpose of the said Order.

[No. F. 4. TTI(58)/65.]

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

(पर्यटन विभाग)

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1972

एस० आ०1917.—आयातित पर्यटक कार (नियंत्रण) आदेश, 1961 के खंड 2 के उप-खंड (ख) के अनुसरण में तथा भारत सरकार के पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय (पर्यटन विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 3342 दिनांक 23 सितम्बर, 1967 का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के पर्यटन और नाग विमानन मंत्रालय में अतिरिक्त महानिदेशक, श्री बी० एन० रामन को उक्त आदेश के प्रयोजन के लिए पर्यटक कारों का निदेशक नियुक्त करती है ।

[सं० 4-टी० टी० आई० (58)/65]

New Delhi, the 27th May 1972

S.O. 1918.—In exercise of the Powers conferred by Section 4 of the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953) the Central Government hereby appoints Shri B. Israni Chairman, International Airports Authority of India, as a Director on the Boards of Air-India and Indian Airlines with immediate effect and until further orders.

[No. F.AV18013/3/71-AC]

N. SAHGAL, Secy.

नई दिल्ली, 27 मई, 1972

एस० आ० 1918.—वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत के अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकारी के अध्यक्ष श्री बी० इसरानी को तत्काल एवम् आगले आदेशों तक एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के निदेशक मण्डलों के एक निदेशक के रूप में नियुक्त करतीं है ।

[सं० ए० बी० 18013/3/71-ए० सी०]

एन० सहगल, सचिव ।

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

INCOME-TAX

New Delhi, the 25th March 1972

S.O. 1919.—In partial modification of Notification No. 258, dated 1st September, 1971 as revised by Notification No. 353, dated 17th December, 1971 and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby directs that with effect from 17th December, 1971, the functions of Addl. Commissioner of Income-tax (Recovery), as set out in Annexure B to Notification No. 87 [F. No. 187/13/70-IT(AI)] dated 29th May, 1970 hitherto performed by Addl. Commissioner of Income-tax Recovery II, Calcutta shall be performed by the Commissioner of Income-tax (Central), Calcutta in respect of (Central), Calcutta charge.

[No. 64(F. No. 187/8/71-IT(AI).]

B. MADHAVAN, Under Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

(आयकर)

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1972

एस० ओ० 1919.— अधिसूचना सं० 353, तारीख 17-12-71 द्वारा यथा पुनरीक्षित अधिसूचना सं० 258, तारीख 1-9-71 को भागत: उपान्तरित करते हुए और आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निदेश देता है कि अधिसूचना सं० 87 [फा० सं० 187/13/70-आई० टी० (ए-I)] तारीख 29-5-70 के उपाबन्ध ख में यथा उपवर्णित, (केन्द्रीय) कलकत्ता चार्ज की बाबत, अपर आयकर आयुक्त (वसूली) के कृत्य, जो अब तक अपर आयकर आयुक्त वसूली-2, कलकत्ता द्वारा किए जाते थे, 17-12-71 से आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) कलकत्ता द्वारा किए जाएंगे ।

[स० 64/फा० स० 187/8/71-आई०टी० (ए०-I)

बी० माधवन, अवर सचिव ।

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, POONA

Poona, the 31st May 1972

ORDER UNDER SECTION (1) OF SECTION 124 READ WITH SUB-SECTION (2) OF SECTION 124 OF INCOME-TAX ACT, 1961.

S.O. 1920.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 124 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), I, the Commissioner of Income-tax, Poona, hereby direct that the Income-tax Officer, Collection Circle, Sholapur, shall and the Income-tax Officers A, B, C and D Wards, Sholapur shall not perform the functions relating to collection and recovery as detailed in Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961 [excluding Sections 215 to 217, 219 and Section 220(1)] and in relation to the issue of tax verification certificate in respect of the persons assessable by the above-mentioned Income-tax Officers or by virtue of any order or orders under Section 126 and/or under Section 127 of the Income-tax Act, 1961 or under the corresponding provision of the Income-tax Act, 1922.

2. This order shall take effect from 7th June, 1971.

[No. 141-Sholapur/71-72/Tech.]

आयकर आयुक्त कार्यालय

पूना, 31 मई, 1971

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 124 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) के अधीन आदेश ।

एस० ओ० 1920.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 124 की उपधारा (1) और (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आयकर आयुक्त, पूना एतद्द्वारा निदेश देता हूं कि आयकर अधिकारी, वसूली मंडल, शोलापुर, [धाराएं 215 से 217, 219 और 220(1) को छोड़कर] संग्रहण और वसूली से सम्बन्धित, कार्य जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII में विस्तृत रूप से दिया गया है तथा निम्नलिखित आयकर अधिकारियों द्वारा कर-निर्धारण योग्य व्यक्तियों के विषय में कर सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में या धारा 126 के अधीन कोई आदेश या आदेशों के कारण-वश और/या आयकर अधिनियम, 1961, की धारा 127 के अधीन या आयकर अधिनियम, 1922 के तत्सम्बद्ध उपबन्धों के अधीन, कार्यों को करेगा और आयकर अधिकारी क, ख, ग, और घ वार्ड, शोलापुर इन कार्यों को नहीं करेंगे ।

यह आदेश दिनांक 7 जून, 1971 से प्रभावी होगा ।

[सं० 141-शोलापुर/71-72/तक०]

ORDER UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 12[4] READ WITH SUB-SECTION (2) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961

S.O. 1921.—In exercise of the powers conferred b[y] sub-sections (1) and (2) of Section 124 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in partial modification of my order of even number dated 31st March, 1971, I the *Commissioner of Income-tax, Poona*, hereby direct that the Income-tax Officers, Collection I, Collection II, and Collection III, Poona shall exercise all th[e] functions of an Income-tax Officer concurrently unde[r] Chapter XVII excluding Sections 194, 195(2), 197, 19[9] 214 to 217, 219, 220(1) and Section 140A(3) and Se[c]tion 141 of the Income-tax Act, 1961, and issue notices of demand under Section 156 in respect [of] amounts which become payable as a result of order under Section 140A(3), 141 and 220 of the Income-t[ax] Act, *in respect of persons assessable by Income-t[ax]* Officers, A, B, C, Addl. C, D, E, F, G, Addl. G, J, K, I and M Wards.

2. This order shall take effect from 7th June, 197[1]

[No. 141/Poona/71-72/Tec[h.]

आयकर अधिनियम, 1961 की उपधारा (2) के साथ पढ़े धारा 124 की उपधारा (1) के अधीन आदेश ।

एस०ओ० 1921.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 124 की उपधाराओं (1) और (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मेरे इसी संख्या के आदेश दिनां 31-3-1971 में आंशिक परिवर्तन करते हुए, मैं, आयकर आयुक्त पूना, एतद्द्वारा निदेश देता हूं कि आयकर अधिकारी वसूली वसूली II और वसूली III, पूना, आयकर अधिनियम 1961 के धाराओं 194, 195(2), 197, 199, 214 से 217, 21[9] 220(1) और धारा 140क (3) और धारा 141 को छोड़कर अध्याय XVII के अधीन एक आयकर अधिकारी के समवर्ती सभी का करेंगे, और क, ख, ग, अतिरिक्त ग, घ, ङ, च, छ, अतिरिक्त छ, ञ अतिरिक्त झ, ज, ट, ठ और ड वार्डों के आयकर अधिकारियों द्वारा कर निर्धारण योग्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में, आयकर अधिनियम की धाराओं 140क (3), 141 और 220 के अधीन, आदेशों के अनुसार जो देय राशि है, उस के सम्बन्ध में धारा 156 के अधीन मांग का नोटिस जारी करेंगे ।

2. यह आदेश दिनांक 7 जून, 1971 से लागू होगा ।

[सं० 141/पूना/71-72 तकनीकी]

INCOME-TAX

Poona, the 18th June, 1971

S.O. 1922.—In exercise of the powers conferred on me under Section 124(1) of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) I hereby create the charge of Additional Income-tax Officer (Technical), in the Office of the Commissioner of Income-tax, Poona, within the charge of Commissioner of Income-tax, Poona, with effect from 21st June, 1971.

[No. 141/70-71(Tech.).]

A. BALASUBRAMANIAN,
Commissioner of Income-tax.

(आयकर)

पूना 18 जून, 1971

एस० ओ० 1922.—आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 124(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा दिनांक 21 जून, 1971 से आयकर आयुक्त पूना प्रभार के अन्तर्गत आयकर आयुक्त कार्यालय पूना में अतिरिक्त आयकर अधिकारी (तकनीकी) प्रभार का सृजन करता हूं।

[सं० 141/70-71(तक०)]

ए० बालासुब्रामनियन, आयकर आयुक्त।

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE: KANPUR

CENTRAL EXCISE

Kanpur, the 8th March, 1972

S.O. 1923.—In exercise of the powers conferred on me by Rule 233 of the Central Excise Rules, 1944 I hereby direct that all assessees of excisable goods in Kanpur Collectorate working under Self Removal Procedure as laid down in Chapter VII-A of the Central Excise Rules, 1944 and notified under Government of India's Notifications No. 171/69-CE, dated 21st June, 1969; 121/70-CE, dated 28th May, 1970; 179/71-CE, dated 23rd September, 1971 and 195/71-CE, dated 12th November, 1971 shall file immediately after 6 P.M. on the day prior to the Budget Day (i.e., the 15th March, 1972), a declaration with the Range Officer Incharge of their range with a copy to the Proper Officer in the form appended to this notification. The declaration shall contain:—

(a) The number of last gate pass (G.P. 1 and G.P. 2) issued by the assessee upto 6 P.M. on that day, viz., 15th March, 1972.

(b) The closing balance of stocks held by the assessee at 6 P.M. on that day, viz., 15th March, 1972.

2. The above declaration shall be furnished by the assessee by hand in the Range Office against written acknowledgement where the factories are located at or near the Range Headquarters. Other assessees who may be situated far away from the headquarters of the Range Office may send their declaration either by hand or through telegram despatched on the same day.

ANNEXURE

Declaration of Stock etc. on Pre-Budget Day by a Manufacturer Working under Self Removal Procedure

1. Name of licensee.
2. L. 4 Licence No.
3. Commodity.

I/We hereby declare that the Serial Number of last gate pass(es) in form G.P. 1/G.P. 2 issued by me/us and the balance in hand of the excisable goods manufactured by me/us on (date)*.....at 6 P.M. was/were as under:

Name of goods with Tariff Item No.	Sl. No. of last G. P. 1/ G. P. 2	Closing Balance of excisable goods in stock in pe R. G. I.

Certified that the particulars given above are correct.

Place:.....

Date:.....

Signature of the assessee or his authorised agent

*One day prior to the presentation of annual/supplementary budget of the Union Government.

Handed over to Superintendent/Assistant Collector of Central Excise on..... at.....

[No. 1/72.

AJIT KUMAR ROY, Collector

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कलक्टर का कार्यालय, कानपुर

कानपुर 8 मार्च, 1972

एस० ओ० 1923.—1944 के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 233 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं निदेश देता हूं कि इस कलेक्टरेट में तैयार सभी उत्पाद शुल्क योग्य माल के निर्धारिती, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के अध्याय 7-क और भारत सरकार के अधिसूचना संख्या 171/69-के०उ० शु० दिनांक 21-6-69, 121/70-के०उ०शु० दिनांक 28-5-70, 179/71-के०उ०शु० दिनांक 23-9-71 और 195/71 के०उ०शु० दिनांक 12-11-71 में वर्णित स्वनिर्धारण पर निकासी कार्यविधि के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं, बजट दिवस के पहले दिन (जो 15 मार्च, 1972 है) 6 बजे शाम को शीघ्र ही बाद रेंज के प्रभारी अधिकारी के पास इस अधिसूचना से संलग्न फार्म में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे और उसकी एक प्रतिलिपि उचित अधिकारी को भी भेजेंगे ।

घोषणा में,

(क) निर्धारिती द्वारा उस दिन (अर्थात् 15 मार्च, 1972) शाम को 6 बजे तक जारी किए गए अन्तिम द्वार पत्र (जी०पी० 1, जी०पी० 2) का नम्बर,

(ख) उस दिन (अर्थात् 15 मार्च, 1972) 6 बजे शाम के समय निर्धारिती के पास बाकी स्टाक का इतिशेष,

अन्तर्विष्ट होना चाहिये ।

2. जहां पर निमाणिया रेंज मुख्यालय पर या उसके पास स्थित हैं उपरोक्त घोषणा निर्धारिती द्वारा रेंज कार्यालय में लिखित पावती प्राप्त करने पर दस्ती दी जायेगी। दूसरे निर्धारिती जो रेंज कार्यालय से दूर स्थित हैं अपनी घोषणा दस्ती अथवा उसी दिन भेजे गये तार द्वारा देंगे।

अनबन्ध

स्वनिर्धारण पर निकासी कार्यविधि के अन्तर्गत कार्य कर रहे विनिर्माता द्वारा बजट के पहले दिन स्टाक इत्यादि की घोषणा

1. अनुज्ञप्तिधारी का नाम

2. अनुज्ञप्ति 4 (एल० 4) की संख्या

3. वस्तु

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा——————— (तारीख) को 6 बजे शाम को फार्म जी०पी० 1, जी०पी० 2 में जारी किये गये द्वार पत्र (पत्रों) (गेट पासों) की क्रम संख्या और उत्पाद शुल्क योग्य निर्मित माल का इतिशेष निम्नलिखित था।

माल का नाम टैरिफ सूची में उनके क्रमांक के साथ	अन्तिम जी० पी० 1/जी०पी० 2 की क्रम संख्या	स्टाक में उत्पाद शुल्क योग्य माल का इतिशेष (गा०र० 1) (आर० जी० 1) के अनुसार

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं।

स्थान: निर्धारिती अथवा उसके अधिकृत

तारीख: एजेंट के हस्ताक्षर

भारत सरकार के वार्षिक/पूरक बजट के प्रस्तुत किये जाने के एक दिन पहले अधीक्षक/सहायक कलेक्टर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को .... तारीख को .... बजे दिया गया।

[संख्या 1/72-के० शु०]

अजित कुमार राय, समाहर्ता।

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE: BARODA

MANUFACTURED PRODUCTS

Baroda, the 1st April, 1972

(Amendment No. 1 to Notification No. 2|70)

S.O. 1924.—Baroda Collectorate Central Excise Notification No. 2/70, dated 20th/24th, November, 1970 may me amended as under:—

2. For the expression "Cotton yarn and Woollen yarn" appearing in Column 2 against Serial No. 1 and 2 of the table appended to the above cited Notification the expression, "Cotton yarn, Woollen yarn and Yarn falling under Item No. 18E of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944" shall be substituted.

[No. 1/72.]

M. R. RAMACHANDRAN
Collector.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टोरेट बड़ौदा

तैयार उत्पादन

बड़ौदा, 1 अप्रैल, 1972

(अधिसूचना संख्या 2/70 के लिए संशोधन सं-1)

एस० ओ० 1924.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कलेक्टोरेट बड़ौदा, अधिसूचना संख्या 2/70 दिनांक 20/24-11-1970 को नीचे के अनुसार संशोधित किया जाय।

उपरि-दत्त अधिसूचना में संलग्न सारणी के अनु० सं० 1 और 2 के सामने स्तम्भ 2 में उपस्थित कपास सूत तथा ऊनी सूत अभिव्यक्ति के लिये, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण (सोल्ट) नियमावली, 1944 की प्रथम अनुसूची की पद-संख्या 18ई के अधीन आने वाले कपास सूत, ऊनी सूत तथा सूत अभिव्यक्ति, प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं० 1/72]

ऐम० आर० रामचन्द्रन, समाहर्ता।

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 19th April 1972.

S.O. 1925.—The member of the Meropolitan Council of Delhi having elected on the 8th April. 1972, Sarvshri Radha Raman, Prem Singh and Brij Lal Goswami, as their representatives on the Delhi Development Authority, the Central Government in exercise of the power conferred by sub-section (f), read with clause (f), of sub-section (3) of section 3 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), makes the following further amendment in the late Ministry of Health Notification No. F.12-137/57-LSG, dated the 30th December, 1957, namely:—

In the said notification, in items No. 7, 8 and 8A for the entries "Shri Vijay Kumar Malhotra, Shri Shiv Charan Gupta and Shri Ram Babu Maheshwari" the following entries shall respectively be substituted.

"7. Shri Radha Raman.

8. Shri Prem Singh.

8A. Shri Brij Lal Goswami."

[No.5/2/69-UDI.]

New Delhi, the 26th May 1972

S.O. 1926.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (I), read with clause (g) of sub-section (3) of section 3 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) the Central Government hereby nominates Shri C. S. Gupte, Chief Planner, Town and Country Planning Organisation, as a member of the Delhi Development Authority in place of Shri B. G. Fernandes and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of

Health No. 12-173/57-LSG, dated the 30th December, 1957, namely:—

In the said notification, in item 10-A, for the entry "Shri B. G. Fernandes" the following entry shall be substituted, namely:—

"Shri C. S. Gupte."

[No. F.5-2/69-UDI.]

L. M. SUKHWANI, Under Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 मई, 1972

एस० ओ० 1926.—दिल्ली विकास अधिनियम 1957 (1957 का 61) की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (छ) के संग पढ़ी जाने वाली उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन के मुख्य आयोजक, श्री सी० एस० गुप्ते को श्री बी० जी० फरनान्डेस के स्थान पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है तथा भारत सरकार के भतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय के दिनांक 30, दिसम्बर, 1957 की अधिसूचना संख्या 12-173/57-एल० एस० जी० में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है ; अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की मद 10-क में "श्री बी० जी० फरनान्डेस" के इंदराज के स्थान पर निम्नलिखित इंदराज प्रतिस्थापित किया जायेगा, नामत :

"श्री सी एस० गुप्ते"

[सं० 5-2/69-यू० डी० I]

एल० एम० सुखवाणी, अवर सचिव ।

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Internal Trade)

New Delhi, the 12th May 1972

S.O. 1927.—In pursuance of sub-rule (2) of Rule 157 of the Trade and Merchandise Marks Rules, 1959, the Central Government hereby notifies the following alterations made in the Register of Trade Marks Agents in the address of the place of residence and qualifications of Shri V. Narayana Rao, a Registered Trade Mark Agent, namely:—

Qualifications.—B.Sc. (Hons), L.L.B., D.T.M: (Bom).

Residential Address.—Flat No. 77, Madhugiri Co-op. Housing Society Ltd., 408, Sion Trombay Road, Chembur Bombay-71 AS.

[No. F.29(9)-IT./TM/72.]

D. C. VAISH, Under Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(आंतरिक व्यापार विभाग)

नई दिल्ली, 12 मई 1972

का० आ० 1927:—व्यापार और वाणिज्य चिह्न नियम, 1959 के नियम 157 के उप-नियम (2) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रजिस्टर में श्री वी० नारायणराव, रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्ता, के निवास स्थान के पते और अर्हताओं में निम्नलिखित परिवर्तन अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

अर्हताएं :—बी०एस०सी (ऑनर्स) एल० एल० बी०, डी० टी० एम० (बौम)

निवास स्थान का पता: फ्लैट नं० 77, मधुगिरी, को०ओ०, हाउसिंग सोसाइटी लि०, 408, साइन ट्रोम्बे रोड, चैम्बूर, बम्बई-71 ए०एस० ।

[सं० फा० 29(9)-आई०टी०/टी०एम०/72

डी०सी० वैश, अवर सचिव ।

ORDER

New Delhi, the 5th May, 1972.

S.O. 1928./IDRA/6/72.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Industrial (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) read with rules 2, 4 and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints for a period of two years with effect from 10th July, 1971, S/Shri Chhatrapati Ambesh, A. K. A. Abdul Samad and Sadhu Ram to be the Members of the Development Council reconstituted by the order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 2582/IDRA/71, dated 10th July, 1971, for the schedule industries engaged in the manufacture of Leather and Leather Goods, and directs that the following amendment shall be made in the said order, namely:—

In the said, order, after entry No. 24 relating to Shri R. Thanjan, the following entries shall be inserted namely:—

25. Shri Chhatrapati Ambesh Member, Lok Sabha.
26. Shri A. K. A. Abdul Samad Member, Rajya Sabha.
27. Shri Sadhu Ram, Member, Lok Sabha.

[No. 31(17)/66-LI&PF.]

R. N. MISRA, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 मई, 1972

का० आ० 1928/आई० डी० आर० ए०/6/72:—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं विकास परिषदों (कार्यविधि) नियम, 1952 के नियम 2, 4 और 5 के साथ पढ़ते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 10 जुलाई, 1971 से दो वर्षों की अवधि तक सर्वश्री छत्रपति अम्बेष, ए०के०ए० अब्दुल समद तथा साधू राम को भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं०का०आ० 2582/आई०डी०आर०ए०/71 दिनांक 10-7-71 के द्वारा चमड़ा तथा चमड़े की वस्तुओं के निर्माणरत अनुसूचित उद्योगों की पुर्नगठित विकास परिषद का

सदस्य नियुक्त करती है और यह निदेश देती है कि उक्त आदेश में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :—

उक्त आदेश में, श्री आर थंजन से सम्बन्धित प्रविष्टि सं० 24 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां निविष्ट की जाएंगी, अर्थात् :—

25 श्री छत्रपति अम्बेश, सदस्य, लोकसभा ।

26 श्री ए० के० ए० अब्दुल समद, सदस्य, राज्यसभा ।

27 श्री साधूराम, सदस्य, लोकसभा ।

[सं० 31 (17)/66-एल० आई० एंड पी० एफ०]

आर० एन० मिश्र, अवर सचिव ।

(Indian Standards Institution)

New Delhi, the 9th May 1972

S.O. 1929.—In pursuance of sub-regulation (1) of regulation 5 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, as amended from time to time, and consequent upon publication of IS:3176-1971 Specification for anti-friction bearing type cop rollers for ring and speed frames (first revision), it is, hereby, notified that IS: 4042-1967 Specification for cop rollers for speed frames, details of which were published under notification number S.O. 2950 dated 6th August, 1967, in the Gazette of India, Part II, section 3—Sub-Section (ii) dated 26th August, 1967, has been cancelled, as its requirements have been covered in IS:3176-1971.

[No. CMD/13:7.]

S. K. SEN, Director General.

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 9 मई 1972

एस० ओ० 1929:—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 5 के उपविनियम (1) के अनुसार तथा IS : 3176–1971 रिंग और स्पीड फ्रेमों के लिए धर्षण-रोधी बेयरिंगनुमा ऊपरी रोलरों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) के प्रकाशित होने के फलस्वरूप अधिसूचित किया जाता है कि IS : 4042–1967 स्पीड फ्रेमों के ऊपरी रोलरों की विशिष्टि जिसके ब्योरे एस० ओ० 2950 दिनांक 16 अगस्त 1967 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र भाग 2 खण्ड 3 उपखण्ड (2) में दिनांक 26 अगस्त 1967 को प्रकाशित हुए थे, रद्द कर दी गई है, क्योंकि इसमें दी गई अपेक्षाएं IS : 3176–1971 में शामिल कर ली गई हैं।

[सं० सी० एम० डी०/13 : 7]

एस० के० सेन,

महानिदेशक ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 22nd April 1972

S.O. 1930.—In pursuance of section 111 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby publishes the report dated the 30th March, 1972 by the High Court of Judicature at Madras in Election Petition No. 9 of 1971.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT MADRAS

(Special Original Jurisdiction)
Election Petition No. 9 of 1971

C. R. Ramaswamy, "Ramakripa", 2/3, Kasthuri Ranga Iyengar Road, Madras-18—*Petitioner*

Vs.

1. Era Sezhian, S/o V. S. Rajagopalan, 13, Sarangapani Street, Madras-17.

2. The Chief Election Commissioner, Talkatora Road, New Delhi.

3. The Chief Electoral Officer, Govt. of Tamil Nadu, Fort St. George, Madras-9.

4. The Returning Officer, Kumbakonam, Parliamentary Constituency (District Collector, Thanjavur) at Thanjavur—*Respondents.*

Report of the High Court, Madras under Section 111 of the Representation of the People Act, 1951.

1. Thiru C. R. Ramaswamy, the above named petitioner, presented an Election Petition, No. 9 of 1971, in this Court, under Sections 84 and 100 of the Representation of the People Act, 1951 on 26th April, 1971, to direct recount of the ballot papers polled in the election to the Kumbakonam Parliamentary Constituency; to set aside the election of the first respondent to the House of the People from the Kumbakonam Parliamentary Constituency at the election held on 7th March, 1971 and to further declare the petitioner herein as duly elected to the House of the People from the Kumbakonam Parliamentary Constituency at the aforesaid Election held on 7th March, 1971, impleading therein, the said Era Eezhian, the Chief Election Commissioner, New Delhi, the Chief Electoral Officer, Government of Tamil Nadu and the Returning Officer, Kumbakonam Parliamentary Constituency as respondents;

2. The aforesaid petitioner, on 7th January, 1972, filed an application, A. No. 54 of 1972 into this court, impleading the aforesaid respondents as Respondents in the said application under Section 109(1) of the Representation of the People Act, 1951, Section 151 C.P.C. and order XIV, Rule 8 of the Rules of the High Court, Madras, Original Side, 1956, read with Rule 3 of the Rules of the Madras High Court, Election Petitions, 1957, for permitting the petitioner-applicant, to withdraw under Section 109(1) of the said Act, the said Election Petition No. 9 of 1971 and for directing the refund of the Security for costs deposited by the petitioner-applicant.

3. After publication in the Tamil Nadu Government Gazette dated 26th January, 1972, Part VI-Section 3, under Section 109(2) of the Act aforesaid, of the notice dated 11th January, 1972, fixing the 11th day of February, 1972 for the hearing of the application, the said application for withdrawal, A. No. 54 of 1972, along with the Election Petition No. 9 of 1971, came up for hearing on the 11th day of February, 1972 and on such hearing, this court has allowed the said application for withdrawal and dismissed the said Election Petition as withdrawn and directed publication of the notice of withdrawal in the Official Gazette of the Tamil Nadu State Government within one month from that date, and communication of the fact of such withdrawal to the Election Commission, in terms of Section 111 of the Act.

4. As required under Section 110(3)(b) of the Act, notice of withdrawal of the aforesaid Election Petition was published in the Tamil Nadu Government Gazette, Part VI, Section 3, dated 8th March, 1972.

5. Since after the grant of the Application for withdrawal, no person has come forward for being substituted as the petitioner, under Section 110(3)(c) of the Act, after the publication of the notice of withdrawal under Section 110(3) (b) of the Act, and as the time allowed under Section 110(3)(c) of the Act expired on 22nd March, 1972, the order of this court dated 11th February, 1972, granting withdrawal of the aforesaid Election Petition No. 9 of 1971 on the file of this Court and dismissing the same as withdrawn, has become final.

This report, in respect of the Election Petition No. 9 of 1971 on the file of this Court is made under Section 111 of the Act, for necessary publication in the Official Gazette by the Election Commission of India.

(Sd.)

Assistant Registrar, (Elections)
High Court, Madras.

[No. 82/TN(9)71)/72.]

New Delhi, the 30th May, 1972

S.O. 1931.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following amendments shall be made in its notification No. 434/WB/70/(3), dated the 19th August, 1970:—

In column 2 of the Table appended to the said notification for the entries against the parliamentary constituencies mentioned below, the following corresponding entries shall be substituted:—

TABLE

Name of the Parliamentary constituency.	Assistant Returning Officer.
1	2
4-Raiganj . .	Additional District Magistrate, West Dinajpur, Senior Deputy Collector, West Dinajpur, Sub-Divisional Executive Magistrates concerned and Magistrates who deal with revenue and administrative matters in the absence of the sub-Divisional Executive Magistrates concerned.
5-Balurghat. . . .	Additional District Magistrate West Dinajpur, Senior Deputy Collector, West Dinajpur, Sub-Divisional Executive Magistrates concerned and Magistrates who deal with revenue and administrative matters in the absence of the Sub-Divisional Executive Magistrates concerned.

The amendments made above will be effective, from the 24th February, 1972 in so far as the appointment of "Sub-Divisional Executive Magistrates concerned" as Assistant Returning Officers in respect of the constituencies the areas of which fall within the District of West Dinajpur is concerned.

[No. 434/WB/72(22).]

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 30 मई, 1972

एस० ओ० 1931.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि उसकी अधिसूचना सं० 434/प० ब०/70(3) तारीख 19 अगस्त, 1970, में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे :

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में, नीचे दी गई संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित तत्स्थानी प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी :—

सारणी

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
4—रायगंज	अपर जिला मजिस्ट्रेट, पश्चिमी दिनाजपुर, ज्येष्ठ उप-कलक्टर, पश्चिमी दिनाजपुर, सम्पृक्त उपखंड कार्यपालक मजिस्ट्रेट तथा वे मजिस्ट्रेट जो सम्पृक्त उपखंड कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं ।
5—बालुरघाट	अपर जिला मजिस्ट्रेट, पश्चिमी दिनाजपुर, ज्येष्ठ उप-कलक्टर, पश्चिमी दिनाजपुर, सम्पृक्त उपखंड कार्यपालक मजिस्ट्रेट तथा वे मजिस्ट्रेट जो सम्पृक्त उपखंड कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की अनपस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं ।

उपयुक्त किए गए संशोधन जहां तक, "सम्पृक्त उपखंड कार्यपालक मजिस्ट्रेटों" की, उन निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में जिनके क्षेत्र पश्चिम दिनाजपुर जिले के भीतर पड़ते हैं, सहायक रिटर्निंग आफिसरों के रूप में नियुक्ति का सम्बन्ध है, 24 फरवरी, 1972 से प्रभावी होंगे ।

[संख्या 434/प० ब०/72 (22)]

ORDERS

New Delhi, the 28th March 1972

S.O. 1932.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Chandra Prakash Atrey, S/o Shri Jhandoo Singh, 1120, Baghpat Gate, Meerut, District

Meerut, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the House of the People from 81-Baghpat Parliamentary Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Chandra Prakash Atrey to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-HP/81/71(7).]

आदेश

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1972

एस० ओ० 1932.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1971 में हुए 81, बागपत संसदीय के लिए लोकसभा निर्वाचन के लिए निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री चन्द्रप्रकाश आत्रेय सपुत्र श्री झंडूसिंह 1120, बागपत गेट, मेरठ शहर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, अपनी असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री चन्द्रप्रकाश आत्रेय को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-लो०स०/81/71(7)]

New Delhi, the 3rd April 1972

S.O. 1933.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jagdish, S/o Shri Ghasi Ram, Village Rahazadka, Post Office Pilona district Meerut, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the House of the People from 80-Meerut Parliamentary Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jagdish to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-HP/80/71(9).]

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1972

एस० ओ० 1933.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1971 में हुए उत्तर प्रदेश के लिए लोक सभा के निर्वाचन के लिए 80, मेरठ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जगदीश सपुत्र श्री घासी राम, ग्राम बहजादका डा० पिलौना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, अपनी असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जगदीश को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-लो०स०/80/71(9)]

New Delhi, the 17th April 1972

S.O. 1934.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Deep Narain S/o Shri Gulab Yadav, 206-Rajapur, Allahabad, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the House of the People from 55-Phulpur Parliamentary Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Deep Narain to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-HP/55/71(11).]

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1972

एस० ओ० 1934.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि लोकसभा के लिए निर्वाचन के लिए 55, फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री दीप नारायण सुपुत्र श्री गुलाब यादव, 206 राजापुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

2. और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है; तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

3. अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री दीप नारायण को संसद् के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-लो० स०/55/71(II)]

S.O. 1935.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Badri Vishal, S/o Shri Thakur Prasad Singh, Village Kanihar, Post Office Sarai Inayat, District Allahabad, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the House of the People from 55-Phulpur Parliamentary Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Badri Vishal to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-HP/55/71(12).]

एस० ओ० 1935—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि लोकसभा के लिए निर्वाचन के लिए 55 फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बद्री विशाल सुपुत्र श्री ठाकुर प्रसाद सिंह, ग्राम कनिहार, पो० आ० सराय इनायत, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है; तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं हैं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बद्री विशाल को संसद् के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-लो०स०/55/71(12)]

New Delhi, the 18th April 1972

S.O. 1936.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shafat S/o Shri Jainul, Paharpur, House No. 71A, Azamgarh, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the House of the People from 45-Azamgarh constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shafat to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No UP-HP/45/71(14).]

नई दिल्ली 18 अप्रैल, 1972

एस० ओ० 1936—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि लोकसभा के लिए 45-आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शफात सुपुत्र जैनुल पहाड़पुर, म०न० 71अ, आजमगढ़ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है; और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10 क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शफात को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-लो०स०/45/71(14)]

S.O. 1937.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Natthoo Chaudhari, S/o Shri Mahadeo, 138 Gopaahsa, (Bara ka Purwa) Post Office Kanaili, Allahabad, Uttar Pradesh a contesting candidate for election to the House of the People from Chail Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Natthoo Chaudhari to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-HP/57/71(15).]

एस० ओ० 1937.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि लोक सभा के लिए निर्वाचन के लिए 57 चायल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नत्थू चोधरी सपुत्र श्री महादेव, 138, गोपसहसा (बारा का पुरवा), डा० कनैली, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

2. और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचनाएं दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है; तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

3. अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10—क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नत्थू चौधरी को संसद् के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०—लो० स०/57/71(15)]

S.O. 1938.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Kishan, S/o Shri Gaya Deen, 24, Sobhatia Bagh, Allahabad Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the House of the People from Chail constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Kishan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-HP/57/71(16).]

एस० ओ० 1938.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया हैकि लोक सभा के लिए निर्वाचन के लिए 57 चायल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम किशन सपुत्र श्रीग यादीन, 24 सोबहतिया बाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

2. और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई करण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है; तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

3. अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10—क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम किशन को संसद् के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०—लो० स०/57/71(16)]

S.O. 1939.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri S. Ramiah, 125/1, Vandiperiyar P.O. Kottayam District (Kerala State) a contesting candidate for mid-term election to the Kerala Legislative Assembly from 79-Peermade (SC) constituency, held in 1970 has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the people Act, 1951, and the Rules made thereunder.

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri S. Ramiah to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. KL-LA/79/70.]

एस० ओ० 1939.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1970 में हुए केरल विधान सभा के लिए मध्यावधि निर्वाचन के लिए 79-पीरमोड (अ० ना०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री एस० रमैय्या, 125/1 वंडीपेरीयार, पो० जिला कोटटायाम (केरल राज्य), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचनाएं दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम को धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री एस० रमैय्या को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की ता० से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० केरल-वि० स०/79/70]

S.O. 1940.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sundaram Murugandy, Panchayat President, Vandiperiyar P.O., Kottawam District (Kerela), a contesting candidate for election to the Kerala Legislative Assembly from 79-Peermade constituency, held in 1970 has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the people Act, 1951, and the Rules made thereunder.

And whreas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure; and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sundaram Murugandy to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. KL-LA/79/70.]

एस०ओ० 1940.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1970 में हुए केरल विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 79-पीरमाड़े निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्रीसुंदरम मुरुगोडे, प्रधान पंचायत, पो० वेन्डीपेरीयार जिला कोट्टायाम (केरल) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है ,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सून्दरम मुरुगाडे को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० केरल-वि० स०/79/70]

New Delhi, the 24th April, 1972

S.O. 1941.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri P. Krishna Pillai, Panickerodathu Kizhakkathil, Kurathicadu, Thekkekara, Mavelikara, District Alleppey, Kerala State, a contesting candidate for mid-term election to the Kerala Legislative Assembly held in 1970 from 103-Mavelikara constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

2. And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri P. Krishna Pillai to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative 9Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order

[No. KL-LA/103/70.]

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1972

एस० ओ० 1941.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1970 में हुए केरल विधान सभा के लिए मध्यावधि निर्वाचन के लिए 103-मावेलीकारा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पी० कृष्णा पिल्लई, पानीचेरोदाधू कोझाकथिल, ठेकेदारा, मावेलीकारा, जिला अल्लेपपी, केरल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा पद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचनाएं दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण या स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है ,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री कृष्ण पिल्लई को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० केरल-वि० स०/103/70]

New Delhi, the 26th April, 1972.

S.O. 1942.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri K. R. Bhaskaran Pillai, Venu Nivas, P.O. Palemadu, (*via*) Edakkara, Kerala State, a contesting candidate for bye-election to the Kerala Legislative Assembly from 34-Nilambur constituency, held in 1970 has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after the due notice, has not given any reason or explanation for the failure; and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri K. R. Bhaskaran Pillai, to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. KL-LA/34/70.]

By Order,

A. N. SEN, Secretary.

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1972

एस०ओ० 1942—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो, गया है कि 1970 में हुए केरल विधान सभा के लिए उप-निर्वाचन के लिए 34-नीलम्बूर निर्वाचन क्षेत्र से लड़ने वाले उम्मीदवार श्री के० आर० भस्करण पिल्लई, वेनु निवास पो० आ० पालेमाडु (वाया) ऐडाक्कारा, केरल राज्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री के० आर० भास्करण पिल्लई को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा

अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश को तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० केरल वि० स०/34/70]

आदेश से,

ए० एन० सेन, सचिव ।

New Delhi, the 28th April 1972

S.O. 1943.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following further amendments shall be made in its Notification No. 434/GJ/71, dated the 2nd December, 1971, namely:—

In column 2 of the Table appended to the said notification for the existing entries numbered 4, 6 and 8 against item 3-Rajkot the entires, Prant Officer, Morvi Sub-Division, Morvi, First Additional Special Land Acquisition Officer, Rajkot and Deputy Controller of Civil Defence, Rajkot, respectively shall be substituted.

[No. 434/GJ/72.]

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1972

एस० ओ० 1943.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि उसकी अधिसूचना सं० 434 गुज०/71, तारीख 2 दिसम्बर, 1971 में निम्नलिखित संशोधन और किए जाएंगे, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में, मद 3—राजकोट के सामने, विद्यमान प्रविष्टि सं० 4, 6 और 8 के स्थान पर, क्रमशः प्रान्त आफिसर, मौरवी उपखंड, मोरवी ; प्रथम अपर विशेष भूमि अर्जन, आफिसर, राजकोट ; और उप नियन्त्रक, सिविल रक्षा राजकोट, प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ।

[सं० 434/गुज०/72]

ORDERS

New Delhi the 18th April, 1972

S.O. 1944.—Whereas the Election Commission is satisfied that Smt. Vidyudvalli Sastry Puranam, resident of 23/375, Fort Road, Machilipatnam, a contesting candidate for general election to the House of the People from 14-Machilipatnam parliamentary constituency, has failed to lodge an account of her election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rule made thereunder;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that she has no good reason or justification for the failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Smt. Vidyudvalli Sastry Puranam to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. AP-HP/14/71.]

आदेश

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1972

एस० ओ० 1944.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन के लिए 14-मछली-पटनम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्रीमती विद्युदवल्ली शास्त्री पुरानम, निवासी 23/375, फोर्ट रोड, मछलीपटनम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उन्हें उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्रीमती विद्युदवल्ली शास्त्री पुरानम को संसद के किसी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालविधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० आ० प्र० लो० स०/14/71]

New Delhi, the 26th April, 1972

S.O. 1945.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mohanbhai Jesanghai Vasava, Pitruchhaya Building, Near Navapura Wadi Rangmahal, Baroda, Gujarat, a contesting candidate for election to the House of the People from 20-Dabhoi constituency, held in March, 1971, has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mohanbhai Jesangbhai Vasava to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Asembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ-HP/20/71]

By Order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secretary.

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1972

एस०ओ० 1945.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1971 में हुए लोक सभा के लिए निर्वाचन के लिए 20—डभोई निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मोहन भाई जेसंगीभाई वसावा, पितृछाया बिल्डिंग, समीप नवापुरा वाडी, रंगमहल, बड़ौदा, गुजरात, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,

1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहें है ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचनाएं दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है; और आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मोहनभाई जेसंगीभाई पसावा को ससंद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[स० गुज-लो० स०/20/71]

आदेश से,

वी० नागपुरमण्यन, सचिव ।

CORRIGENDUM

New Delhi, the 25th March 1972

S.O. 1946.—In the Commission's Order No. KL-LA/100/70, dated the 23rd December, 1972, published at pages 680 and 681 in the Gazette of India, Part II, Section 3(ii), dated the 5th February, 1972, for the words "said Act, the Election Commission hereby declares the sen as", occurring in line 3 and 4 of para 3, substitute the words 'said Shri P. J. David to be disqualified for being chosen as'.

[No. KL-LA/100/70.]

By Order.

I. K. K. MENON, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 30th March 1972

S.O. 1947.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri Virendra D. Vyas, Director in the Ministry of Information and Broadcasting as Chairman, Board of Film Censors with effect from the 11th day of February, 1972.

[No. F.2/64/71-FC.]

By order and in the name of the President.

C. B. GIRIDHAR, Dy. Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1972

एस०ओ० 1947.—चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में निदेशक श्री वीरेन्द्र देव व्यास को 11 फरवरी, 1972 से केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करती है ।

[फाइल संख्या 2/64/71-एफ० सी०]

राष्ट्रपति के नाम तथा उनके आदेशानुसार ।

सी० बी० गिरिधर, उप सचिव ।

New Delhi, the 5th April 1972

S.O. 1948.—The Central Government hereby accepts the resignation of Shri Prabodh Raval from membership of the Central Board of Film Censors, Bombay with effect from 17th March, 1972.

[No. 11/5/71-FC.]

By Order and in the name of the President.

S. N. MITAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1972

एस० ओ० 1948.—केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 17 मार्च, 1972 से श्री प्रबोध रावल का केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, बम्बई की सदस्यता से त्यागपत्र स्वीकार करती है ।

[संख्या 11/5/71-एफ० (सी)]

राष्ट्रपति के नाम में तथा उनके आदेशानुसार

एस० एन० मित्तल, अवर सचिव ।

New Delhi, the 10th April 1972

S.O. 1949.—In exercise of the powers conferred by section 5(1) of the Cinematograph Act, 1952 and sub-rule (3) of rule 3 read with sub-rule 2 of rule 9 of the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958, the Central Government hereby reappoints the following persons after consultation with the Central Board of Film Censors as members of the Advisory Panel of the said Board at Bombay with effect from 1st April, 1972 upto June 30, 1972:

1. Shri Kamaleshwar
2. Smt. Dinabai K. Dubash.
3. Prof. K. G. Aggarwal.
4. Prof. (Smt.) Vijaya Rajadhyaksha
5. Shri S. S. Rege
6. Shri D. G. Nadkarni
7. Prof. Murli Thakur
8. Shri G. K. Dutia
9. Dr. (Smt.) Charusheela B. Gupta
10. Smt. Kamala Tilak
11. Smt. Padma K. Desai
12. Shri S. D. Shah
13. Dr. (Miss) Labuben S. Soneji.
14. Smt. Nalini S. Sukthankar
15. Smt. Manibon Desai.
16. Smt. Laxmi Wahi
17. Smt. T. V. Dehejia
18. Shri Ganga Ram Joshi
19. Shri Rama Narang
20. Shri U. A. Thadani
21. Shri R. K. Soni.
22. Shri S. E. Hassnain
23. Smt. Kamala Dua
24. Shri Talakshi Shah
25. Shri Rajnarain Singh
26. Smt. R. S. Boga
27. Shri M. N. Siddiqi
28. Shri A. K. Banerjee
29. Smt. Indira Dhanraj Girji.
30. Shri Rasik J. Shah
31. Smt. Mrinalini Choksi
32. Smt. Lalita N. Bapat
33. Smt. S. Gulrajani

[No. F. 11/3/72-FC.]

S. N. MITAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1972

एस०ओ० 1949.—चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5(1) और चलचित्र (सेंसर) नियमावली, 1958 के नियम 9 के उप-नियम (2) के साथ पठित नियम 8 के उप-नियम (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड से परामर्श करके एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को पहली अप्रैल, 1972 से 30 जून, 1972 तक, उक्त बोर्ड के बम्बई सलाहकार पैनल का फिर से सदस्य नियुक्त किया है :—

1. श्री कमलेश्वर
2. श्रीमती दीनाबाई के० दुबाष
3. प्रो० के०जी० अग्रवाल
4. प्रो० (श्रीमती) विजया राजाध्यक्ष
5. श्री एस० एस० रेगे
6. श्री डी० जी० नादकर्णी
7. प्रो० मुरली ठाकुर
8. श्री जी० के० दुतिया
9. डा० (श्रीमती) चारुशीला बी० गुप्त
10. श्रीमती कमला तिलक
11. श्रीमती पदमा के० देसाई
12. श्री एस०डी० शाह
13. डा० (कुमारी) लवुबेन एस० सोनेजी
14. श्रीमती नलिनी एस० सुखथंकर
15. श्रीमती मणिबेन देसाई
16. श्रीमती लक्ष्मी वाही
17. श्रीमती टी०बी० देहेजिया
18. श्री गंगाराम जोशी
19. श्री राम नारंग
20. श्री यू०ए० थदानी
21. श्री आर०के० सोनी
22. श्री एस०ई० हुसनैन
23. श्रीमती कमला दुआ
24. श्री तलाक्षी शाह
25. श्री राजनारायण सिंह
26. श्रीमती आर०एस० बोगा
27. श्री एम०एन० सिद्दीकी
28. श्री ए०के० बनर्जी
29. श्रीमती इन्दिरा धनराज गिरजी
30. श्री रसिक जे० शाह
31. श्रीमती मृणालिनी चोक्सी
32. श्रीमती ललिता एन० बापट
33. श्रीमती एस० गुलरजानी

[सं० फा० 11/3/72—एफ०सी०]

S.O. 1950.—In exercise of the powers conferred by Section 5(1) of the Cinematograph Act, 1952, and sub-rule (3) of rule 8 read with sub-rule (2) of rule 9 of the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958, the Central Government hereby re-appoints the following persons after consultation with the Central Board of Film Censors, as members of the Advisory Panel of the said Board at Madras with effect from 1st April, 1972 upto 30th June, 1972:—

1. Shri T. Neelakanthan.
2. Smt. Soundra Kailasam
3. Shri Pakala Suryanarayana Rao
4. Shri Mohd. Yousuf Kokan
5. Shri M. Govindan
6. Smt. C. L. Meenakshi Amma
7. Shri P. V. Chalapatheswara Rao
8. Prof. M. Mariappa Bhat
9. Smt. Marry Clubwala Jadav
10. Shri P. K. Ramalingam
11. Shri G. Varadappa
12. Smt. R. Suvarna
13. Smt. Amu Swaminathan
14. Smt. P. V. Bhagirathi
15. Smt. Bertha Lobo
16. Smt. Indira D. Kothari
17. Smt. Malati Chendur
18. Shri C. R. Sharma
19. Smt. Raji Rangachari
20. Smt. Padmini Achutha Menon
21. Smt. N. S. Mani
22. Dr. S. Vijayalakshmi
23. Smt. Leela Parthasarathi
24. Smt. Sarojini Varadappan.
25. Kumari P. Shanta Bai
26. Smt. M. Leelavathi
27. Shri P. S. Srinivasa
28. Smt. Rohini Krishnachandra
29. Dr. (Miss) C. M. Leelavati
30. Smt. Hemlata Anjaneyulu
31. Smt. Sara Syed Yusuff.

[No. F. 11/4/72-FC.]

एस०ओ० 1950.—चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5(1) और चलचित्र (सेंसर) नियमावली, 1958 के नियम 9 के उप-नियम (2) के साथ पठित नियम 8 के उप नियम (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने एतद्द्वारा केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के परामर्श करने के बाद, निम्नलिखित व्यक्तियों को 1 अप्रैल, 1972 से 30 जून, 1972 तक, उक्त बोर्ड के मद्रास सलाहकार पैनल का सदस्य फिर से नियुक्त किया है।

1. श्री टी० नीलकन्तन
2. श्रीमती सोन्द्रा केलासम
3. श्री पकाला सूर्यनारायण राव
4. श्री मोहम्मद यूसुफ कोकण
5. श्री एम ० गोविन्दन
6. श्रीमती सी०एल० मीनाक्षी अम्मा
7. श्री पी० वी० चलपतेश्वर राव
8. प्रो० एम० मरिअप्पा भट्ट
9. श्रीमती मेरी क्लबवाला जादव
10. श्री पी० के० रामलिंगम
11. श्री जी० वरदप्पा
12. श्रीमती आर० सुवर्ण
13. श्रीमती अमू स्वामिनाथन
14. श्रीमती पी०बी० भागीरथी
15. श्रीमती बर्था लोबो
16. श्रीमती इंदिरा डी० कोठारी
17. श्रीमती मालती चेन्दूर
18. श्री सी० आर० शर्मा

19. श्रीमती राजी रंगाचारी
20. श्रीमती पद्मिनी अचुता मेनन
21. श्रीमती एन० एस० मणि
22. डा० एस० विजयालक्ष्मी
23. श्रीमती लीला पार्थसारथी
24. श्रीमती सरोजिनी वरदप्पन
25. कुमारी पी० शान्ता बाई
26. श्रीमती एम० लीलावती
27. श्री पी० एस० श्रीनिवास
28. श्रीमती रोहिणी कृष्णचन्द्र
29. डा० (कुमारी) सी० एम० लीलावती
30. श्रीमती हेमलता अर्जनेयुलु
31. श्रीमती सारा सैयद युसुफ

[संख्या एफ० 11/4/72-एफ०सी०]

S.O. 1951.—In exercise of the powers conferred by Section 5(1) of the Cinematograph Act, 1952, and sub-rule (3) of rule 8 read with sub-rule (2) of rule 9 of the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958, the Central Government hereby re-appoints the following persons after consultation with the Central Board of Film Censors, as members of the Advisory Panel of the said Board at Calcutta with effect from April 1st, 1972 upto June 30, 1972:—

1. Smt. Uma Sahanabis
2. Shri Sailen Mookerji
3. Smt. Kajal Sen Gupta
4. Smt. Abu Sayeed Ayyub
5. Smt. Shaibya Dutt
6. Smt. Asha Purna Debi
7. Smt. Rita Ray
8. Shri Sujit K. Chakrabarti
9. Shri R. P. Gupta
10. Shri Anant Mahapatra
11. Shri Saumyendra Nath Tagore
12. Shri Kshitish Roy
13. Smt. Usha Khan
14. Shri Ranen Ayan Dutta
15. Smt. Arati Tagore
16. Smt. Jayasree Sen.

[No. F. 11/5/72-FC.]

एस० ओ० 1951.—चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5 (1) और चलचित्र (सेंसर) नियमावली, 1958 के नियम 9 के उप-नियम (2) के साथ पठित नियम 8 के उपनियम (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने एतद्द्वारा केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड से परामर्श करने के बाद निम्नलिखित व्यक्तियों को 1 अप्रैल, 1972 से 30 जून, 1972 तक उक्त बोर्ड के कलकत्ता सलाहकार पैनल का फिर से सदस्य नियुक्त किया है : —

1. श्रीमती उमा सहानवीस
2. श्री सेलन मुखर्जी
3. श्रीमती काजल सेनगुप्त
4. श्रीमती अबू सईद अय्यूब
5. श्रीमती शैव्या दत्त
6. श्रीमती आशा पूर्णा देवी
7. श्रीमती रीता रे
8. श्री सुजीत के० चक्रवर्ती
9. श्री आर० पी० गुप्त
10. श्री अनन्त महापात्रा
11. श्री सोमयेन्द्र नाथ टैगोर
12. श्री क्षितिश राय
13. श्रीमती ऊषा खान
14. श्री रानेन अयन दत्त
15. श्रीमती आरती टैगोर
16. श्रीमती जयश्री सेन

[संख्या फाइल 11/5/72-एफ० सी०]

S.O. 1952.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 3 of the Cinematograph Act, 1952, the Central Government hereby re-appoints the following persons as members of the Central Board of Film Censors with effect from 1st April, 1972 upto 30th June, 1972:—

S. No.	Name
1.	Shri B. R. Agarwal
2.	Shri V. R. Mohan
3.	Shri A. L. Srinivasan
4.	Shri B. R. Chopra
5.	Shri B. N. Sircar
6.	Smt. Veena Duggal
7.	Smt. M. Nasrullah
8.	Smt. Surrinder Gupta.

[No. F. 11/6/72-FC.]

S. N. MITAL, Under Secy.

एस० ओ० 1952.—चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को 1 अप्रैल, 1972 से 30 जून, 1972 तक, केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड का फिर से सदस्य नियुक्त किया है :—

क्रम संख्या	नाम
1.	श्री बी० आर० अग्रवाल
2.	श्री वी० आर० मोहन
3.	श्री ए० एल० श्रीनिवासन
4.	श्री बी० आर० चोपड़ा
5.	श्री बी० एन० सरकार
6.	श्रीमती वीना दुग्गल
7.	श्रीमती एम० नस्रुल्लाह
8.	श्रीमती सुरेन्द्र गुप्त

[संख्या फा० 11-6-72-एफ०सी ०]

एस० एन० मित्तल, अवर सचिव ।

ORDER

New Delhi, the 28th April, 1972

S. O. 1953.—In pursuance of the directions issued under the provisions of each of the enactments specified in the First Schedule annexed hereto, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the film specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto in Gujarati to be of the description specified against it in column 6 of the said Second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

(1) Sub-Section 4 of the Section 12 and Section 16 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act XXXVII of 1952).

(2) Sub-Section (3) of Section 5 and Section 9 of the Bombay Cinemas (Regulation) Act, 1953 ((Bombay Act XVII of 1953).

(3) Sub-Section (4) of Section 5 and Section 9 of the Saurashtra Cinemas (Regulation) Act, 1953 (Saurashtra Act XVII of 1953).

THE SECOND SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
(1)	Mahitichitra No. 148	298·70 M	Director of Information, Government of Gujarat, Ahmedabad.		Film dealing with news and current events (For release in Gujarat Circuit only).

[No. 28/1/72-F(P) App. 1661]

K. K. KHAN, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1972

एस० ओ० 1953.—इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा, इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके गुजराती भाषा के रूपान्तरों सहित जिस का विवरण उसके सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है :—

प्रथम अनुसूची

(1) चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37वां केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 12 की उपधारा (4) तथा धारा 16 ।

(2) बम्बई सिनेमा (विनियम) अधिनियम 1953 (1953 का 17वां बम्बई अधिनियम) की धारा 5 की उपधारा (3) तथा धारा 9 ।

(3) सौराष्ट्र सिनेमा (विनियम) अधिनियम 1953 (1953 का 17 वां सौराष्ट्र अधिनियम) की धारा 5 की उपधारा (4) तथा धारा 9 ।

द्वितीय अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धि फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाक्युमैन्ट्री फिल्म है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	महितिचित्र संख्या 148	298·70 मीटर	सूचना निदेशक, अहमदाबाद ।	गुजरात सरकार,	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल गुजरात सर्किट के लिये)

[संख्या फ० 28/1/72–एफ० पी० परिशिष्ट 1661]

क० क० खान, अवर सचिव ।

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 7th April 1972

S.O. 1954.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Associated Commerce and Industries (India) Private Limited, 12, Netaji Subhas Road, Calcutta-1 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1970.

[No. S.35018/71/71-PF.II(i).]

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

श्रम और रोजगार विभाग

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1972

का० आ० 1954—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एसोसिएटिड कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, 12, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता—1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1970 की दिसम्बर के 31 वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस—35018(71)/71—पी० एफ० 2(i)]

S.O. 1955. In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby, specifies, with effect from the thirty-first day of December, 1970, the establishment known as Messrs Associated Commerce and Industries (India) Private Limited, 12, Netaji Subhas Road, Calcutta-1 for the purposes of the said proviso.

[No. S.35018/71/71-PF.II(ii).]

का० आ० 1955—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में, आवश्यक जांच करने के पश्चात् 31 दिसम्बर, 1970 से एसोसिएटिड कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, 12—नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता—1 नामक स्थापन को एतद्द्वारा उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस—35018(71)/71—पी० एफ० 2(ii)]

S.O. 1956.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as The Industrial Conduits Private Limited, 15, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-1, including its Factory at 40, Regent Grove, Calcutta-40, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of March, 1971.

[No. S.35018(63)/71-PFII(i).]

का० आ० 1956—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि दि इंडस्ट्रियल कन्ड्इस प्राइवेट लिमिटड, 15 गनेश चन्द्रा एवन्यू, कलकत्ता तथा इस का कारखाना जो 40—रोजेंट ग्रोव, कलकत्ता-40 पर है, नामक स्थापन से सम्बद्ध क नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है

यह अधिसूचना 197 के मार्च के 31 वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35018 (63)/71—पी० एफ० 2(i)]

S.O. 1957.—In exercise of the powers conferred by first proviso to Section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 31st March, 1971, the establishment known as The Industrial Conduits Private Limited, 15, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-1, including its Factory at 40, Regent Grove, Calcutta-40 for the purposes of the said proviso.

[No. S.35018(63)/71-PF(II)(ii).]

का० आ० 1957—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 31 मार्च, 1971 से दि इण्डस्ट्रियल कण्डयूट प्रा० लि० 15 गनेश चन्द्रा एवेन्यू, कलकत्ता-1 तथा इसका 40-रैजीमेंट ग्रोव, कलकत्ता-40 का कारखाना नामक स्थापन को एतद्द्वारा उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

(सं० एस०-35017(63)/71—पी०एफ० 2(ii)]

S.O. 1958.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rolex Manufacturer and Engineers, Bombay-13 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of October, 1970.

[No. S-35017/53/71-PF.II(i).]

का० आ० 1958—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रोलैक्स मैन्यूफैक्चर्स एण्ड इंजीनियर्स, मुम्बई—13 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1970 के अक्तूबर के 31 वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस—35017(53)/71पी० एफ० 2 (i)]

S.O. 1959.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirty-first day of October, 1970 the establishment known as Messrs Rolex Manufacturers and Engineering, Bombay-13, for the purposes of the said proviso.

[No. S-35017/53/71-PF.II(ii).]

का० आ० 1959—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 31 अक्तूबर, 1970 से रोलैक्स मैन्यूफैक्चरर्स एण्ड इंजीनियरिंग, मुम्बई—13 नामक स्थापन को एतद्द्वारा उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस—35017(53)/71-पी० एफ० 2(ii)]

S.O. 1960.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Hindustan Sheet Metal Works, 1076, Dr. E. Moses Road, Warli, Bombay-18 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of September, 1970.

[No. S.35017/62-71-PF.II(i)]

का० आ० 1960—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हिन्दुस्तान शीट मैटल वर्क्स, 1076, डा० ई० मौसिस रोड, वर्ली, बम्बई-18 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1970 के सितम्बर के 30वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस—35017(62)/71-पी०एफ2(i)]

S.O. 1961.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies, with effect from the 30th September 1970, the establishment known as Messrs Hindustan Sheet Metal Works, 1076, Dr. E. Moses Road Warli, Bombay-18, for the purposes of the said proviso.

[No. S-35017/62/71-PF.II(ii).]

का० आ० 1961—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 30 सितम्बर, 1970 से हिन्दुस्तान शीट मैटल वर्क्स, 1076, डा० ई० मोसिस रोड, वर्ली, बम्बई 18 नामक स्थापन को एतद्द्वारा उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस-35017(62)/71-पी०एफ2(ii)]

S.O. 1962.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kriscast, F-5, Industrial Estate, Ambattur, Madras-58, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1971.

[No. S.35019(150)/71-PF.II(i).]

का० आ० 1962—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स क्रिसकास्ट, एफ-5 इण्डस्ट्रियल एस्टेट, अम्बाटूर, मद्रास-58 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1971 के अक्तूबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35019(150)/71-पी०एफ०(i)]

S.O. 1963.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies, with effect from the 1st day of October, 1971, the establishment known as Messrs Kriscast, F. 5, Industrial Estate, Ambattur, Madras-58, for the purposes of the said proviso.

[No. S-35019(150)/71-PF.II(ii).]

का० आ० 1963.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अक्तूबर, 1971 से क्रिसकास्ट, एफ 5, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, अम्बाटूर, मद्रास 58-नामक स्थापन को एतद्द्वारा उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस-35019(150)/71-पी० एफ० 2(ii)]

S.O. 1964.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 1st day of August, 1971, the establishment known as Messrs Jagan Nath and Company, Ram Nagar, Jullundur Cantonment for the purposes of the said proviso.

[No. S.35019(134)/71-PF.II(ii).]

का० आ० 1964.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952(1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अगस्त, 1971 से मैसर्स जगन नाथ एण्ड कम्पनी, राम नगर, जलन्धर कंटोनमेंट नामक स्थापन को एतद्द्वारा उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[(सं० एस-35019(134)/71-पी०एफ० 2(ii)]

S.O. 1965.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies, with effect from the 1st August, 1971, the establishment known as Messrs Ravi Udog, Yantrapur Post Office, Harihar (Mysore State) for the purposes of the said proviso.

[No. S.35019/136/71-PF.II(ii).]

का० आ० 1965.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् पहली अगस्त, 1971 से मैसर्स रवि उद्योग, यन्त्रापुर पोस्ट आफिस, हरिहर (मैसूर राज्य) नामक स्थापन को एतद्द्वारा उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस०35019(136)/71-भ०नि० 2( )]

S.O. 1966.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Narbod Constructions Private Limited No. 1, Poonamallee High Road, Madras-3, and its branch office at No. 74, Gulosin Flat, Jamshedpur-3 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1971.

[No. S.35019/149/71-PF.II)1).]

का० आ० 1966.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स नारबोद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड नं० 1, पूनामाली हाई रोड, मद्रास-3 तथा इसका नं० 74, गुलोसिन फ्लैट, जमशेदपुर-3 का कार्यालय भी नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1971 के अक्तूबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस 35019(149)/71-पी०एफ० 2(i)]

S.O. 1967.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 1st October, 1971, the establishment known as Messrs Narbod Constructions Private Limited No. 1 Poonamallee High Road, Madras-3 including its branch office at No. 74, Gulosin Flat, Jamshedpur-3 for the purposes of the said proviso.

[No. S.35019/149/71-PF.II(ii).]

का० आ० 1967.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अक्तूबर, 1971 से नारबोद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, नं० 1, पूनामाली हाई रोड, मद्रास-3 तथा इसका नं० 74, गुलोसिन फ्लैट्स जमशेदपुर-3 का कार्यालय भी नामक स्थापन को एतद्द्वारा उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस० 35019(149)/71—पी०एफ० 2(ii)]

S.O. 1968.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Joy Engineering Enterprises IC/30-B, Nehru Ground, Faridabad have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1971.

[No. S.35019/152/71-PF. II(i).]

का० आ० 1968—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जौय इंजीनियरिंग एण्टरप्राइसस, I सी/30/बी, नेहरू ग्राउण्ड, फरीदाबाद नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1971 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(152)/71-पी०एफ० 2(i)]

S.O. 1969.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies, with effect from the 1st April, 1971, the establishment known as Messrs Joy Engineering Enterprises, IC/30-B Nehru Ground, Faridabad for the purposes of the said proviso.

[No. S.35019/152/71-PF. II(ii).]

का० आ० 1969.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अप्रैल, 1971 से जौय इंजीनियरिंग एण्टरप्राइसस, आई सी।30—बी, नेहरू ग्राउण्ड, फरीदाबाद नामक स्थापन को एतद्द्वारा उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस-35019(152)।71-पी०एफ० 2(ii)]

S.O. 1970.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Andhra Oil and Cake Products Limited, Dwarakanagar, Visakhapatnam including its branches at 1&3 Brabourne Road Calcutta and 8, Chinnanaya Karn, St. Madras-1 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of he powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of December, 1970.

[No. S.35019/161/71-PF. II(i).]

का० आ० 1970—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आंध्र आयल एण्ड केक प्रोडक्ट्स लि० द्वारकानगर, विशाखापत्तनम तथा इसकी शाखाएं 1—3 ब्राबोर्न रोड, कलकत्ता और 8—चिनानाया कर्न, एसटी मद्रास—1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1970 के दिसम्बर, के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(161)/71—पी०एफ० 2(i)]

S.O. 1971.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies, with effect from the 1st December, 1970 the establishment known as Messrs Andhra Oil and Cake Products Limited, Dwarakanagar, Visakhapatnam including its branches at 1&3 Brabourne Road, Calcutta and 8, Chinnanaya Karn St. Madras-1 for the purposes of the said proviso.

[No. S.35019/161/71-PF. II(ii).]

का०आ० 1971—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 दिसम्बर, 1970 से आंध्र आयल एण्ड केक प्रोडक्ट्स लि० द्वारकानगर, विशाखापटनम तथा इसकी शाखाएं 1-3 ब्राबोर्न रोड, कलकत्ता और, 8 चिनानाया कर्न एसटी मद्रास-1 नामक स्थापन को एतद्द्वारा उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस-35019(161)/71—पी०एफ० 2 (ii)]

S.O. 1972.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Vikas Motors, 12-A, Najafgarh Road, Industrial Area, New Delhi have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1970.

[No. S.35019/164/71-PF. II(i).]

का०आ० 1972—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स विकास मोटर्स, 12-ए, नजफगढ़ रोड, इण्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन पर लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त

अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1970 की मई के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(164)/71-पी०एफ० 2(ii)]

S.O. 1973.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies, with effect from the first May, 1970 the establishment known as Messrs Vikas Motors, 12-A, Najafgarh Road, Industrial Area, New Delhi, for the purposes of the said proviso.

[No. S.35019/164/71-PF. II(ii).]

का० आ० 1973—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 मई, 1970 से विकास मोटर्स, 12-ए, नजफगढ़ रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली, नामक स्थापन को एतद्द्वारा उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस-35019(164)/71-पी०एफ०-2(ii)]

New Delhi, the 11th April 1972

S.O. 1974.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Travelera Limited Shabibag House, 13 Walchand Hirachand Ballard Estate, Bombay-1 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1971.

[No. S-35017/61/71-PF.II(i).]

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1972

का० आ० 1974—यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ट्रेवलर्स लिमिटेड, शाबीबाग हाउस, 14 बालचंद हिराचंद बेलर्ड एस्टेट, बम्बई-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1962 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अत :, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1971 के अप्रल के प्रथम दिन को प्रवत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35017(61)/71-पी० एफ० 2(ii)]

S.O. 1975.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies, with effect from the 1st April, 1971 the establishment known as Messrs Travelera Limited, Shabibag House, 13, Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate, Bombay-1 for the purposes of the said proviso.

[No. S-35017/61/71-PF.II(ii).]

का० आ० 1975—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात 1 अप्रैल, 1971 से मैसर्स ट्रेवलर्स लि०, शाबीबाग हाउस, 13, बालचंद हीराचंद मार्ग, बेलर्ड एस्टेट, बम्बई-1 नामक स्तापन को एतद्द्वारा उक्त परन्तुक के प्रयोजनो के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस-35017/61/71-पी० एफ० 2(ii)].

S.O. 1976.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs M. J. Exports Abubakar Mansion, 2nd Floor, 7, Colaba Causeway Road, Bombay-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of March, 1971.

[No. S. 35017(66)/71-PF.II(i).]

का० आ० 1976—यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एम० ज० एक्सपोर्ट अबूबकर मेंशन, सेकेन्ड फ्लोर, 7, कोलाबा कोसवे रोड, बम्बई-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु संख्याइस बात पर सहमत हो गई कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952(1952 का 19)के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अत : अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह आधसूचना 1971 के मार्च, के 31 वें दिन को प्रवत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एम-35017(66)/71-पी० एफ० 2(i)]

S.O. 1977.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies, with effect from the 31st March, 1971, the establishment known as Messrs M. J. Exports Abubakar Mansion, 2nd Floor, 7, Colaba Causeway Road, Bombay-1, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35017(66)/71-PF.II(ii).]

का० आ० 1977—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 31 मार्च 1971 से मैसर्स एम० जे० एक्सपोर्ट अब्बूबकर मेंशन, सेकेण्ड फ्लोर 7, कोलाबा कोसवे रोड, बम्बई-1 नामक स्थापन को एतद्-द्वारा उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस०-35017(66)/71-पी० एफ० II(ii)]

S.O. 1978.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Mineral Ore Extension and Trading Company and its other branches detailed in the Scheduled below—

(1) Verlem Mines, Neturlem—P.O. Sangnem.
(2) Mangal Mines P.O. Sangnem.
(3) Vichundrem Mines P.O. Sangnem.
(4 Bonquitembe Mines—P.O. Sangnem.
(5) Curpem Mines P.O. Sengnem.
(6) Rivona Mine P.O. Rivona—Taluka Qnepem Goa.
(7) Revora Mine—P.O. Pirna Barder Goa.
(8) Marcel Mine—P.O. Marcel, Goa.

have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of July, 1971.

[No. S.35017/55/71-PF. II.]

का० आ० 1978 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मिनरल और एक्सटेंशन एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी तथा इसकी शाखायें—

(1) वार्लीम माइन्स, नेतरलिम—पो० आ० सगनेम।
(2) मंगल माइन्स, पो० आ० सगनेम।
(3) विचूड्रेम माइन्स, पो० आ० सगनेम।
(4) बौक्विटैम्बो माइन्स, पो० आ० सगनेम।
(5) करपैम माइन्स, पो० आ० सगनेम।
(6) रिवोना माइन, पो० आ० रिवोना, तालुका क्वेपेम गोआ।
(7) रेवारा माइन—पो० आ० पिरना, बार्डर गोआ।
(8) मारेल माइन—पो० आ० मारेल, गोआ

नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1971 की जुलाई के 31वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[संख्या एस-35017(55)/71-पी एफ० 2]

S.O. 1979.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Damhera Steel and Forgings Private Limited Calcutta including its (1) Accounts office 58, Netaji Subhas Road, Calcutta-1 (2) Works at 15, Grand Trunk Road North Howrah and (3) Branch office at 234, Ajmeri Gate Delhi-6 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of August, 1969.

[No. S-35018/60/71-PF. II.]

का० आ० 1979. — यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दमहेरा स्टील एण्ड फोर्जिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता तथा इसके (1) लेखा कार्यालय—58, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता—1।

(2) कारखाना—15, ग्रांड ट्रंक रोड, हावड़ा, तथा
(3) शाखा कार्यालय 234, अजमेरी गेट, दिल्ली—6

नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाये चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1969 के अगस्त के 31वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35018(60)/71-पी०एफ० 2]

S.O. 1980.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Shah Radio Stores 4/1, Madan Street, Calcutta and its Show Room at 3/B Madan Street, Calcutta have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the Thirty first day of December, 1970.

[No. S.35018/62/71-PF. II.]

का० आ० 1980:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स शाह रेडियो स्टोर्स, 4/1, मदन स्ट्रीट, कलकत्ता तथा 3-बी, मदन स्ट्रीट, कलकत्ता की शो रूम भी नामक स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1970 के दिसम्बर, के 31वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35018(62)/71-पी० एफ० 2]

S.O. 1981.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs United Cooperative Distributors Ltd., 18, Rabindra Sarani, Calcutta-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of March, 1971.

[No. S.35018(68)/71-PF. II.]

का० आ० 1981:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स यूनाइटेड कोआपरेटिव डिस्ट्रीब्यूटर्स लि०, 18, रवीन्द्र सारणी कलकत्ता—1, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहियें ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1971 के मार्च के 31वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35018(68)/71-पी० एफ० 2]

S.O. 1982.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Hindustan Steel Works Construction Limited, 5/1, Commissariat Road, Calcutta-23 including its Branch at Bokaro Steel City, Bokaro have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of August, 1965.

[No. S-35018(66)/71-PF. II(i).]

का० आ० 1982.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स, कन्स्ट्रैक्शन लिमिटेड 5/1, कमिश्रेट रोड, कलकत्ता—23 तथा इसकी शाखा जो बोकारो स्टील सिटी, बोकारो में है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 का 19) को उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1965 के अगस्त के 31वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35018(66)/71-पी० एफ० 2(i)]

S.O. 1983.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 31st day of August, 1965 the establishment known as Messrs Hindustan Steel Works Construction, Limited 5/1, Commissariat Road, Calcutta-23 including its branch at Bokaro Steel City, Bakaro for the purposes of the said proviso.

[No. S.35018(66)/71-PF.II(ii).]

का० आ० 1983.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात 31 अगस्त, 1965 से हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन, लिमिटे , 5/1, कमिश्रेट रोड, कलकत्ता—23 तथा इसकी बोकारो स्टील सिटी बोकारो वाली शाखा नामक स्थापन को एतदद्वारा उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस-35018(66)/71-पी०एफ० 2(ii)]

S.O. 1984.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the Employees in relation to the establishment known as Messrs. Equipment Leasing Company, 134-B, Ratu Sircar Lane, Calcutta-7, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1969.

[No. S. 35018(69)/71-PF.II.]

का० आ० 1984.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इक्विपमेंट लीजिंग कम्पनी, 34-बी राटू सिरकार लेन, कलकत्ता-7 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1969 के दिसम्बर, के 31वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35018(69)/71-पी०एफ० 2]

S.O. 1985.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Micro Offset Printer Road, Post Box No. 106, S have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of February, 1971.

[No. S. 35019/16/71-PF.II.]

का०आ० 1985.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स माक्रो ऑफसेट प्रिंटर्स, 156, थिरुथंगल रोड, पोस्ट बाक्स संख्या 106, सिवाकासी, (साउथ इंडिया) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1971 की फरवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(16)/71-पी०एफ०-2]

S.O. 1986.—Whereas is appears the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Maharaja Cossimbazar Stone Works (P) Ltd., 138, Canning Street. (Third Floor), Calcutta-1 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Govrnment hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of June, 1971.

[No. S.35018(65)/71-PF.II.]

का० आ० 1986.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स महाराजा कोसिम बाजार स्टोन वर्क्स (प्रा०) लिमिटेड, 139, कैनिंग स्ट्रीट (3अई-फ्लोर) कलकत्ता-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1971 के जून के 30वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35018(65)/71-पी०एफ० 2]

S.O. 1987.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Vijaya Lithos, 42-A Langs Garden Road, Madras-2, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1971.

[No S-35019(97)/71-PF.II.]

का० आ० 1987.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स विजया लिथोस, 42-ए, लैंस गार्डन रोड, मद्रास-2 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है

यह अधिसूचना 1971 के जून के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(97)/71-पी० एफ० 2]

S.O. 1988.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sterling Traders, Pearey Lal Building, Kashmiri Gate Delhi-6 including its branch M/s Sterling Traders C/O Tara Chand Satya Petrol

Pump (Burmah Shell) Faridabad (Haryana) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1971.

[No. S.35019/155/71-PF.II(i)]

का०आ० 1988.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स स्टर्लिंग ट्रेडर्स, प्यारेलाल बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली–6 तथ इसकी शाखा मेसर्स स्टर्लिंग ट्रेडस, मार्फत तारा चंद सत्या पेट्रोल पम्प (बर्मा शैल) फरीदाबाद (हरियाणा) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1971 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस–35019/155/71–पी० एफ० 2(i)]

S.O. 1989.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies, with effect from the 1st January, 1971 the establishment known as Messrs Sterling Traders, Pearey Lal Building, Kashmiri Gate, Delhi-6 including its Branch C/O Tara Chand Satya Petrol Pump (Burmah Shell), Faridabad, Haryana for the purposes of the said proviso.

[No. S.35019/155/71-PF.II(ii)]

का०आ० 1989.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात 1 जनवरी, 1971 से मैसर्स स्टर्लिंग ट्रेडस, प्यारेलाल बिल्डिंग, कश्मीरी गैट, दिल्ली–6 तथा इसकी शाखा मार्फत ताराचन्द सत्या पेट्रोल पम्प (बर्मा शैल) फरीदाबाद, हरियाणा नामक स्थापन को एतद्द्वारा उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस–35019/155/71–पी० एफ० 2(ii)]

S.O. 1990.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Prabakar Transports, 31-B, Chimmayapillai Road, N.M. Extension, Salem-7 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of December, 1971.

[No. S.35019(179)/71-PF.II.]

का०आ० 1990.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स प्रभाकर ट्रांसपोर्ट, 31–बी, चिमायापिलई रोड, एंन० एम० एक्सटेंशन सालेम–7 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटम्ब पेंशन निधि अधिनिय, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1971 के दिसम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस–35019/179/71–पी०एफ०–2]

S.O. 1991.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Yezdi Distilleries, Bannimantap Lay-out, Mysore-7 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1971.

[No. S-35019(180)/71-PF.II.]

का० आ० 1991.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स यज्दी डिस्टीलरीज, बानीमनटप ले-आउट, मैसूर-7 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1971 के नवम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस–35019/180/71–पी० एफ०(2)]

S.O. 1992.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs K. K. Menon Motor Service, Anthikad, Trichur, Kerala State have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers confererd by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall come into force on the thirty first day of March, 1972.

[No. S. 35019/181/71-PF. II.]

का०आ० 1992.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स के० के० मेनन मोटर सर्विस, अंधीकड, त्रिचूर, केरल स्टेट नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1972 की मार्च के 31वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस–35019(181)/71–पी० एफ० 2]

S.O. 1993.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Merrs Tiffin's Barytes Asbestos and Paints Limited, Station Road, Cuddapah (District) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pensionn Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1972.

[No. S.35019(189)/71-PF.II.]

का० आ०1993.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स टिफिन्स बैरीट्स एसबैस्टोस एण्ड पेन्ट्स लिमिटेड, स्टेशन रोड, कुडापाह (जिला) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1972 को जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं०एस–35019(189)/71–पी०एफ०2]

New Delhi, the 25th April 1972

S.O. 1994.—In pursuance of clause (g) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby nominates Miss E. D'Souza as a member of the Employees' State insurance Corporation and makes the folowing further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. 2763, dated the 27th May, 1971, namely:—

In the said notification, for serial No. 29 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"29. Miss E. D'Souza, Incharge Social Security Department, Rashtriya Mill Mazdoor Sangh, Mazdoor Manzil, G. D. Ambekar Marg, Parel, Bombay-12."

[No. F. U-16012/10/71-HI.]

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1972

का०आ० 1994.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (छ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कुमारी ई० डी० सीउजा को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्य के रूप में नामित करती है और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास, मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या 2763 तारीख 27 मई, 1971 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 29 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"29. कुमारी ई० डी० सोउजा,
प्रभारी, सामाजिक सुरक्षा विभाग,
राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ,
मजदूर मंजिल, जी० डी० अमेकर मार्ग,
पारेल, बम्बई-12"।

[संख्या फा० य० 16012/10/72-एच० आई०]

S.O. 1995.—Whereas the Central Government is of opinion that Shri M. T. Shukla, member of Employees' State Insurance Corporation nominated by the Central Government in consultation with the Indian Trade Union Congress under clause (g) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), has ceased to represent that Trade Union Congress;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 12 of the said Act, the Central Government hereby declares that Shri M. T. Shukla shall cease to be a member of the Employees' State Insurance Corporation with effect on and from the date of publication of this notification in the official Gazette.

[No. F. U-16012/10/71-HI.]

एस०आ० 1995.—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (छ) के अधीन भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्य श्री एम० टी० शुक्ला ने मजदूर संघ का प्रतिनिधित्व करना बंद कर दिया है ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यह घोषणा करती है कि श्री एम० टी० शुक्ला इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्य नहीं रहेंगे ।

[संख्या यू-16012/10/71-एच० आई०]

New Delhi, the 11th May 1972

S.O. 1996.—In pursuance of clause (c) of sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, the Central Government appoints the Labour Secretary of the Bengal Chamber of Commerce and Industry as a member of the Regional Committee for the State of West Bengal and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour No. S.R.O. 1278 dated the 20th June, 1959:—

In the said notification for entry (5), the following entry shall be substituted, namely:—

"(5) The Labour Secretary, The Bengal Chamber of Commerce and Industry, 6 Netaji Subhas Road, Calcutta—1."

[No. 12/6/64-PF.II.]

नई दिल्ली, 11 मई, 1972

का०आ० 1996.—कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 4 के उपपारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्रम सचिव, बंगाल चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री को पश्चिमी बंगाल राज्य के लिए क्षेत्रीय समिति का सदस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 1278 तारीख 20 जून, 1959 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है,

उक्त अधिसूचना में प्रविष्टि (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(5) श्रम सचिव, बंगाल चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, 6, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता—1।

[सं० 12/6/64—पी० एफ०—II]

New Delhi, the 2nd June 1972

S.O. 1997.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Baltex Engineering Private Limited, Union Bank Buildings, Bombay, Samachar Street, Bombay-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1971.

[No. S. 35018(20)/72-PF. II.]

नई दिल्ली, 2 जून, 1972

का०आ० 1997.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बालटैक्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, यूनियन बैंक बिल्डिंग, समाचार स्ट्रीट बम्बई-1 बी आर० नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1971 के दिसम्बर के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[संख्या एस० 35018 (20)/72—पी० एफ० 2]

S.O. 1998.—Whereas is appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Raghomull & Sons, 4-E, Connaught Place, New Delhi have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1971.

[No. S. 35019(36)/72-PF. II.]

का० आ० 1998.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मसर्स राघोमल्ल एण्ड सन्स, 4-ई, कनाट प्लेस, नई दिल्ली नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1971 की अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[संख्या एस० 35019 (36)/72—पी० एफ० 2]

S.O. 1999.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Emkeyyesbee, 40, Arcot Road, Madras-26, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of March, 1971.

[No. 8/43/70-PF. II(i).]

का०आ० 1999—यतः केन्द्रीय सरकार की यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एम के एस बी, 40 अर्काट रोड, मद्रास-26, नामक स्थापन से सबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1971 की मार्च के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[संख्या 8/43/70-पी० एफ० 2 (i)]

S.O. 2000.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 1st March, 1971, the establishment known as Messrs Emkeyyesbee, 40, Arcot Road, Madras-27 for the purposes of the said proviso.

[No. 8(43)/70-PF. II(ii).]

का०आ० 2000.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् मार्च, 1971 से मैसर्स एम के एस बी, 40 अर्काट रोड, मद्रास-26, नामक स्थापन को एतद्द्वारा उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[संख्या एस०-8 (43)/70-पी० एफ० 2 (ii)]

S.O. 2001.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Mokalbari Tea Estate Private Limited, 13/2, Ballygunge Park Road, Calcutta-19, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1969.

[No. S-35017(18)/72-PF. II(i)]

का० आ० 2001.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मसर्स मोकलबारी टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, 13/2, बालीगंज पार्क, रोड, कलकत्ता-19 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1969 के दिसम्बर के 31 वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35017(18)/72-पी० एफ० 2 (i)]

S.O. 2002.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 31st December, 1969, the establishment known as Messrs Mokalbari Tea Estate Private Limited, 13/2, Ballygunge Park Road, Calcutta-19 for the purposes of the said proviso.

[No. S-35017(18)/72-PF.II(ii).]

का० आ० 2002.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 31 दिसम्बर, 1969 से मोकलबारी टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, 13/2, बालीगंज पार्क रोड, कलकत्ता-19 नामक स्थापन को एतद्द्वारा उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस०-35017(18)/72-पी० एफ० 2 (II)]

S.O. 2003.—Where it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Anand and Company, 34A, Brabourne Road, Calcutta-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of March, 1971.

[No. S. 35017(4)/72-PF. II(i).]

का० आ० 2003.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आनन्द एण्ड कम्पनी, 34-ए, ब्राबोर्न रोड, कलकत्ता-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1971 के मार्च के 32 वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35017(4)/72-पी० एफ० 2 ()]

S.O. 2005.—Whereas it appears to the Central by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 31st March, 1971, the establishment known as Messrs Anand and Company, 31A, Brabourne Road, Calcutta-1 for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35017(4)/72-PF. II(ii).]

का० आ० 2004.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 31 मार्च, 1971 से मैसर्स आनन्द एण्ड कम्पनी, 31ए, ब्राबोर्न रोड, कलकत्ता-1 नामक स्थापन को एतद्द्वारा उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[संख्या एस०-35017(4)/72 पी० एफ० II (ii)]

S.O. 2005.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Laminated Packings (P) Ltd., A-1, Industrial Estate, Visakhapatnam-7, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1971.

[No. S. 35019(146)/71-PF. II(i).]

का० आ० 2005.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स लेमिनेटेड पैकिंग्ज (पी०) लिमिटेड, ए-1, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, विशाखापट्टनम्-7 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1971 की जुलाई के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(146)/71-पी० एफ० 2(i)]

S.O. 2006.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 1st July, 1971, the establishment known as Messrs Laminated Packings (P) Ltd., A-1, Industrial Estate, Visakhapatnam-7, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(146)/71-PF. II(ii).]

का० आ० 2006.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 जुलाई, 1971 से लैमिनेटेड पैकिंग्ज (पी) लिमिटेड, ए-1, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, विशाखापट्टनम्-7 नामक स्थापन को एतद्द्वारा उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस० 35019(146)/71-पी० एफ० II(ii)]

S.O. 2007.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Khaitan & Company, Flat No. B-72, 7th Floor, Himalaya House, 23, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1970.

[No. S. 35019(15)/72-PF. II(i).]

का० आ० 2007.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स खैतन एंड कम्पनी, फ्लैट, न० बी०-72, सातवीं मंजिल, हिमालया हाउस, 23, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1970 के अक्तूबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(15)/72-पी० एफ० 2(i)]

S.O. 2008.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 1st October, 1970, the establishment known as Messrs Khaitan & Company, Flat No. B-72, 7th Floor, Himalaya House, 23, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(15)72-PF. II(ii).]

का० आ० 2008.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अक्तूबर 1970 से खैतन एण्ड कम्पनी, फ्लैट सं० बी—72, सातवीं मंजिल, हिमालया हाउस, 23, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली नामक स्थापन को एतद्द्वारा उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस०—35019(15)/72-पी० एफ० II(ii)]

S.O. 2009.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Anita Prints, Andheri Kurla Road, Bombay-59, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1971.

[No. S. 35018(8)/72-PF. II(i).]

का० आ० 2009.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अनिता प्रिंटस, अन्धेरी कुर्ला रोड, बम्बई 59 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1971 की मई के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०—35018(8)/72-पी०एफ० 2(i)]

S.O. 2010.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 1st May, 1971, the establishment known as Messrs Anita Prints, Andheri Kurla Road, Bombay-59, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018(8)/72-PF. II(ii).]

का० आ० 2010.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 मई, 1971 से अनिता प्रिंटस, अन्धेरी कुर्ला रोड, मुम्बई—59 नामक स्थापन को एतद्द्वारा उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस०—35018(8)/72—पी० एफ० II(ii)]

S.O. 2011.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rajpurohit Construction Co. Dharamchand Industrial Estate, Behind Telecom Factory Sion—Trombay Road, Bombay, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1971.

[No. S. 35018(13)/72-PF. II(i).]

का० आ० 2011—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स राजपुरोहित कन्सट्रक्शन कम्पनी, धर्मचन्द इंडस्ट्रियल एस्टेट, बिहाइंड टेलीफाम फैक्टरी साएन, ट्रौम्बे रोड, बम्बई, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1971 के अप्रैल, के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०—35018 (13)/72—पी० एफ० 2(i)]

S.O. 2012.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 1st April, 1971, the establishment known as Messrs Rajpurohit Construction Co., Dharamchand Industrial Estate, Behind Telecom Factory Sion—Trombay Road, Bombay, for the purposes of the said proviso.

[No. S-35018(13)-72-PF. II(ii).]

का० आ० 2012.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अप्रैल, 1971 से राजपुरोहित कन्सट्रक्शन कम्पनी, धर्मचन्द इंडस्ट्रियल एस्टेट, बिहाइंड टेलीफाम फैक्टरी, सिओन ट्रौम्बे रोड, बम्बई, नामक स्थापन को एतद्द्वारा उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस०—35018(13)/72—पी० एफ० II(ii)]

S.O. 2013.—Whereas it appears to Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as the Vacuum Forming Company, 3/21, Prabhadevi Industrial Estate, 402, Cadell Road, Bombay-25 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1971.

[No. 35018(16)/72-PF.II(i).]

का० आ० 2013.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि दि वैक्युम्र कम्पनी, 3/21, प्रभादेवी इन्डस्ट्रियल एस्टेट, 402, काडेल रोड, मुम्बई–25 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ;

यह अधिसूचना 1971 के दिसम्बर के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०–35018 (16)/72–पी० एफ० 2(i)]

S.O. 2014.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 31st December, 1971 the establishment known as the Vaccum Forming Company, 3/21, Prabhadevi Industrial State, 402, Cedell Road, Bombay—25 for the purposes of the said proviso.

[No. S.35018(16)/72-PF.II.(ii).]

का० आ० 2014.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात 31 दिसम्बर, 1971 से वैक्युम्र फार्मिंग कम्पनी, 3/21 प्रभादेवी इंडस्ट्रियल एस्टेट, 402 काडिल रोड, मुम्बई –25 नामक स्थापन को) एतद्द्वारा उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस०–35018(16)/72–पी० एफ० 2(ii)]

S.O. 2015.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Malhotra Spear Jackson Saws Manufacturing Company Private Limited, Post Office Wagle Industria Estate Agra Road, District Thana, Maharashtra have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of July, 1971.

[No. S.35018(5)/72-PF.II(i).]

का० आ० 2015.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मलहोत्रा स्पीयर जैकसन सा मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, पोस्ट आफिस वागला इंडस्ट्रियल एस्टेट, आगरा रोड, जिला थाना, महाराष्ट्र नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ;

यह अधिसूचना 1971 की जुलाई के 31 वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस–35018(5)/72–पी० एफ० 2(i)]

S.O. 2016.– In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 31st July, 1971, the establishment known as Messrs. Malhotra Spear Jackson Saws Manufacturing Company Private Limited, Post Office Wagle, Industrial Estate, Agra Road, District Thana, Maharashtra for the purposes of the said proviso.

[No. S.35018(5)/72-PF.II(ii).]

का० आ० 2016.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1052 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात 31 जुलाई 1971 से मैसर्स मल्होत्रा स्पीयर जैक्सन सा मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, पोस्ट आफिस बागला इंडस्ट्रियल एस्टेट आगरा रोड, जिला थाना महाराष्ट्र नामक स्थापन को एतद्द्वारा उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस०–35018(5)/72–पी० एफ० II(ii)]

S.O. 2017.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Renuka Engineering Works, 140, Patel Road, Coimbatore-9 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1972.

[No. S. 35019(13)/72-PF.II.]

का० आ० 2017.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रेनुका इंजीनियरिंग वर्क्स, 140, पटल रोड, कोयम्बाटोर–9 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1972 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस०-35019(13)/72-पी० एफ० 2]

S.O. 2018.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bandeckar Parkkot Shipping (Private) Limited, Box No. 1, Panjim, Goa have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1971.

[No. S. 35018/14/72-PF.II.]

का० आ० 2018.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बंदेकर परखोट शिपिंग (प्राइवेट) लिमिटेड, बाक्स सं० 1, पंजिम, गोआ—नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1971 का जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35018(14)/72-पी० एफ०2]

S.O. 2019.—Whereas it appears to the Central Government that the empoyer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Manjakattai Estate, Asambur (B.O.), Yercband (Post) Salem District have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1972.

[No. S. 35019(32)/72-PF.II.]

का० आ० 2019.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मंजाकुटई एस्टेट, असमबुर (बी० ओ०) यहकाड (पोस्ट) जला ससुम, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) 8 उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1972 की जनवरी, के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एम-35019(32)/71-पी० एफ० 2]

S.O. 2020.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment know as Messrs Tamilnadu Consumers' Cooperative Federation Ltd., Madras, including its Branch at 52/53, Thamby Chetty Street, Madras-1, have agreed that provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1972.

[No. S. 35019(9)/72-PF.II.]

का० आ० 2020.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स तमिलनाडु कनज्यूमर्स कोआपेरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, मद्रास, जिसमें 52/53, थम्बी स्ट्रीट, मद्रास-1 स्थित उसकी शाखा सम्मिलित है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1972 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रदत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(9)/72-पी० एफ० 2]

S.O. 2021.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Femme International, 5-A, Krishna Udyog Bhavan, G-4, Nariman Road, Worli, Bombay-25 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of September, 1971.

[No. S. 35018(15)/72-PF.II.]

का० आ० 2021.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स फैमीन इन्टरनेशनल, 5-ए, कृष्ण उद्योग भवन, जी० एच० नारीमान रोड, बोरीवली, मुम्बई-25 नामक स्थापन मे सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1971 के सितम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35018(15)/72-पी०एफ० 2]

S.O. 2022.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as The Southern Railway Employees Consumers Co-operative Stores Ltd., Virudunagar, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1971.

[No. S. 35019(78)/71-PF.II.]

का० आ० 2022.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स साउदर्न रेलवे एम्पालाइज को-ओपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड, विरुदुनगर नामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1971 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(78)/71-पी० एफ० 2]

S.O. 2023.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs W. D. Engineering Works, 233, Balilious Road, P. S. Bantra, Howrah, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of April, 1970.

[No. S. 35017(3)/72-PF.II.]

का०आ० 2023—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि डब्ल्यू० डी० इंजीनियरिंग वर्क्स, 233, बेलिलयस रोड़, पी० एस० बंत्रा, हावड़ा नामक स्थापन मे सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19), के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थातपन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह सूचना 1970 की अप्रैल के तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35017 (3)/72—पी०एफ०-2]

New Delhi, the 6th June 1972

S.O. 2024.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 3364 dated the 18th August, 1971 the Central Government having regard to the location of the Police Automobile Workshops at Bikaner and Jodhpur in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said workshops from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year with effect from the 1st July, 1972 upto and inclusive of the 30th June, 1973.

[No. F.S. 38017(22)/72-HI.]

नई दिल्ली, 6 जून, 1972

का० आ० 2024.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73ब द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 3364 तारीख 18 अगस्त, 1971 के क्रम में केन्द्रीय सरकार पुलिस आटोमोबाइल वर्कशाप, बीकानेर और जोधपुर की ऐसी क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबंध प्रवृत्त है, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कर्मशालाओं को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से 1 जुलाई, 1972 से 30 जून, 1973 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष की अवधि के लिए एतद्द्वारा छूट देती है।

[सं० फा० एस०-38017 (22)/72-एच० आई०]

S.O. 2025.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 773, dated the 4th February, 1972, the Central Government having regard to the location of the Biological Products Section Badshah

Bagh, Lucknow, in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said factory from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year with effect from the 15th May, 1972 upto and inclusive of the 14th May, 1973.

[No. S.38017(31)/72-HI.]

का० आ० 2025.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० 773 तारीख 4 फरवरी, 1972 के क्रम में केन्द्रीय सरकार बायोलोजिकल प्रडक्टस संक्शन, बादशाह बाग, लखनऊ की ऐसी क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबंध प्रवृत्त हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उदग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से 15 मई, 1972 से 14 मई, 1973 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष की अवधि के लिये एतद्द्वारा छूट देती है।

[सं० फा० एस० 38017(31)/72-एच० आई०]

S.O. 2026.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2780, dated the 5th July, 1971 the Central Government having regard to the location of the factory, namely, Central Jail Factory, Vellore, in an areas in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said factory from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year with effect from the 24th June, 1972 upto and inclusive of the 23rd June, 1973.

[No. F.S-38017(30)/72-HI.]

का० आ० 2026.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73 च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 2780, तारीख 5 जुलाई, 1971 के क्रम में केन्द्रीय सरकार सेन्ट्रल जेल फैक्टरी, वेल्लोर नामक कारखाने को ऐसे क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबंध प्रवृत्त हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उदग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से 24 जून, 1972 से 23 जून, 1973 तक, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए एतद्द्वारा छूट देती है।

[सं० फा० एस०-38017(30)/71-एच० आई०]

S.O. 2027.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Empoyees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), No. S.O. 2785, dated the 5th July, 1971 the Central Government having regard to the location of the factory, namely, Workshop belonging to the Municipal Corporation, Indore, in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said factory from the payment of the employers' special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year with effect from the 29th June, 1972 upto and inclusive of the 28th June, 1973.

[No. F.S-38017(26)/72-HI.]

का०आ० 2027.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73 च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 2785 तारीख 5 जुलाई, 1971 के क्रम में केन्द्रीय सरकार म्युनिसिपल कारपोरेशन, इंदौर, की कर्मशाला नामक कारखाने की ऐसे क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबंध प्रवृत्त है, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए, उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उदग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से 29 जून, 1972 से 28 जून, 1973 तक, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए एतद्द्वारा छूट देती है।

[सं० फा० 38017(26)/71-एच० आई०]

S.O. 2028.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2124 dated the 19th May, 1971 the Central Government having regard to the location of the Central Jail Woollen Factory, Bhagalpur in an area in whih the provisions of Chapter IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said factory from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year with effect from the 20th April, 1972 upto and inclusive of the 19th April, 1973.

[No. F.S.38017/16/72/HI.]

का० आ० 2028.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73 च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 2124 तारीख 19 मई, 1971 के क्रम में केन्द्रीय सरकार सैन्ट्रल जेल वूलन फैक्टरी, भागलपुर की ऐसी क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त हैं, अवस्थति को ध्यान में रखते हुए, उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विधि अभिदाय के संदाय से 20 अप्रैल, 1972 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष की कालावधि के लिए एतद्द्वारा छूट देती है।

[सं० फा० एस० 38017(16)/72-एच० आई०]

S.O. 2029.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2129 dated the 19th May, 1971 the Central Government having regard to the location of the Government Regional

Press, Tiruchirapalli in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said press from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year with effect from the 1st June, 1972 upto and inclusive of the 31st May, 1973.

[No. F.S.38017(19)/72-HI.]

का० आ० 2029.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73—च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 2129 तारीख 19 मई, 1971 के क्रम में केन्द्रीय सरकार गवर्नमेंट रिजनल प्रैस, तिरुचिरापल्ली की ऐसी क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबंध प्रवृत्त है, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रैस को उक्त अधिनियम के अध्याय 5—क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से 1 जून, 1972 से 31 मई, 1973 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष की कालावधि के लिए एतद्द्वारा छूट देती है।

[सं० फा० एस० 38017 (19)/72-एच० आई०]

S.O. 2030.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2128 dated the 19th May, 1971 the Central Government having regard to the location of the Sewage Purification Plant, Colaba, Bombay in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said plant from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year with effect from the date of expiry of the period specified in the said notification upto and inclusive of the 2nd April, 1973.

[No. F.S.38017(18)/72-HI.]

का० आ० 2030.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73—च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 2128 तारीख 19 मई, 1971 के क्रम में केन्द्रीय सरकार सीवेज प्योरिफिकेशन प्लान्ट, कोलाबा, मुम्बई की ऐसी क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबंध प्रवृत्त है, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त संयत्र को उक्त अधिनियम के अध्याय 5—क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख से 2 अप्रैल, 1973 तक जिस में वह दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष की कालावधि के लिए एतद्द्वारा छूट देती है।

[सं० फा० एस० 38017(18)/72-एच० आई०]

S.O. 2031.—Whereas the Central Government was satisfied that Mysore Cements Limited was situated in Ammasandra area which was a sparse area (that is, an area whose insurable population was less than 500) in the district of Tumkur in the State of Mysore;

And, whereas by virute of its location in a sparse area the aforesaid factory was granted exemption from the payment of the employer's special contribution under section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) until enforcement of the provisions of Chapter V of the said Act in that area by the Central Government in the notification of the Government of India in late Department of Social Security No. S.O. 946 dated the 19th March, 1965;

And, whereas the Central Government is satisfied that the insurable population of the Ammasandra area in the district of Tumkur in the State of Mysore has now exceeded 500, and it is no longer a sparse area;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the said notification, namely:—

In the Schedule to the said notification against Serial No. 11, the entry "Ammasandra" in column 3 and the corresponding entry in Column 4 shall be omitted.

[No. F.S-38018(1)/72-HI.]

का० आ० 2031.—यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया था कि मैसूर सीमेंटस लिमिटेड, आमासंद्रा क्षेत्र में स्थित था जो मैसूर राज्य के तुमकुर जिले में बिखरी हुई आबादी का क्षेत्र (अर्थात् ऐसा क्षेत्र जिसकी बीमा योग्य आबादी 500 से कम थी) था ;

और, यतः उसकी बिखरी हुई आबादी के क्षेत्र में अवस्थिति के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त कारखाने को, भारत सरकार के भूतपूर्व सामाजिक सुरक्षा विभाग की अधिसूचना सं० का० आ० 946 तारीख 19 मार्च, 1965, द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च के अधीन नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से तब तक के लिए छूट दे दी थी जब तक कि उस अधिनियम के अध्याय 5 के उपबंध उस क्षेत्र में प्रवर्तित नहीं हो जाते ।]

और यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि मैसूर राज्य के तुमकुर जिले में आमासंद्रा क्षेत्र की बीमा योग्य आबादी अब 500 से बढ़ गई है, और वह अब बिखरी हुई आबादी का क्षेत्र नहीं है ;

अतः, अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्या 11 के सामने स्तंभ 3 में "आमासंद्रा" प्रविष्टि और स्तंभ 4 में तत्स्थानी प्रविष्टि लुप्त कर दी जाएगी ।

[सं० फा० एस० 38018(1)/72-एच० आई०]

New Delhi, the 19th June 1972

S.O. 2032.—In exercise of the powers conferred by Section 73 F of the Employees, State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government, having regard to the location of the factories specified in column (4) of the Schedule hereto annexed in areas specified in column (3) of the said Schedule in the State of Mysore in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are not in force hereby exempts the said factories from the payment of employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette or until the enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of District	Name of area	Name of the factory
1	2	3	4
	Private Factories.		
1.	Mangalore.	Neermarga	M/s. Neria Timber Industries, Neermarga, Mangalore.
2.	Do.	Do.	M/s. Fimco Saw Mills and Industries, Neermarga, Mangalore.
3.	Bangalore.	Dodda Kalasandra Village.	M/s. Hegde and Golay(P) Ltd., 8th Mile Stone Kanakapura Road, Thalaghattapura, Bangalore.
4.	Gulbarga	Narayanpur.	M/s. Chhaya R. C. Pipes P.O. Narayanapur, Taluk Shorapur Gulbarga District.
5.	Bangalore	Viswaneedam P.O.	M/s. Cor Card Containers, 7th Mile, Magadi Road Viswaneedam P.O. Bangalore-23.
6.	Hassan	Alur.	M/s. Gayathri Match Factory, Alur, Hassan District.
7.	Bangalore	Doddakallasandra Village.	M/s. Bit Tul (P) Ltd., Shree Shyla, 8th Mile Stone Doddakallasandra village, Kanakapura Road, Bangalore-11.
8.	Shimoga	Sagar	M/s. Gajanana Motor Transport Co. Ltd., Sagar.
9.	Bangalore	Bangalore.	M/s. Bengal Electric Lamp Works, Ltd., 13th Mile, Old Madras Road, Mangalore.-36.
10.	Mysore.	Hunsur.	M/s. Jothi Small Industries, B. M. Road, Hunsur.
11.	Hassan	Holenarasipur.	M/s. Indira Match Industries, Holenarasipur, Hassan District.
12.	Hassan	Manchanahalli.	M/s. Sivakami Match Factory, Manchanahalli village Belur Road, Hassan.
13.	Mysore	Badanaval.	M/s. Badanaval Khadi and Gramodhyog Sangha, Badanaval, Mysore District.
14.	Mangalore.	Belinela.	M/s. Indian Plywood Manufacturing Co., Belinela, Subramanya Road Station, P.O. Nettana S. K.
15.	Belgaum.	Machhe.	M/s. Meghadoot Cement Pipe Industries Machine P.O., Belgaum.
16.	Dharwar	Jaknur	M/s. Jaknur Jaggery Limited, Jaknur, P.O. Jamakhandi.
17.	Tumkur	Tumkur	M/s. Prakash Furniture Works and Saw Mills, Near Electric Colony, Tumkur.
	Public Factories.		
1.	Kolar	Chikkaballapur.	Mysore State Road Transport Corporation Depot/Work shop, Chikkaballapur.
2.	Mangalore,	Panambur.	The Executive Engineering, Mechanical Division, Mangalore Harbour Project, Panambur S. K.
3.	Dharwar	Annigere	Mysore State Electricity Board, Annigeri.
4.	Dharwar	Kalghatgi	Mysore State Electricity Board, Kalghatgi.
5.	Tumkur	Tumkur	Mysore State Road Transport Corporation, Depot, Bus Stand, Tumkur.

[No. F. S-38014(3)/71-HI.]

नई दिल्ली, 19 जून 1972

का० आ० 2032.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 73-च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कारखाने की उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट मैसूर राज्य के ऐसे क्षेत्रों में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं है, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए, उक्त कारखाने को, उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजकों के विशेष अभिदाय के संदाय से, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या तब तक के लिए जब तक उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते, जो भी पहले हो, एतद्द्वारा छूट देती है।

अनुसूची

क्रम सं०	जिले का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
	प्राइवेट कारखाने		
1	मंगलोर	नीरमार्ग	मैसर्स नेरिया टिम्बर इण्डस्ट्रीज, नीरमार्ग मंगलोर।
2	यथोक्त	यथोक्त	मैसर्स फिमको सा मिल्ज एण्ड इण्डस्ट्रीज नीरमार्ग, मंगलोर।
3	बंगलोर	डोडा कालासंदरा	मैसर्स हेजडे और गोले (प्राइवेट) लिमिटेड, 8-माइलस्टोन, कनकपुरा रोड़, थालाधाट्टापुर, बंगलोर।
4	गुलबर्ग	नारायणपुर	मैसर्स छाया आर० सी० पाइप्स, डाकखाना नारायणपुर तालुक शोरापुर जिला गुलबर्ग।
5	बंगलोर	विस्वानीदम डाकखाना	मैसर्स कोर कार्ड कंटेनर्ज, 7 मिली, मागादी रोड़, विस्वानीदम डाकखाना बंगलौर-23.
6	हसन	एलूर	मैसर्स गयाधरी मैच फैक्टरी, एलुर जिला हस्सन।
7	बंगलोर	डोडा कालासंदरा ग्राम	मैसर्स बिट तल (प्राइवेट) लिमिटेड श्री शीला, 8-माइल स्टोन डोडाकालासंदरा ग्राम, कनकपुर रोड़ बंगलोर-11.
8	शिमोगा	सागर	मैसर्स गजानन मोटर ट्रांस्पोर्ट कम्पनी लिमिटेड, सागर।
9	बंगलोर	बंगलोर	मैसर्स बंगाल इलेक्ट्रिक लैम्प वर्कस लिमिटेड, 13-माइल, ओल्ड मद्रास रोड़, मगलोर-36
10	मैसूर	हसनपुर	मैसर्स जोधी स्माल इंडस्ट्री, बी० एम० रोड, हनसूर।
11	हस्सन	होलेनारासीपुर	मैसर्स इंदिरा मैच इण्डस्ट्रीज, होलेनारासीपुर, जिला हस्सन।
12	हस्सन	मनचलाहाली	मैसर्स सिवाकासी मैच फैक्ट्री, मनचलाहाली ग्राम, बेलूर रोड, हस्सन।
13	मैसूर	बदनावाल	मैसर्स बदनावाल खादी और ग्रामोद्योग संध, बदनावाल, जिला मैसूर।
14	मंगलोर	बेलीनेला	मैसर्स इण्डियन प्लाईवुड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी बैलिनेला सुब्रामण्या रोड स्टेशन, डाकखाना नेताना एस के०।
15	बलगाम	माच्ची	मैसर्स मेधदूत सीमेन्ट पाइप इंडस्ट्रीज, माच्ची, डाकखाना बेलगाम।
16	धारवार	जकनुर	मैसर्स जकनूर आगरी लिमिटेड, जकनूर, डाकखाना जामाखांडी।
17	तुमकुर	तुमकुर	मैसर्स प्रकाश फर्नीचर वर्क्स और सामिलूज नायर इलैक्ट्रिक कालोनी, तुमकुर।

(1)	(2)	(3)	(4)
	पब्लिक कारखाने		
1	कोलार	चिकाबालापुर	मैसर्स स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन डिपो/वर्कशाप, चिकाबालापुर।
2	मंगलौर	पानमबुर	कार्यपालिका इंजीनियरी, यांत्रिक प्रभाग, मंगलोर हारबर प्रयोजना, पानमबुर एस० के०
3	धारवार	ऐनीगेरे	मैसर्स राज्य बिजली बोर्ड, ऐनीगेरे।
4	धारवार	कालघाटगी	मैसर्स राज्य विद्युत बोर्ड, कालघाटगी।
5	तुमकुर	तुमकुर	मैसर्स स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट, कारपोरेशन डिपो, बस अड्डा, तुमकुर।

[संख्या फा० एस० 38014(3)/71—एच० आई०]

S.O.2033:—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees, State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S. O. 2970 dated the 17th July, 1971 the Central Government having regard to the location of the factories specified in column (4) of the Schedule hereto annexed in areas specified in column (3) of the said Schedule in the State of Uttar Pradesh in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are not in force, hereby, exempts the said factories from the payment of employers special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year from the data of expiry of the period specified in the said notification or until the enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of District	Name of the area	Name of the factory
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bahraich	Nanpara.	M/s. Hanuman Rice and Dall Mills.
2.	Meerut	Hastinapur.	1. M/s. Madan Industries, P.O. Hastinapur. 2. M/s. Vulcanised Fibre Factory, Industrial Area Hastinapur.
3.	Muzaffar Nagar	Shamli.	M/s. Aurvindo Syringes, Thinjore Road.
4.	Varanasi	Industrial Estate.	1. M/s. Hem Electric Manufacturing Company, 28 Nandan Shah. 2. M/s. Meghdoot Engineering Industries. 3. M/s. Malleable and Alloys Industries. 4. M/s. Bharat Metal Industries. 5. M/s. Sukhdeo Udy of B-5 Industrial Estate.

[No. F. S. 38017/10/72-HI]

का० आ० 2033—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 2970 तारीख 17 जुलाई, 1971 के क्रम में केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कारखानों की उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे क्षेत्रों में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं है, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखानों को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के सन्दाय से, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या तब तक के लिए जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते, जो भी पहले हो, उसके लिए, एतद्द्वारा छूट देती है।

अनुसूची

क्रम सं०	जिले का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	बहराइच	नानपाड़ा	मैसर्स हनुमान राइस एण्ड दाल मिल्स।

(1)	(2)	(3)	(4)
2	मेरठ	हस्तिनापुर	1. मैसर्स मदन इंडस्ट्रीज, पोस्ट आफिस हस्तिनापुर। 2. मैसर्स बलकेनाइज्ड फाइबर फैक्टरी, इंडस्ट्रियल एरिया हस्तिनापुर।
3	मुजफ्फरनगर	शामली	मैसर्स अरविन्दो सिरिंज, पिंजोर रोड,
4	वाराणसी	इंडस्ट्रियल एस्टेट	1. मैसर्स हेम इलेक्ट्रिक मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी, 28, नन्दन शाह। 2. मैसर्स मेघदूत इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। 3. मैसर्स मैलीएबल एण्ड एलायज इंडस्ट्रीज। 4. मैसर्स भारत मेटल इंडस्ट्रीज 5. मैसर्स सुखदेव उदी, बी–5, इंडस्टियल एस्टेट।

[संख्या फा० एस० 38017(10)/72–एच० आई०]

S.O. 2034.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), an in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 5309 dated the 4th November, 1971 the Central Government, having regard to the location of the factories specified in column (4) of the Schedule here to annexed in areas specified in column (3) of the said Schedule in the State of Punjab in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are not inforce, hereby exempts the said factories from the payment of employers' special contri bution leviable under chapter VA of the said Act for a further period of one year with effect from the date of expriy of the period specified in the said notification upto and inclusive of the 4th July, 1972 or until the enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of District	Name of Area	Name of the factory
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Amritsar	Gandasingh Wala (Village.)	Messrs Modela Private Limited Majitha Road.
2.	Ludhiana	Samrala	Messrs Aggarwal Oil Mills Chandigarh Road.
3.	Hoosiarpu	Samundra	Messrs Balram Engineering Works.

[No. F. S-38017(8)/72-HI]

का० आ० 2034.–कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73–च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 5309 तारीख 4 नवम्बर, 1971 के क्रम में केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कारखाने की, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट पंजाब राज्य के ऐसे क्षेत्रों में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं है, अवस्थति को ध्यान में रखते हुए, उक्त कारखाने को, उक्त अधिनयिम के अध्याय 5–क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजकों के विशेष अभिदाय के सन्दाय से उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान की तारीख से 4 जूलाई 1972 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की अवधि के लिए या तब तक के लिए जब तक उक्त अधिनियम के अध्याय 5–के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते, जो भी पहले हो, एतद्द्वारा छूट देती है।

अनुसूची

क्रम सं०	जिलों का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अमृतसर	गंडासिंह वाला (गाँव)	मैसर्स मोडेला प्राइवेट लिमिटेड, मजिठा रोड।
2	लुधियाना	समराला	मैसर्स अग्रवाल आयल मिल्स, चण्डीगढ़ रोड।
3	होशियारपुर	समुन्द्रा	मैसर्स बलराम इंजिनीयरिंग वर्क्स।

[सं० फा० एस०–38017(8)/72–एच० आई०]

S.O.2035.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2971 dated the 17th July, 1971 the Central Government, having regard to the location of the factories specified in column (4) of the Schedule hereto annexed in areas specified in colmn (3) of the said Schedule in the State of Uttar Pradesh in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are not in force hereby exempts the said factories from the payment of employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year from the date of expiry of the period specified in the said notification or until the enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of District	Ne of Area	Name of the factory
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bulandshar	Uncha Gaon . . .	Messrs Agro Industries.
2.	Muzaffarnagar	Gangarampura . . .	Messrs Government Blanket Factory.

[No. F. S-38017/10/72-HI]

का०आ० 2035.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का०आ० 2971 तारीख 17 जुलाई, 1971 के क्रम में केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कारखानों की उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे क्षेत्रों में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं है, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखानों को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशिष अभिदाय के संदाय से, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या तब तक के लिए जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते, जो भी तहले हो उसके लिए, एतद्द्वारा छूट देती है।

अनुसूची

क्रम सं०	जिले का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	बुलन्द शहर	ऊँचा गाँव	मैसर्स एग्रो इंडस्ट्रीज.
2	मुजफ्फरनगर	गंगारामपुरा	मैसर्स गवर्नमेन्ट ब्लैकिट फैक्टरी।

[संख्या फा० एस० 38017(10)/72-एच० आई०]

New Dehli, the 24th June, 1972

S.O. 2036.—In exercise of the powers onferred by Section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 297 dated the 17th July, 1971 the Central Government, having regard to the location of the factories specified in column (4) of the Schedule hereto annexed in areas specified in column (3) of the said Schedule in the State of Uttar Pradesh in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are not in force, hereby exempts the said factories from the payment of employers' special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year from the date of expiry of the period specified in the said notification or until the enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

SCHEDULE

Serial No.	Name of District	Name of area	Name of the factory
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mathura	Vindraban Udyognagar . .	1. Messrs Sindia Ceramic and Synthetic Industries. 2. Messrs Raman Engineering Industries.

[No. F.S. 38017(10)/72—HI]

नई दिल्ली, 24 जून, 1972

का० आ० 2036.–कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73 च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 2972 तारीख 17 जुलाई, 1971 के क्रम में केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कारखानों को उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे क्षेत्रों में, जिसमें में उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 उपाबद्ध प्रवृत्त नहीं हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखानों को उक्त अधिनियम के अध्याय 5–क के उद्ग्रीह्य नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि समाप्ती की तारीख से एक वर्ष की अवधि की लिए या तब तक के लिए जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपाबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते, जो भी पहले हो उसके लिए, एतदद्वारा छूट देती है।

अनुसूची

क्रम संख्या	जिले का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मथुरा	वृन्दावन उद्योग नगर	1. मैसर्स सिंधिया सेरामिक एण्ड सेन्थेटिक इंडस्ट्रीज 2. मैसर्स रमन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज।

[सं० फा एस० –38017(10)/70–एच० आई०]

S.O. 2037.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1142 dated the 22nd February, 1971 the Central Government, having regard to the location of the factories specified in column (4) of the Schedule hereto annexed in areas specified in col. (3) of the said schedule in the State of Rajasthan in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are not in force, hereby exempts the said factories from the payment of employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year from the date of expiry of the period specified in the said notification in the Official Gazette or until the enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

SCHEDULE

Serial No.	Name of District	Name of Area	Name of the factory
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dungerpur	Sagwara	Rajasthan State Electricity Board, Sagwara.
2.	Jhalawar	Jhalra Patan	Water Works, Jhalra Patan.
3.	Chittorgarh	Bengu	Raj Engineering Works, Bengu.

[No. F S. 38017(58)/72-HI]

का० आ० 2037.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73 च प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 1142 तारीख 22 फरवरी, 1971 के क्रम में केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 4 में विदिष्ट कारखानों की उक्त अनुसूची के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट राजस्थान राज्य के ऐसे क्षेत्रों में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रथवृत्त नहीं हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए, उक्त कारखानों को उक्त अधिनियम अध्याय 5 क के अधीन उद्ग्रीहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से, राजपत्र में उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अविधि की समाप्ति की तारीख से एक वर्ष की और अवधि के लिए या तब तक के लिए जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते, इनमें से जो भी पहले हो, उसके लिए, एतदद्वारा छूट देती है।

अनुसूची

क्रम संख्या	जिले का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	डूंगरपुर	सगवारा	राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सगवारा।
2	झालावाड़	झालरा पाटन	वाटर वर्क्स, झालरा पाटन
3	चित्तौड़गढ़	बेंगू	राज इंजीनियरिंग वर्क्सा, बेंगू।

[सं० एस० 38017(58)/72-एच०आई०]

New Delhi, the 26th June, 1972

S.O. 2038.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2782, dated the 5th July, 1971, the Central Government, having regard to the location of the factories specified in column (4) of the Schedule hereto annexed in areas specified in column (3) of the said Schedule in the State of Bihar in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are not in force, hereby exempts the said factories from the payment of employers special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year from the date of expiry of the period specified in the said notification or until the enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of District	Name of Areas	Name of factory
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bhagalpur	Sultanganj	Messrs Hanuman Oil Mills.
2.	Muzaffarpur	Dighra	(*i*) Messrs Muzaffarpur Rereolling Mills, R.K. Ashram. (*ii*) Messrs Ratan Aluminium Works Industries R.K. Ashram.
3.	Santhal Pargana	Bandarjori	Messrs Saw Mills cum Depot Forest Department.
4.	Singhbhum	Chandil	Messrs Ratan Lal and Company Shellac Factory.

[No. F. S-38017(1)/71—HI]

नई दिल्ली, 26 जून, 1972

का० आ० 2033.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73 च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 2782 तारीख 5 जुलाई, के क्रम में केन्द्रीय सरकार इससे उपाबन्ध अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कारखानों की, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट बिहार बिहार के राज्य के ऐसे क्षेत्रों में जिनमें अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपाबन्ध प्रवृत्त नहीं है, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखानों को उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के अधीन उदग्रीहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के दाय से, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति समाप्ति की तारीख से एक और वर्ष की अवधि के लिए या तब तक के लिए जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते इनमें से जो भी पहले हो उसके लिए, एतदद्वारा छूट देती है।

अनुसूची

क्रम संख्या	जिले का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	भागलपुर	सलतान गंज	मैसर्स हनुमान आयल मिल्स ।
2	मुज्जफरपुर	दीधरा	(1) मैसर्स मुज्जफरपुर रीरोलिंग मिल्स आर० के आश्रम (2) मैसर्स रतन ऐलमीनियम वर्क्स इंडस्ट्रीज, आर० के० आश्रम ।
3	संथाल परगना	बंदरजोरी	मैसर्स सामिल्स कम डिपो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट ।
4	सिंहभूमि	चण्डील	मैसर्स रतन लाल एण्ड कम्पनी, शिलौक फैक्ट्री ।

[सं० फा एस० 38017(1)/71-एच० आई०]

S.O. 2039.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2966 dated the 17th July, 1971 the Central Government, having regard to the location of the factories specified in column (4) of the Schedule hereto annexed in areas specified in column (3) of the said Schedule in the State of Uttar Pradesh in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are not in force, hereby exempts the said factories from the payment of employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year from the date of expiry of the period specified in the said notification or until the enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of District	Name of Area	Name of the factory.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Azamgarh	Azamgarh	Doharighat Pumped Canal.
2.	Bulandsher	Chipyana	Chhabra Rolling and General Mills, P.O. Chipyana, Bulandsher Road, Ghaziabad.
3.	Allahabad	Mau Aima	Mau Aima Sizing Works, P.O. Mau Aima, Allahabad.
4.	Meerut	Barnawa Road Near City Station.	Metal Febs, Barnawa Road, Near City Station Meerut.
		Delhi Road, Meerut	Meessrs International Rubber Works.
		Ramlila Ground, Meerut	Messrs Engineering Corporation of India.
		Sardhana Road, Near Meerut Cantt. Railway Station.	Messrs Saru Smelting Refining Corporation.

[F. No. S. 38017(10)/72-HI]

का० आ० 2039.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 2966 तारीख 17 जुलाई, 1972 के क्रम में केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट कारखानों की उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे क्षेत्रों में जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखानों को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उदग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या तब तक के लिए जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते, जो भी पहले हो उसके लिए एतद्द्वारा छूट देती है

अनुसूची

क्रम संख्या	जिले का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आजमगढ़	आजमगढ़	दोहरीघाट पावर कनाल
2	बुलन्द शहर	छिपियाना	छावरा रोलिंग एण्ड जनरल मिल्स पोस्ट आफिस, छिपियाना, बुलन्दशहर, रोड़, गाजियाबाद
3	इलाहाबाद	मऊआइमा	मऊआइमा साइजिंग वर्क्स, पोस्ट आफिस, माऊआइमा, इलाहाबाद
4	मेरठ	बरनावारोड़, सिटी स्टेशन, के निकट	मेटल फार्म्स, बरनावा रोड़, सिटी स्टेशन के निकट
		दिल्ली रोड़, मेरठ	मसर्स इन्टरनेशनल रबर वर्क्स,
		रामलीला ग्राउंड मेरठ	मसर्स इंजिनियरिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया
		सरधनारोड़, मेरठ कैण्ट रेलवे स्टेशन के निकट	मैसर्स सरु स्मेलटिंग रिफाइनिंग कारपोरेशन

[सं० फा० एस०-38017 (10)/72-एस० आई०]

S.O. 2040—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation, (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1143 dated the 22nd February, 1971 the Central Government, having regard to the location of the factories specified in column (4) of the Schedule hereto annexed in areas specified in column (3) of the said Schedule in the State of Uttar Pradesh in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are not in force, hereby exempts the said factories from the payment of employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year from the date of expiry of the period specified in the said notification or until the enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

SCHEDULE

Serial No	Name of District	Name of Area	Name of the factory
1	2	3	4
1	Agra	Peera Khar	Messers Agra Steel Corporation.
2	Etah	Kasaganj	Messrs Tayal Steel Rolling Mls, Saron Gate.
3	Gonda	Bahraich Road	Messers. Awadh Ply Wood.
4	Meerut	Partapur	Messrs. Star Rubbers Private Limited, A-4, In- Estate.
5	Muzaffar Nagar	Partapur	Messrs Mulop Foundries Private Limited, Industrial Estate.

(No.S-38017(34)/72-H.I)

का० आ० 2040—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम और रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 1143 तारीख 22 फरवरी, 1971 के क्रम में केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट कारखानों की उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे क्षेत्रों में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं है, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखानों को उक्त अधिनियम के अध्याय 5क के अधीन अंशदायीय नियोजक के विशेष आभदाय के संदाय से उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ती की तारीख से एक वर्ष का और अवधि के लिए या तब तक के लिए जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते, जो भी पहले हो, एतद्द्वारा छूट देती है।

अनुसूची

क्रम संख्या	जिले का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आगरा	पीरा खर	मैसर्स आगरा स्टील कारपोशन
2	एटा	कासगज	मैसर्स तायल स्टील रोलिग मिल्स, सरी गेट
3	गौंडा	बहराइच रोड़	मैसर्स अवध स्लाईवड
4	मेरठ	परतापुर	मैसर्स स्टार रबर प्राइवेट लिमिटेड ए-4, इडास्ट्रयल एस्टेट
5	मुज्जफर नगर	परतापुर	मैसर्स म्यलाप फाउंड्रोज प्राइवेट लिमिटे, इडस्ट्रियल एस्टेट

[सं० फा० एस-38017(34)/72-एच आई]

S.O. 2041.—In exercise of the powers conferred by section 79F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 3052 dated the 31st July, 1971, the Central Government, having regard to the location of the factories specified in column (4) of the Schedule hereto annexed in areas specified in column (3) of the said Schedule in the State of Bihar in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are not in force, hereby exempts the said factories from the payment of employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year from the 31st May, 1972 upto and inclusive of the 30th May, 1973 or until the enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

SCHEDULE

S. No.	Name of District	Name of Area	Name of factory
1	2	3	4
1	Bhagalpur	Barahgama Sultanganj	Messrs Ajanta Stone Works at Barahgama, Amarpur Messrs Bihar Khadi Gramodhog Sang, Saranjain Karavalaya.
2	Champaran	Sagauli	Messrs Bajrang Saw Mitl, Post Sagauli.
3	Dhanbad	Govindpur Mohuda	Messrs Laxmi Steel Industries, Post Office, Govindpur Messrs Bihar Cement Products.
4	Hazaribagh	Hirodih	Messrs Gayday Iron Steel Company Limited, Post Office Hirodih.
5	Mongayr	Sheikhpura	Messrs Chandi Birdaban Stone Works, Station Road.
6	Patna	Bikram Biharsharif	Messrs Foot Wear Factory, Post Office Bikram. Messrs Vividh Engineering Works.
7	Shahbad	Mohania	Messrs Agarwal and Company.

(No.S-38017(38)/72-HI)

DALJIT SINGH, Under Secy.

का० आ० 2041—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73 च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 3052 तारीख 31 जुलाई, 1971 के क्रम में केन्द्रीय सेरकार इससे पाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट कारखानों में की उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट बिहार राज्य के ऐसे क्षेत्रों में जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं हैं, अवस्थिति को ध्यान मे रखते हुए, उक्त कारखानों को उक्त अधिनियम के अध्याय 5 क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से 31 मई, 1972 से 30 मई, 1973 तक, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए या तब तक के लिए जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते, इनमें से जो भी पहले हो उसके लिए, एतदद्वारा छूट देती है ।

अनुसूची

क्रम संख्या	जिले का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	भागलपुर	बराहगामा	मैसर्स अजन्ता स्टोन वर्क्स, बराहगामा, अमरपुर
		सुल्तानगंज	मैसर्स बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ, संरजन कार्यालय
2	चम्पारन	सगौली	मैसर्स बजरंग सा मिल, डाकघर, सगौली
3	धनबाद	गोबिन्दपुर	मैसर्स लक्ष्मी स्टील इंडस्ट्रीज, डाकघर, गोबिंदपुर
		मोहदा	मैसर्स बिहार सीमेन्ट प्राडक्टस
4	हजारीबाग	हिरोडीह	मैसर्स गे डे आयरन स्टील कम्पनी लिमिटेड, डाकघर, हिरोडीह
5	मुंगेर	शेखपुरा	मैसर्स चण्डी बिरवाबम स्टोन वर्क्स, स्टेशन रोड
6	पटना	बिक्रम	मैसर्स फ्रूट बियर फैक्टरी, डाकघर, बिक्रम
		बिहार शरीफ	मैसर्स विविध इंजीनियरिंग वर्क्स
	[illegible] ;	मोहनिया	मैसर्स अग्रवाल एण्ड कम्पनी

[सं० का० एस-38017(38)/72-एफ० आई०]

दलजीत सिंह अवर सचिव।

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 18th May, 1972

S.O. 2642.—An account of all sums received into and paid out of the Personal Injuries (Compensation Insurance) Fund for the year 1970-71 is hereby published in the prescribed form:—

Account of sums received into and paid out of the Personal Injuries (Compensation Insurance) Fund during the year ending 31st March, 1971.

RECEIPTS.			EXPENDITURE.		
	Amount	Progress of receipts upto the end of 1970-71.		Amount	Progress of expenditure upto the end of 1970-1971.
1	2	3	4	5	6
	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.
1. Advances of premium.	6,299·13	70,93,635·33	1. Compensation under the Personal Injuries (Compensation Insurance) Scheme.	..	..
2. Advances from General Revenues under Section 12(3).	..	..	2. Remuneration and expensions of Government Agents of and cost of forms.	39,425·00	5,43,559·84

1	2	3	4	5	6
3. Miscellaneous Receipts .	..	..	3. Expenses of the staff employed to do the work in the States and at the Headquarters of the Central Government. . .	..	56,390·12
			4. Expenses of the additional staff employed to cope with the audit and accounting arrangements.	..	..
			5. Repayments of advances made under Clause 12 of the Personal Injuries (Compensation Insurance) Scheme. . .	..	..
			6. Miscellaneous Expenditure (showing details if necessary.		
	6,299·13	70,93,635·33		39,425·00	5,99,949·96

[No. S-19019(1)/72-FAC]

LALFAK ZUALA, Under Secy.

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 18 मई, 1972

का० आ० 2042.—शारीरिक क्षति (प्रतिकर बीमा) निधि में प्राप्त और उससे प्रदत्त सभी रकमों का 1970-71 वर्ष के लिए लेखा एतद्द्वारा विहित प्रपत्र में प्रकाशित किया जाता है :—

शारीरिक क्षति (प्रतिकर बीमा) निधि में 31 मार्च, 1971 के समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान प्राप्त और उसमें से प्रदत्त रकमों का लेखा ।

प्राप्तियां			व्यय		
	रकम	1970–71 के अन्त तक प्राप्तियों की प्रगति		रकम	1970–71 के अन्त तक व्यय की प्रगति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	रु०	रु०		रु०	रु०
1. प्रिमियम का उधार	6,299.13	70,93,635.33	(1) शारीरिक क्षति (प्रतिकर बीमा) स्कीम के अधीन प्रतिकर ।	—	—
2. धारा 12–(3) के अधीन साधारण राजस्व से उधार	—	—	(2) सरकारी अभिकर्ता के पारिश्रमिक और व्यय और प्रपत्रों पर खर्च ।	39,425.00	5,43,559.84
3. प्रकीर्ण प्राप्तियां	—	—	(3) राज्यों में और केन्द्रीय सरकार के मुख्यालय में काम करने के लिए नियोजित कर्मचारीवृन्द का व्यय ।	—	56,390.12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	रु०	रु०		रु०	रु०
			(4) लेखा परीक्षा और लेखा-व्यवस्थाओं का काम चलाने के लिए नियोजित अतिरिक्त कर्मचारीवृन्द का व्यय ।	—	—
			(5) शारीरिक क्षति (प्रतिकर बीमा) स्कीम के खण्ड 12 के अधीन दिए गए उधारों की वापसी अदायगियां ।	—	—
			(6) प्रकीर्ण व्यय (आवश्यक हो तो विवरण दर्शाते हुए) ।	—	—
	6,299.13	70,93,635.33		39,425.00	5,99,949.96

[सं० एस-19019(1)/72-फैक०]

लालफ़क जोला, अवर सचिव ।

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 19th May 1972

S.O. 2043.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 8 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962, namely:—

1. This Rule may be called the Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Rules, 1972.

2. In the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962, to sub-rule (3), of rule 7 the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that the decision of the Board on any question may also be considered if the Chairman so directs, by circulation of the necessary papers to every member of the Board and if there is no unanimity of decision on any question in circulation, the said question shall be placed before the Board for its decision."

[No. F. S-65012/2/71-P&D.]

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 19 मई, 1972

का०आ० 2043.—डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 8 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) नियम, 1962 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 (1) ये नियम डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन नियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

(2) डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) नियम, 1962 के नियम 7 मे, उपनियम 3 के साथ निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे तो किसी भी प्रश्न पर बोर्ड के विनिश्चय पर बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को आवश्यक कागजात के परिचालन द्वारा विचार किया जा सकता है और यदि परिचालन में के किसी प्रश्न पर विनिश्चय एक मत से न हो तो उक्त प्रश्न को बोर्ड के सामने उसके विनिश्चय के लिए रखा जाएगा ।

[संख्या एस-65012(2)/71-पी०एंड डी०]

New Delhi, the 24th May 1972

S.O. .—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 5A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of

1948), the Central Government hereby appoints Shri C. R. Govindarajan, General Manager, Madras Port Trust, as a member of the Madras Dock Labour Board for a period of 31 days with effect from the 11th May, 1972 to the 10th June, 1972, *vice* Shri R. Balasubramanian proceeded on leave and makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 169(E), dated the 25th February, 1972, namely:—

In the said Notification,—

(1) under the heading "Members representing the Central Government", in item (1), for the words "Shri R. Balasubramanian, Chairman, Madras Post Trust", the words "Shri C. R. Govindarajan, General Manager, Madras Port Trust", shall be substituted;

(2) in paragraph 2, for the words "Shri R. Balasubramanian", the words "Shri C. R. Govindarajan", shall be substituted;

[No. F.54/5/69-Fac.II/P&D.]

O. P. TALWAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 24 मई, 1972

का०आ० 2044.—डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 5-क की उपधाराओं (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री सी० आर० गोविन्दराजन, महा प्रबंधक, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट, को श्री आर० बालासुब्रामणियन, जो छुट्टी पर गए हैं, के स्थान पर 11 मई, 1972 से 11 जून, 1972 तक 31 दिन की अवधि के लिए ; मद्रास डाक श्रम बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 169(ई०), तारीख 25 फरवरी, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में :—

(1) मद (1) में शीर्षक "केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य" के अन्तर्गत "श्री आर० बालासुब्रामणियन, अध्यक्ष, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट," शब्दों के स्थान पर "श्री सी० आर० गोविन्दराजन, महाप्रबंधक, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

(2) पैरा 2 में "श्री आर० बालासुब्रामणियन" शब्दों के स्थान पर "श्री सी० आर० गोविन्दराजन" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे

[संख्या फा० 54/5/69-फैक०-2/पी० एंड डी०]

ओ० पी० तलवाड़, उप सचिव ।

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 10th May 1972

S.O. 2045.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 27 of the Payment of Bonus Act, 1965 (21 of 1965), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1870 dated the 1st May, 1969, namely:—

In the Table attached to the said notification (i) in the entries against item III, in column 2, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"The States of West Bengal (Excluding the Districts of Burdwan, Birbhum and Purulia) Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Tripura and the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands and Arunachal Pradesh.";

(ii) in the entries against item IV, in column 2 for the existing entries, the following entries shall be substituted namely:—

"The States of Tamil Nadu and Kerala and the Union territories of Pondicherry and Laccadive Minicoy and Amindive Islands";

(iii) in the entries against item VI, in column 2 for the existing entries, the following entries shall be substituted; namely:—

"The States of Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir and the Union territories of Delhi and Chandigarh.";

(iv) in the entries against item VII, in column 2, the words "excluding Singhbhum District" shall be omitted;

(v) in the entries against item XI, in column 2, the words "and Singhbhum District of Bihar" shall be omitted.

[No. S.33012/18/71-WB.]

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 10 मई, 1972

का० आ० 2045.—बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (1965 का 21) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना स० का० आ० 1870 तारीख 1 मई, 1969 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी में—

(i) मद III के सामने की प्रविष्टियों में, स्तंभ 2 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"पश्चिमी बंगाल (बर्दवान, बीरभूम और पुरुलिया जिलों को छोड़कर), असम, मेघालय, नागालैंड मणिपुर, त्रिपुरा राज्य और अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र ।"

(ii) मद IV के सामने की प्रविष्टियों में, स्तंभ 2 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"तमिल नाडु और केरल राज्य तथा पांडीचेरी और लंकाद्वीप, मिनिकोय और अमिनदीवद्वीपसमूह;

(iii) मद VI के सामने की प्रविष्टियों में, स्तभ 2 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर राज्य तथा दिल्ली और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र ;",

(iv) मद VII के सामने की प्रविष्टियों में, स्तंभ 2 में, "सिंहभूम जिले को छोड़कर" शब्द लुप्त हो जाएंगे ;

(v) मद XI के सामने की प्रविष्टियों में, स्तभ 2 में, "और बिहार का सिंहभूम जिला" शब्द लुप्त हो जाएंगे ।

[सं० एस०-33012/18/71-डब्ल्यू० बी०]

New Delhi, the 3rd June 1972

S.O. 2046.—Whereas the Central Government is of opinion that the minimum rates of wages should be fixed under the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) in respect of employment in Graphite Mines covered under the Mines Act, 1952 (35 of 1952).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 27 of the said Act, and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. 3409 dated the 4th August, 1971, the Central Government hereby gives notice of its intention to add the said employment in Part I of the Schedule to the said Act.

Any suggestions or objections which may be received from any person in respect of the said addition before the expiry of four months from the date of its publication in the official Gazette, will be considered by the Central Government.

[No. LWI-I-2(23)/67-WE(MW).]

नई दिल्ली, 3 जून 1972

का० आ० 2046.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के अन्तर्गत आने वाली ग्रेफाईट खानों में नियोजन के बारे में मजदूरी की न्यूनतम दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन नियत की जाने चाहिए ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 3409 तारीख 4 अगस्त, 1971 को अधिक्रांत करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग 1 में उक्त नियोजन को जोड़ने के अपने आशय की सूचना, एतद्द्वारा देती है ।

उक्त जोड़ने के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4 मास की समाप्ति से पूर्व प्राप्त सुझावों या आक्षेपों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

[सं० एल डब्ल्यू आई-1/2(23)/67-डब्ल्यू ई (एमडब्लू)]

S.O. 2047.—Whereas the Central Government is of opinion that the minimum rates of wages should be fixed under the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) in respect of employment in Silica Mines covered under the Mines Act, 1952 (35 of 1952).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 27 of the said Act, and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) Nos. S.O. 858 dated the 20th January, 1971 and S.O. 3697 dated the 14th September, 1971, the Central Government hereby gives notice of its intention to add the said employment in Part I of the Schedule to the said Act.

Any suggestions or objections which may be received from any person in respect of the said addition before the expiry of four months from the date of its publication in the official Gazette, will be considered by the Central Government.

[No. LWI.I-2(34)/67-WE(MW).]

का० आ० 2047.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के अन्तर्गत आने वाली सिलीका खानों में नियोजन की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन नियत की जानी चाहिए ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 858 तारीख 20 जनवरी, 1971 और का० आ० 3897 तारीख 14 सितम्बर, 1971 को अधिक्रांत करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग 1 में उक्त नियोजन को जोड़ने के अपने आशय की सूचना देती है ।

उक्त जोड़ने के बारे में किसी व्यक्ति से जो आक्षेप या सुझाव इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4 मास समाप्त होने के पूर्व प्राप्त होंगे उन पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी ।

सं० एल डब्ल्यू आई-1/2(34)/67-डब्ल्यू ई (एम डब्ल्यू)

New Delhi, the 24th June 1972

S.O. 2048.—The following proposals made by the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 3, read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), for fixing the minimum rates of wages as specified in column 2 of the Schedule, annexed hereto, payable to the categories of the employees employed in employments in China Clay, Clay and White Clay Mines, as specified in the corresponding entries in column 1 of the said Schedule, are hereby published, as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said proposals will be considered after the expiry of three months from the date of the publication of this notification in the Gazette of India.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said proposals before the said period will be duly considered by the Central Government.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
1	2
China Clay, Clay and White Clay Mines	
	Rs. P.
Unskilled	
Mazdoor (Male and Female), Loader, Sweeper, Cleaner, Chowkidar, Coollie, Earth cutter, Khalasi, other categories by whatever name called which are unskilled.	3·50 per day
Semi-skilled or unskilled supervisory	
Mukadams, Mate, Cook, Oilman, Pump-khalasi, Attendant, Miner Priest, Gardner, Helper, Supervisory fireman, Breaker, Head chowkidar, Creche Aya, Non-matriculate clerical employee, other categories by whatever name called which are semi-skilled.	4·65 per day
Skilled .	
Blacksmith, Carpenter, Tailor, Mason, Electrician, Geologist, Mine supervisor, Driver, Pump operator or Driver, Clay press or drying and refining workers, Supervisor Foreman, other categories by whatever name called which are skilled.	7·00 per day
Clerical	
Cashier, Accountant, Clerk, Timekeeper, Store keeper, Store attendant, Record keeper, Register keeper, Munshi, Typist, Steno, other categories by whatever name called which are clerical.	7·00 per day

Explanation

1. (a) *Unskilled* work is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job.

(b) *Semi-skilled* work is one which involves some degree of skill or competence required through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of skilled employee, and includes unskilled supervisory work.

(c) *Skilled* work is one which involves skill of competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice or in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

2. The minimum rates of wages are all inclusive rates and include also the wages for weekly day of rest.

3. Where essential commodities at concessional rates are supplied to employees, the exmployers may, if they so desire, approac h the Central Government to get the cash value of the concessions duly computed by the competent authority.

[No. S-32019(5)/72-WE(MW)]

HANS RAJ CHHABRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 जून 1972

का० आ० 2048.—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 में यथाविनिर्दिष्ट उन मजदूरियों की न्यूनतम दरें नियत करने के लिए, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 1 में तत्संबन्धी प्रविष्टियों में यथा विनिर्दिष्ट चीनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी और श्वेत मिट्टी खानों के नियोजनों में नियोजित कर्मचारी प्रवर्गों को संदेय हैं, किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा यथा अपेक्षित, उनसे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावों पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन मास की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

उक्त प्रस्तावों के संबन्ध में किसी भी व्यक्ति से उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त होने वाले आक्षेपों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया जाएगा ।

अनुसूची

काम का वर्गीकरण	प्रति दिन मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2
चीनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी और श्वेत मिट्टी खानें	
	रु० पै० प्रतिदिन
अकुशल :	
मजदूर (पुरुष और नारी) लोडर, झाड़ूकश, क्लीनर, चौकीदार, कुली, भूमि काटने वाला, खलासी किसी भी नाम से कहलाने वाले अन्य ऐसे प्रवर्ग, जो अकुशल किस्म के हैं।	3.50

1	2
	रु० पै०
अर्धकुशल या अकुशल पर्यवेक्षकीय	
मुकादम, मेट, रसोइया, आयल मैन, पम्प खलासी, परिचर, खनिक, पुजारी, माली, सहायक, पर्यवेक्षकीय फायरमैन, ब्रेकर, मुख्य चौकीदार, शिशु कक्ष आया, गैर-मैट्रिकुलेट लिपिक कर्मचारी, किसी भी नाम से कहलाने वाले अन्य प्रवर्ग, जो अर्धकुशल किस्म के हैं।	4.65
कुशल	
लोहकार, काष्ठकार, दर्जी, राजमिस्त्री, बिजली-मिस्त्री, भूविज्ञानी, खान पर्यवेक्षक, चालक, पम्प प्रचालक या चालक, चिकनी मिट्टी बदाने वाला या सुखाने वाला और परिकरण कर्मकार, पर्यवेक्षक फोरमैन, किसी भी नाम से कहलाने वाले अन्य प्रवर्ग, जो कुशल किस्म के हैं।	7.00
लिपिकीय	
रोकड़िया, लेखापाल, लिपिक, समयपाल, भंडारी, भंडार परिचर, अभिलेखपाल, रजिस्टरपाल, मुन्शी, टाइपिस्ट, आशुलिपिक, किसी भी नाम से कहलाने वाले अन्य प्रवर्ग, जो लिपिकीय हैं।	7.00

स्पष्टीकरण

(क) **अकुशल** काम वह है जिसमें साधारण संक्रियाएं अन्तर्वलित हों और जिसे करने के लिए थोड़ी सी कुशलता या अनुभव का होना या कुशलता या अनुभव का बिल्कुल ही न होना अपेक्षित हो।

(ख) **अर्धकुशल** काम वह है जिसमें कुशलता या क्षमता की कुछ मात्रा अन्तर्वलित हों, जिसे काम पर अनुभव द्वारा प्राप्त किया जाए, और जो किसी कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन में किया जा सके तथा इसमें अर्धकुशल पर्यवेक्षकीय काम सम्मिलित है।

(ग) **कुशल** काम वह है जिसमें कुशलता या क्षमता अन्तर्वलित हो, पर अनुभव द्वारा या शिशु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यवसायिक संस्थान में प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त किया जा सके और जिसके करने में पहले और विवेक बुद्धि की आवश्यकता हो।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें सर्वसमावेशी दरें हैं और इसमें विश्राम के साप्ताहिक दिन की मजदूरी भी सम्मिलित है।

3. जहां कि कर्मचारियों को आवश्यक वस्तुएं रियायती दरों पर दी जाती हैं वहां, नियोजक, यदि चाहे तो, केन्द्रीय सरकार से सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से संगणित रियायतों का नकदी मूल्य पाने के लिए कह सकता है।

[सं० एस-32019(5)/72-डब्ल्यू ई (एम डब्ल्यू)]

हंस राज छाबड़ा, अवर सचिव।

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 16th May 1972

S.O. 2049.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 83 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby exempts the following categories of persons employed by the Oil and Natural Gas Commission in the Electrologging Section of that Organisation, from the provisions of sub-sections (1) and (2) of section 30 of the said Act:—

1. Geophysicist Assistant—Senior.
2. Draftsman Grade I
3. Winchman-cum-driver
4. Truck Drivers.
5. Assistant Store Keeper.
6. Technical Bearers.
7. Khalasis.

[No. S.29014/4/72-MI.]

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 16 मई, 1972

का०आ० 2049.—खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 83 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा संगठन के इलैक्ट्रोलागिंग अनुभाग में, नियोजित व्यक्तियों के निम्नलिखित प्रवर्गों को उक्त अधिनियम की धारा 30 की उपधाराओं (1) और (2) के उपबंधों से छूट देती है :—

1. भूभौतिकीविद सहायक—ज्येष्ठ
2. नक्शानवीस श्रेणी I
3. विंचमैन एवं चालक
4. ट्रक चालक
5. सहायक भंडारी
6. तकनीकी वाहक
7. खलासी

[सं० एस० 29014(4)/72-एम०आई]

New Delhi, the 1st June 1972

S.O. 2050.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour No. S.R.O. 1135, dated the 23rd May, 1955, the Central Government hereby appoints the following medical officers of the Directorate General of Mines Safety, being qualified medical practitioners, to be certifying surgeons for the purposes of the said Act for all the mines in the whole of India:—

(1) Deputy Director of Mines Safety (Industrial Hygiene).

(2) Assistant Director of Mines Safety (Industrial Hygiene) Grade I, posted in any Zone or Region of the Directorate General of Mines Safety.

(3) Assistant Director of Mines Safety (Industrial Hygiene) Grade II, posted in any Zone or Region of the Directorate General of Mines Safety.

[No. S. 29013/4/72-MI.]

नई दिल्ली, 1 जून, 1972

का० आ० 2050—खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 11 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम मंत्रालय की तारीख 23 मई, 1955 की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 1135 को अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार खान सुरक्षा महा निदेशालय के निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों को अर्हित चिकित्सा व्यवसायी होने के कारण सम्पूर्ण भारत की सभी खानों के लिए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ एतद्द्वारा प्रमाणकर्ता सर्जन नियुक्त करती है :—

(1) खान सुरक्षा उपनिदेशक (औद्योगिक स्वास्थ्य)

(2) खान सुरक्षा सहायक निदेशक (औद्योगिक स्वास्थ्य) श्रेणी 1, जो खान सुरक्षा महानिदेशालय के किसी भी अंचल या क्षेत्र में तैनात हो।

(3) खान सुरक्षा सहायक निदेशक (औद्योगिक स्वास्थ्य श्रेणी 2, जो खान सुरक्षा महानिदेशालय के किसी भी अंचल या क्षेत्र में तैनात हो।

[सं० एस० 29013/4/72-एम० आई०]

S.O. 2051.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri B. N. Singh as Inspector of Mines subordinate to the Chief Inspector of Mines.

[No. A. 35021/2/72-MI.]

का० आ० 2051.—खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री बी० एन० सिंह को मुख्य खान निरीक्षक के अधीन खान निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या ए० 35021/2/72-एम०-1]

ORDERS

New Delhi, the 4th March 1972

S.O. 2052.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Central Bank of India and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Bombay, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of the Central Bank of India in terminating the services of Shri B. K. Shrimali, Peon-cum-Watchman at Dhulia Branch of the Bank was justified? If not, to what relief is he entitled?"

[No. L-12012/48/71-LR.III.]

आदेश

नई दिल्ली, 4 मार्च 1972

का० आ० 2052.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सैंट्रल बैंक आफ इंडिया से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निदर्शित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7—क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, सं० 2 बम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या सैंट्रल बैंक आफ इंडिया के प्रबन्ध तंत्र को बैंक के धुलिया शाखा के श्री बी० के० श्रीमाली, चपरासी-एवम्-चौकीदार, की सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित थी? यदि नहीं, तो वह किस अनुतोष का हकदार है?

[सं० एल—12012/48/71-एल० आर० III]

New Delhi, the 6th March 1972

S.O. 2053.—Whereas the employers in relation to Canara Bank and their workmen represented by the Canara Bank Employees' Union, 135, Moore Street, Madras-1 have jointly applied to the Central Government for reference of an industrial dispute that exists between them to an Industrial Tribunal in respect of the demand set forth in the said application and reproduced in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government is satisfied that the persons applying represent the majority of each party;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and sub-section (2) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Thiru K Seetharama Rao shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"(1) Whether the readjustment of salaries and emoluments of Sri P. N. Balaji, Sri K. Ratnakar and Shri A. Habib Rehman on their transfers to Chennimalai, Gangully and Palni respectively is justified. If not, to what relief these employees are entitled?

(2) Whether readjustment of salaries and emoluments of Sri U. Bhaskar Shenoy on his transfer in terms of option exercised by him under the Settlement dated the 11th August, 1967 is justified, if not, to what relief he is entitled?"

[No. L-12025/3/72-LRIII.]

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1972

का०आ० 2053.—यतः कनारा बैंक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों जिनका प्रतिनिधित्व कनारा बैंक एम्पलाईज़ यूनियन, 135 मूर स्ट्रीट, मद्रास-1, करती है, ने उस औद्योगिक विवाद को, जो आवेदन में उपवर्णित और इससे उपाबद्ध अनुसूची में उद्धृत मांग के बारे में उनके बीच विद्यमान है, एक औद्योगिक अधिकरण को निर्देशित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को संयुक्त रूप से आवेदन किया है ।

और यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि आवेदन करने वाले व्यक्ति प्रत्येक पक्ष की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं ;

अतः अब औद्योगिक विवाद; अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिस पीठासीन अधिकारी श्री थिरू के सीथाराम राव होंगे जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

1. क्या श्री पी०एन० बाला जी, श्री के० रत्नाकर और श्री ए० हबीब रहमान के क्रमशः चेन्नीमलाई, गांगुली और पालनी से उनके स्थानान्तरण पर उनके वेतनों और उपलब्धियों का पुनः समायोजन न्यायोचित है। यदि नहीं तो ये कर्मचारी किस अनुतोष के हकदार हैं।

2. क्या श्री यू० भास्कर शिनोय के, तारीख 11 अगस्त, 1967 वाले समझौते के अधीन उसके द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार उसके स्थानान्तरण पर उसके वेतन और उपलब्धियों का पुनः समायोजन न्यायोचित है। यदि नहीं तो वह किस अनुतोष के हकदार हैं ?

[सं० एल०-12025/3/72-एल० आर० II]

New Delhi, the 10th March 1972

S.O. 2054.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Central Bank of India and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication, to the Industrial Tribunal, Calcutta constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of the Central Bank of India, Calcutta in stopping from October, 1970, the payment of Daftry Allowance to Shri Sobhnath Singh No. 1, (recipient of the said allowance from November, 1966) is justified? If not, to what relief is he entitled?"

[No. L. 12012/112/71/LRIII.]

B. K. SAKSENA, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1972

का० आ० 2054.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इस के उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारेमें भारतीय सेन्ट्रल बैंक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियमम 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कलकत्ता को न्याय-निर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या अक्टूबर 1971 से श्री शोभनाथ सिंह स0 1 को (जो नवम्बर 1966 से दफ्तरी भत्ता पा रहा था) उस भत्ते का संदाय करना रोक देने का भारतीय सेन्ट्रल बैंक प्रबंधमंडल की कारवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं तो वह किस अनुतोष का हकदार है ?"

[सं० एल-12012/112/71०-एल० आर० III]

बी० के० सक्सेना, अवर सचिव

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 7th June 1972

S.O. 2055.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri J. J. Naik, Welfare Administrator-cum-Secretary under the Iron Ore Mines Labour Welfare Fund Organisation to be in Inspector of Mines subordinate to the Chief Inspector of Mines.

[No. Z/20025/8/71-M.IV.]

R. K. SRIVASTAVA, Under Secy.

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 7 जून 1972

का० आ० 2055.—खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, लौह अयस्क खान श्रम निधि संगठन के अधीन कल्याण प्रशासक एवं सचिव, श्री जे० जे० नायक को एतद्द्वारा खानों के मुख्य निरीक्षक के अधीनस्थ खान निरीक्षक नियुक्त करती है ।

[सं० जेड/20025/8/71-एम० IV]

आर० के० श्रीवास्तव, अवर सचिव

(Department of Labour and Employment)

ORDER

New Delhi, the 16th December 1971

S.O. 2056.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Shantikhani, Bellampalli Division of Singareni Collieries Company Limited, Post Office Bellampalli (Andhra Pradesh), and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri P. S. Ananth, as Presiding Officer, with headquarters at Afzal Lodge, Tilak Road, Ramkote, Hyderabad-1, and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

"Taking all the circumstances of this case into consideration is the management of Shantikhani, Bellampalli Division of Singareni Collieries Company Limited, justified in laying off without wages the following fillers of Gang Nos. 13 and 14 on the 15th and the 16th April, 1971 respectively? If not, to what relief are the said workmen entitled?

1. Shri Lingam Chandriah.
2. Shri Boddula Chandriah.
3. Shri Pasikanti Rayamalloo.
4. Shri Jamme Odeloo.
5. Shri Thotapalli Ankuloo.
6. Shri Kambala Gurvaiah.
7. Shri Chedipalli Mallaiah.
8. Shri Akkapaka Mallaiah.
9. Shri Katam P. Posham.
10. Shri Akunuri Posham.
11. Shri Buddarthi Gattaiah.
12. Shri Morapaka Lingiah.
13. Shri Erkala Rayamallu.
14. Shri Kasthuri Sammaiah.
15. Shri Bathula Rajam.
16. Shri Puttapaka Iylaiah.
17. Shri Dongeri Buchaiah.
18. Shri Edla Mallaiah.
19. Shri Kollabathula Rayamaloo.
20. Shri Kkula Venkaty.
21. Shri Bommedi Bheemaiah.
22. Shri Kasarla Mallaiah.
23. Shri Oddi Komaraiah.
24. Shri Akula Posham.
25. Shri Chinthapuri Posham.
26. Shri Gaddam Sammaiah.
27. Shri Kampalli Rajam.
28. Shri S. K. Ali.
29. Shri Mittapalli Laxmaiah.
30. Shri Sabbani Muthaiah.
31. Shri Engala Rayamalloo.
32. Shri Bejjanki Rajam.
33. Shri Kadari Madanaiah.
34. Shri Ravula Laxmaiah.
35. Shri Dwarka Prasad.
36. Shri Ande Komaraiah.
37. Shri Oddi Komaraiah.
38. Shri Pendala Rajam.
39. Shri Durgam Rajam.
40. Shri Saliganti Rajam.
41. Shri Ranga Mallaiah.
42. Shri Manda Rayalingoo.
43. Shri Kadari Madanaiah.
44. Shri Bejjanki Rajam.
45. Shri Engala Rayamaloo.
46. Shri Sabbani Muthaiah.
47. Shri Mittapalli Laxmaiah.
48. Shri S. K. Ali.
49. Shri Kampalli Rajam.
50. Shri Renelli Lingaiah.
51. Shri Ande Komaraiah.
52. Shri Perka Lingaiah.
53. Shri Jangapalli Rayaratham.
54. Shri Ankam Bondyaloo.
55. Shri Keerthi Posham.
56. Shri Gogarla Rayamalloo.
57. Shri Gaddam Sammaiah.
58. Shri Chintapuri Posham.
59. Shri Akula Posham.
60. Shri Oddi Komaraiah.
61. Shri Kasarla Mallaiah.
62. Shri Bommidi Bheemaiah.
63. Shri Akula Venkaty.
64. Shri Kollabathula Rayamloo.
65. Shri Edla Mallaiah.
66. Shri Dongari Buchaiam.
67. Shri Puttapaka Iylaiah.
68. Shri Bathula Rajam.
69. Shri Pasikauti Lingaiah.
70. Shri Kasthuri Lingaiah.
71. Shri Erkala Rayamaloo.
72. Shri Morapaka Lingaiah.
73. Shri Jaguta Posham.
74. Shri Kotipalli Lingaiah."

[No. L/2111/571-LRII.]

(श्रम और रोजगार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1971

का० आ० 2056.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड शान्तिखनी, बेलमपल्ली प्रभाग, डाकघर बेलमपल्ली (आंध्र प्रदेश) से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके

पीठासीन अधिकारी श्री पी० एस० आनन्थ होंगे, जिनका मुख्यालय अफज़ल लाज, तिलक मार्ग, रामकोटे हैदराबाद-1 होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निदेशित करती है।

अनुसूची

"इस मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्या सिंगरेनी कोलियरीज़ कम्पनी लिमिटेड के शान्तिखनी, बेलमपल्ली प्रभाग, के प्रबन्धमण्डल का दल संख्या 13 और 14 के निम्नलिखित फ़िल्लरों को क्रमश: 15 और 16 अप्रल, 1971 को बिना मजदूरी दिए, उनकी कामबन्दी कर देना न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं?"

1. श्री लिंगम चन्द्रैयाह
2. श्री बोड्डुला चन्द्रैयाह
3. श्रीपासीकान्ती रायामाल्लू
4. श्री जाम्मे ओडेलू
5. श्री थोटापाल्ली अंकुल
6. श्री कामबाला गुरवैयाह
7. श्री चेडीपल्ली मल्लैयाह
8. श्री अक्कापाका मल्लैयाह
9. श्री कातम पी० पोशाम
10. श्री आकुनुरी पोशम
11. श्री बुड्डार्थी गाटेयाह
12. श्री भोरापाका लिंगैयाह
13. श्री एर्काला रायामाल्लू
14. श्री कास्युरी साम्मैयाह
15. श्री बाथुला राजाम
16. श्री पुट्टापाका इलैयाह
17. श्री डोंगेरी बुचयाह
18. श्री एद्ला माल्लैया
19. श्री कोल्लाबायुला रायामालू
20. श्री आकुला वेंकाटी
21. श्री बोम्मेदी भीमैयाह
22. श्री कासारला माल्लैयाह
23. श्री आड्डी कोमारैयाह
24. श्री आकुला पोशम
25. श्री विंथापुरी पोशम
26. श्री गाड्डम साम्मैयाह
27. श्री कामपल्ली राजम
28. श्री के० के० अली
29. श्री मिट्टापल्ली लक्समैयाह
30. श्री साब्बानी मुथैयाह
31. श्री एंगाला रायामाल्लू
32. श्री बेज्जांको राजाम
33. श्री कादारी मदनैयाह
34. श्री राबुला लक्समैयाह
35. श्री द्वारका प्रसाद
36. श्री अंदे कोमारैयाह
37. श्री ओड्डी कोमारैयाह
38. श्री पेंडाला राजम
39. श्री दुर्गम राजम
40. श्री सालीगान्नी राजम
41. श्री रंगा मल्लैयाह
42. श्री मेंडा रायालिंगू
43. श्री कादारी मदनैयाह
44. श्री बेजूजान्की राजम
45. श्री एनगाला रायामाल्लू
46. साब्बानी मुथैयाह
47. श्री मिट्टापल्ली लक्समैयाह
48. श्री एस० के० अली
49. श्री कामपल्ली राजम
50. श्री रेनेल्ली लिंगैयाह
51. श्री अंदे कोमारैयाह
52. श्री पर्का लिंगैयाह
53. श्री जांगापल्ली रायाराथाम
54. श्री अंकम बोंदयालू
55. श्री कीर्थि पोशाम
56. श्री गोगरला रायामाल्लू
57. श्री गद्दम सम्मैयाह
58. श्री चितापुरी पोशाम
59. श्री अकुला पोशम
60. श्री ओडी कोमारैयाह
61. श्री कासारला मल्लैयाह
62. श्री बोम्मिडी भीमैयाह
63. श्री आकुला वेंकाटी
64. श्री कोल्लाबाथुला रायामालू
65. श्री एदला माल्लैयाह
66. श्री डांगरी बुचैयाम
67. श्री पुट्टापाका इलैयाह
68. श्री बाथुला राजम
69. श्री पासीकोटी लिंगैयाह
70. श्री कास्थरी लिंगैयाह
71. श्री एरकाला रायामालू
72. श्री मोरापाका लिंगैयाह
73. श्री जागृता पोशम
74. श्री कोटीपल्लो लिंगैयाह।"

[संख्या एल-2111/5/71-एल० आर० 2]

New Delhi, the 29th December 1972

S.O. 2057.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Nag's Kajora Jambad Colliery, Post Office Ukhra, District Burdwan and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Nag's Kajora Jambad Colliery, Post Office Ukhra, District Burdwan to stop Shri Montu Mukherjee from working as Explosive Carrier at the Colliery with effect from the 14th July, 1971, is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?"

[No. L/1912/101/71-LRII.]

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर 1971

का० आ० 2057.—यतः, केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में नाग की कजोरा जामबाद कोलियरी, डाकघर उखड़ा, जिला बर्दवान के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या नाग की कजोरा जामबाद कोलियरी, डाकघर उखड़ा, जिला बर्दवान के प्रबन्ध मण्डल की श्री मोंटू मुकर्जी को कोलियरी में एक्सप्लोसिव कैरियर के रूप में 14 जुलाई, 1971 काम से रोकने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[संख्या एल/1912/101/71-एल०आर-2]

New Delhi, the 6th January 1972

S.O. 2058.—Whereas the Central Government is of opinion that industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Chirimiri Colliery, Post Office Chirimiri, District Surguja, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the demand of the workmen of Chirimiri Colliery that they should be paid Variable Dearness Allowance as per recommendations of the Wage Board for the Coal Mining Industry is justified? If so, to what relief the workmen are entitled?"

[No. L/2211/16/71-LRII.]

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1972

का० आ० 2058.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में निर्दिष्ट विषयों के बारे में चिरीमिरी कोलियरी, डाकघर चिरीमिरी, जिला सुरगुजा के प्रबन्ध मण्डल से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निदेशित करना वांछनीय समझता है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जबलपुर, को न्यायनिर्णय लिए निदेशित करती है

अनुसूची

"क्या चिरीमिरी कोलियरी के कर्मकारों की यह मांग कि उन्हें कोयला खनन उद्योग सम्बन्धी मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार परिवर्ती मंहगाई भत्ता दिया जाना चाहिए न्यायोचित है ? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?"

[संख्या एल-2211/16/71-एल० आर०-2]

New Delhi, the 13th January 1972

S.O. 2059.—Whereas the Central Government is opinion that an industrial dispute exists between employers in relation to the management of Messrs. Chewgule and Company Private Limited, Mormugoa Harbour, Goa and their workmen in respect of the matters specifide in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desidable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Bombay constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Messrs. Chowgule and Company Primate Limited, Mormugao Harbour, in terminating the services of the workman Shri Anand S. Vernekar, trainee in Electrical department Palletisation Plant, Pale Mines in their letter No. STAFF/TL/53, dated the 27th June, 1969 and consequently not offering him the post of Charge hand in the grade of Rs. 300—15—390—20—510 after the completion of the training period was justifiable? If not, to what relief is the workman entitled?

[No. L-29012/22/71-LRIV.]

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1972

का० आ० 2059.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स चोगले एंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, मोरमुगाओ हारबोर, गोआ के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकारण, (संख्या 2) बम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या मैसर्स चोगुले एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, मोरमुगाओ हारबार के प्रबन्ध मण्डल की उनके पत्र संख्या स्टाफ/टी०एल०/53,तारीख 27 जून, 1969 के द्वारा श्री आनन्द एस० वरनेकर, पेलमाइन्स की पाल्लेटाइजेशन प्लाट के बिजली विभाग में प्रशिक्षार्थी की सेवा समाप्त करने और परिणामतः प्रशिक्षण की अवधि पूरी हो जाने के बाद उसे 300-15-390-20-510 के ग्रेड में चार्ज हैंड के पद की पेशकश न करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल/29012/22/71-एल० आर० 4]

New Delhi, the 29th January 1972

S.O. 2060.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Gazdhar Kajora Colliery of Messrs Gazdhar Kajora Coal Mines Limited, Post Office Kajoragram, District Burdwan and their workmen in respect of the matters specified in the schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Gazdhar Kajora Colliery of Messrs Gazdhar Kajora Coal Mines Limited, Post Office Kajoragram, Burdwan, in stopping from work Shri Sunil Kumar Nandi, Mechanical Fitter, Mazdoor with effect from the 22nd October, 1970, by invoking the provisions of Standing Order 10(f) of the Certified Standing Orders of the establishment, is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

[No. L/1912/77/71-LRII.]

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1972

का०आ० 2060.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स गजधर काजोरा कोल माईन्स लिमिटेड की गजधर काजोरा कोलियर, डाकघर काजोरा ग्राम जिला बर्दवान के प्रबन्ध से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वाछंनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 का उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या मैसर्स गजधर काजोरा कोल माईन्स लिमिटेड की गजधर काजोरा कोलियरी, डाकघर काजोरा ग्राम बर्दवान के प्रबन्धमण्डल की, श्री सुनिल कुमार नन्दी, मेकैनिकल फिटर मजदूर को प्रतिष्ठान के प्रमाणित स्थायी आदेशों के स्थायी आदेश 10 (घ) के उपबन्धों को लागू करके 22 अक्टूबर, 1970 से काम से रोकने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[संख्या एल०-1912/77/71-एल० आर० 2]

New Delhi, the 4th February 1972

S.O. 2061.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Tandur and Navandgi Stone Quarries (Private) Limited, Hyderabad and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Bombay constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the existing rates of wages and dearness allowance of the different categories of workers employed in the Stone Quarries of Messrs The Tandur and Navandgi Stone Quarries (Private) Limited, Hyderabad on various operations require any revision? If, so, what should be such rates of wages and dearness allowance and from what date?

[No. L. 29011/39/71-LR.IV.]

नई दिल्ली, 4 फरवरी 1972

का० आ० 2061.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स तन्दूर एण्ड नवान्दगी स्टोनक्वारीज (प्राइवेट) लिमिटेड, हैदराबाद के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उसके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निदर्शित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण अबम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना है ।

अनुसूची

"क्या मैसर्स दि तन्दूर एण्ड नावान्दगी स्टोन क्वारीज (प्राइवेट) लिमिटेड, हैदराबाद की पत्थर खदानों में विभिन्न संक्रियाओं पर नियोजित विभिन्न प्रवर्गों के कर्मकारों की वर्तमान मजदूरी और महंगाई भत्तों की दरों में कोई पुनरीक्षण अपेक्षित है? यदि हां, तो ऐसी मजदूरी और महंगाई भत्ते की क्या दर और किस तारीख से होने चाहिएं ? "

[संख्या एल०-29011/39/71-एल०आर०-4]

New Delhi, the 7th February 1972

S.O. 2062.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of North Keshalpur Colliery of Messrs North Keshalpur Colliery Company Private Limited, Post Office Katrasgarh, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 1), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of North Keshalpur Colliery of Messrs North Keshalpur Colliery Company Private Limited, Post Office Katrasgarh, Dhanbad, of dismissal of Shri L. P. Singh, Overman, with effect from the 1st/2nd March, 1971 is justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

[No. L/2012/185/71-LRII.]

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1972

का० आ० 2062—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबन्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स नॉर्थ के केशालपुर कोलियरी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड की नार्थ केशालपुर कोलियरी, डाकघर कत्रासगढ़, जिला धनबाद के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (संख्या 1) धनबाद को न्याय-निर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या मैसर्स नार्थ केशालपुर कोलियरी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड की नार्थ केशालपुर कोलियरी, डाकघर कत्रासगढ़, धनबाद के प्रबन्ध-मण्डल की श्री एल० पी० सिंह, ओवरमैन को 1/2 मार्च, 1971 से पदच्युत करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[संख्या एल०2012/185/71-एल० आर० - 2]

New Delhi, the 11th February 1972

S.O. 2063.—Whereas the industrial dispute specified in the Schedule hereto annexed is pending before Shri A. Panchakshraiah, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Bangalore; whereas this dispute was shown erroneously as pending before Shri B. M. Jayamahadeva Prasad, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Banglore, *vide* order No. S.O. 1756 dated the 28th January, 1971 published in the Gazette of India on 24th April, 1971;

And whereas the services of Shri A. Panchakshraiah have ceased to be available;

Now, therefore, in supersession of the said order in so far as it relates to this dispute, and in exercise of the powers conferred by section 7A and sub-section (1) of section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri Narayana Rai Kudoor as the Presiding Officer, with headquarters at Banglore, withdraws the proceedings in relation to the said dispute from Shri A. Panchakshraiah and transfers the same to the said Industrial Tribunal, Banglore, for the disposal of the said proceedings with the direction that the said Tribunal shall proceed with the proceedings from the stage at which they are transferred to it and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

Sl. No.	Reference No. and date	Parties to the dispute
1.	F. No. 37/2/66-LR.I dated the 28th July, 1967.	Workmen and managements of several contractors in the Mines of the Mysore Iron & Steel Ltd., Bhadravathi.

[No. L/29025/14/71-LR-IV.]

नई दिल्ली, 11 फरवरी 1972

का० आ० 2063.—यतः इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद, श्री ए० पंचाक्षरैया, मीठासीन अधिकारी औद्योगिक अधिकरण, बंगलौर के समक्ष लम्बित है, और यतः भारत के राजपत्र तारीख 24-4-1971 में प्रकाशित आदेश संख्या का० आ० 1756, तारीख 28-1-1971 द्वारा इस विवाद को भूल से श्री बी० एम० जयामहादेवा, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, बंगलौर के समक्ष लम्बित दिखाया गया था ;

और यतः श्री ए० पंचाक्षरैया की सेवाएं उपलब्ध नहीं रही हैं ;

अतः अब, उक्त आदेश को अधिक्रांत करते हुए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1949 का 14) की धारा 7-क और धारा 33-ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री नारायण राय कुडूर होंगे, जिनका मुख्यालय बंगलौर होगा, श्री ए० पंचाक्षरैया से उक्त विवाद से सम्बद्ध कार्यवाही को वापिस लेती है और उसे उक्त कार्यवाही के निपटाने के लिये उक्त औद्योगिक अधिकरण, बंगलौर को इस निदेश के साथ अन्तरित करती है कि उक्त अधिकरण आगे कार्यवाही उसी प्रक्रम से करेगा जिस पर वह उसे अन्तरित की जाए और विधि के अनुसार उसका निपटान करेगा ।

अनुसूची

क्रम सं०	हवाला संख्या और तारीख	विवाद के पक्षकार
1.	फा० संख्या 37/2/66-एल० आर० -1, तारीख 28 जुलाई 1967 ।	मैसूर आयरन और स्टील लिमिटेड, भद्रावती की खानों में कई ठेकेदारों के कर्मकार और प्रबन्ध मंडल ।

[सं० एल० -29025/14/71-एल० आर०-IV]

S.O. 2064.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Jamuna Colliery of Messrs National Coal Development Corporation Limited, Post Office Jamuna Colliery, District Shahdol (Madhya Pradesh), and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Keeping in view the seniority list of Lower Division Clerks notified in 1968, whether the management of Jamuna Colliery of Messrs National Coal Development Corporation Limited, was justified in giving seniority to Shri A. K. Prasad over Shri Samukutty as per the subsequent seniority list notified in 1969? If not, to what relief is the workman entitled?"

[No. L22012/21/71-LRII.]

का० आ० 2064.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स नैशनल कोल डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की जमुना कोलियरी, डाकघर जमुना कोलियरी, जिला शहडोल मध्य प्रदेश से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निदर्शित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या मैसर्स नैशनल कोल डेवेलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की जमुना कोलियरी के प्रबन्धमंडल का 1968 में अधिसूचित निम्नश्रेणी लिपिकों का ज्येष्ठता सूची को ध्यान में रखते हुए उसके बाद 1969 में अधिसूचित ज्येष्ठता सूची के आधार पर श्री ए०के० प्रसाद को श्री सामुकुट्टी पर ज्येष्ठता देना न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[संख्या एल०-22012/21/71—एल०आर०-2]

New Delhi, the 14th February 1972

S.O. 2065.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relaion to the management of Pure Sitalpur Colliery, Post Office Ukhra, District Burdwan and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Pure Sitalpur Colliery owned by Messrs Pure Sitalpur Coal Concern Limited, Post Office Ukhra, District Burdwan in not providing employment to Shri Purustom Harijan, Loader with effect from the 25th December, 1970, is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

[No. L/1912/74/71-LRII.]

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1972

का० आ० 2065.—अतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में प्योर सीतलपुर कोलियरी, डाकघर उखरा, जिला बर्दवान के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्याय-निर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्याय-निर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या मैसर्स प्योर सीतलपुर कोल कन्सर्न कोलियरी लिमिटेड, डाकघर उखरा, जिला बर्दवान की प्योर सीतलपुर कोलियरी के प्रबन्धमण्डल को श्री पुरुस्तोम हरिजन, लीडर को 25 दिसम्बर, 1970 से रोजगार न देने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[संख्या एल०-1912/74/71-एल० आर०-2]

S.O. 2066.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Ghusick Colliery of Messrs Coal and Mineral Syndicate Private Limited, Post Office Kalipahari, District Burdwan and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Ghusick Colliery of Messrs Coal and Mineral Syndicate Private Limited, Post Office Kalipahari, District Burdwan in laying off of their workmen from the 2nd September, 1971 to the 9th October, 1971 is legal and justified? If not, to what relief are the concerned workmen entitled?"

[No. L/1912/156/71-LRII.]

का० आ० 2066.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स कोल एण्ड मिनरल सिंडीकेट प्राईवेट लिमिटेड की धुसिक कोलियरी, डाकघर काली पहाड़ी, जिला बर्दवान के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या मैसर्स कोल एण्ड मिनरल सिंडीकेट प्राईवेट लिमिटेड की धुसिक कोलियरी, डाकघर काली पहाड़ी, जिला बर्दवान के प्रबन्धमण्डल की अपने कर्मकारों की 2 सितम्बर, 1971 से 9 अक्तूबर, 1971 तक कामबन्दी करने की कार्यवाही वैध और न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?"

[संख्या एल०/1912/156/71-एल०आर०-2]

New Delhi, the 1st March, 1972

S. O. 2067.—Whereas the industrial disputes specified in the Schedule hereto annexed are pending before Shri Gopal Narain Sharma, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Rajasthan Jaipur;

And whereas the services of the said Shri Gopal Narain Sharma are no longer available;

And whereas for the ends of justice and convenience of parties, the said disputes should be disposed of without further delay;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and sub-section (1) of section 33B of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri Mohd. Yaqub Khan, as the Presiding Officer, with head quarters at Jaipur, withdraws the proceedings in relation to the said disputes from Shri Gopal Naraian Sharma, and transfers the same to Shri Mohd. Yaqub Khan, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Jaipur for the disposal of the said proceedings with the direction that the said Tribunal shall proceed with the said proceedings from the stage at which they are transferred to it and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

Sl. No.	Parties to the dispute	Reference number and date to the Industrial Tribunal	S.O. of Gazette/ year of publication
1.	Employers in relation to management of Messrs Western Bengal Coal Fields Limited, Khetri Copper Project, Khetri Nagar and their workmen.	No. L—29011/36/71-LR-IV dt. 22-9-1971	3550/71
2.	Management of Khetri Copper Project owned by Hindustan Copper Limited, Khetri District Jhunjhunu and their workmen.	No. 10/64/70-LR-IV dated 2-11-1970	3643/70

[No. L-29011/36/71-LRI/IV.]

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1972

का०आ० 2067—यत: इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद, श्री गोपाल नारायण शर्मा, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, राजस्थान, जयपुर के समक्ष लम्बित है;

और यत: उक्त श्री गोपाल नारायण शर्मा की सेवाएं उपलब्ध नहीं रही हैं;

और यत: न्याय के उद्देश्यों और पक्षकारों की सुविधा के लिए, उक्त विवाद बिना और विलम्ब के निपटाए जाने चाहिए;

अत:, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और 33 ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन श्री मोहम्मद याकुब खां होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर होगा, श्री गोपाल नारायण शर्मा से उक्त विवाद से सम्बद्ध कार्यवाहियों को वापस लेती है और उन्हें उक्त कार्यवाहियों के निपटान के लिए मोहम्मद याकुब खां, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, जयपुर को इस निदेश के साथ अन्तरित करती है कि उक्त अधिकरण और आगे कार्यवाहियां उसी प्रक्रम से करेगा जिस पर वे उसे अन्तरित की जाएं और विधि के अनुसार उनका निपटान करेगा।

अनुसूची

क्रमांक	विवाद के पक्षकार	औद्योगिक विवाद की निर्देश संख्या और तारीख	राजपत्र में का०आ० संख्या/ प्रकाशन का वर्ष
1.	मैसर्स वेस्टर्न बंगाल कोल फील्ड्स लिमिटेड, खेत्री काप्पर प्राजेक्ट, खेत्री नगर के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजक और उनके कर्मकार	एल-29011/36/71-एल० आर०-4, तारीख 22-9-71	3550/71
2.	हिन्दुस्तान काप्पर लिमिटेड, खेत्री, जिला खेत्री का खेत्री काप्पर प्राजेक्ट का प्रबन्धमंडल और उनके कर्मकार।	10/64/70-एल० आर०-4, 2-11-1970	3643/70

[सं० एल०-29011/36/71-एल० आर०-I/4]

New Delhi, the 4th March 1972

S.O. 2068.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs K. G. Khanna and Sons, Messrs Kisan Miners and Messrs R. N. Tandon and Sons, Contractors, Ispat Lime stone Quarries of Rourkela Steel Project of Hindustan Steel Limited, Babupur, Satna and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur with Headquarters at New Delhi constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the demand of the workmen for payment of variable Dearness Allowance to the piece-rated workers by the managements of Messrs K. G. Khanna and Sons, Messrs Kisan Miners and Messrs R. N. Tandon and Sons, Contractors, Ispat Limestone Quarries, Babupur, Satna with effect from the 1st May, 1970 as per the recommendations of the Central Wage Board for Limestone and Dolomite Mining Industry is justified? If so, to what relief are the workmen enttiled?

[No. L-29011/2/72-LR-IV.]

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1972

का० आ० 2068.—यत: केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स के० जी० खन्ना एंड संस, मैसर्स किसान माईनर्स और मैसर्स आर० एन० टंडन एंड संस, ठेकेदार, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, स्टील प्रोजेक्ट की इस्पात चूना पत्थर क्वारीज बाबूपुर, सतना के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यत: केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अत:, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जबलपुर, जिसका मुख्यालय, नई दिल्ली होगा, को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या मैसर्स के० जी० खन्ना एंड संस, मैसर्स किसान माइनर्स और मैसर्स आर० एन० टंडन एंड संस, ठेकेदार, इस्पात चूना पत्थर क्वारीज, बाबूपुर, सतना के प्रबन्धमंडलों द्वारा चूना पत्थर और डोलोमाईट खनन उद्योग के लिए केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार 1-5-70 से मात्रानुपाती दर के कर्मकारों को परिवर्ती, महंगाई भत्ते के संदाय करने की कर्मकारों की मांग न्यायोचित है? यदि हां, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है ?

[सं० एल० -29011/2/72-एल० आर०-4]

New Delhi, the 6th March, 1972

S.O. 2069.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Badjna Colliery of Messrs Oriental Coal Company Limited, Post Office Nirsachatti, District Dhanbad, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Governmnf hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 1), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the demand of the Colliery Mazdoor Sangh that Shri Lallu Singh, Assistant Supervisor (C.R.O.), Badjna Miners Hostel of Badjna Colliery of Messrs Oriental Coal Company Limited, Post Office Nirsachatti, District Dhanbad, should be allowed by the management to resume his duty immediately with full back wages from the 27th October, 1970, is justified? If so, to what relief is the workman entitled?"

[No. L/2012/179/71-LRII.]

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1972

का० आ० 2069.— यत : केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसके उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स ओरिएंटल कोल कंपनी लिमिटेड, की बादजना कोलियरी, डाकघर निरसाचट्टी, जिला धनबाद के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारो के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यत : केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्याय निर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अत :, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7–क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (संख्या 1), धनबाद को न्याय निर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या कोलियरी मजदूर संघ की यह मांग कि प्रबन्ध मंडल द्वारा मैसर्स ओरिएंटल कोल कम्पनी लिमिटेड, डाकघर निरसाचट्टी, जिला धनबाद की बादजना कोलियरी के बादजना खनिक होस्टल के सहायक पर्यवेक्षक (सी० आर० ओ०) श्री लाल्लू सिंह को 27 अक्तूबर, 1970 से पूर्ण बकाया मजदूरी देकर उसे अपनी ड्यूटी तुरन्त पुन : आरम्भ करने की अनुमति दी जानी चाहिए, न्यायोचित है ? यदि हां, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल–2012/179/71-एल० आर०–II]

New Delhi, the 7th March, 1972

S.O. 2070.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Company Limited, Post Office Kothagundium Collieries (Andhra Pradesh) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri P. S. Ananth, as Presiding Officer, with headquarters at Afzal Lodge, Tilak Road, Ramkote, Hyderabad-I, and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

1. "Whether the action of the management of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem is justified in terminating the services of Sarvashri K. Sambasiva Rao and M. Rajendra Prasad, Forest Clerks of Main Stores? If not, to what relief are they entitled?
2. Whether the action of the management in not fixing Sarvashri K. Sambasiva Rao and M. Rajendra Prasad in the grade of Rs. 205-325 with retrospective effect is justified? If not, to what relief are they entitled?"

[No. L/2112/44/71-LRII.]

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1972

का० आ० 2070 — यत : केन्द्रीय सरकार की राय है कि इस मे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सिंगरैनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, डाकघर कोठागुंडियम कोलियरीज, (आन्ध्रप्रदेश) के प्रबन्ध मे सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारो के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यत : केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अत :, अब, औदयोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7–क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री पी० एस० अनन्थ होंगे, जिनका मुख्यालय अफजल लॉज, तिलक रोड, रामकोटे, हैदराबाद । होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

1. "क्या सिंगरैनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, कोठागुंडियम के प्रबन्ध मंडल की सर्वश्री के० साम्ब शिवा राव और एम० राजेन्द्र प्रसाद, भंडार के वन लिपिकों की सेवाएं खतम करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नही, तो वे किस अनुतोष के हकदार है ।"

2 "क्या प्रबन्ध मंडल की सर्वश्री के० साम्बशिवा राव और एम० राजेन्द्र प्रसाद का वेतन 205–325 रुपये की श्रेणी में भूत

लक्षी प्रभाव से नियत न करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं तो वे किस अनुतोष के हकदार हैं ?"

[संख्या एल०/2112/44/71-एल०आर०-2]

S.O. 2071.—Whereas the Central Governnent is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Kotma Commiery of Associated Cement Company Limited, Post Office Kotma Colliery, District Shahdol (Madhya Pradesh), and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication, to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether in view of the recommendations of the Central Wage Board for Coal Mining Industry, the workload of the Miners of the Kotma Colliery of Associated Cement Company Limited Post Office Kotma Colliery, District Shahdol, requires to be revised? If so, what piece rate should be fixed for the workers?

Whether the rates of payment per tub made by the Kotma Colliery of Associated Cement Company Limited, Post Office Kotma Colliery, District Shahdol, to their miners for lead and lift and for ancillary jobs need be revised? If so, to what relief are the workmen entitled and from what date?"

[No. L/2211/2/72-LRII.]

का० आ० 2071.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड की कोतमा कोलियरी, डाकघर कोतमा कोलियरी, जिला शहडोल (मध्य प्रदेश) के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निदेशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निदेशित करती है।

अनुसूची

क्या कोयला खनन उद्योग के केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड की कोतमा कोलियरी, डाकघर कोतमा कोलियरी, जिला शहडोल के खनिकों के कार्यभार को पुनरीक्षित करना अपेक्षित है ? यदि, हां, तो कर्मकारों के लिए क्या भारानुपाती दर नियत की जाए ?

क्या एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड की कोतमा कोलियरी, डाकघर कोतमा कोलियरी, जिला शहडोल द्वारा उनके खनिकों को अगवानी और उठान तथा अन्य अनुसंगी कार्यों के लिए दिए गए प्रति टब के संदाय की दरों को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता है ? यदि हां, तो कर्मकार किस अनुतोष के और किस तारीख से हकदार हैं ?

[संख्या एल०/2211/2/71-एल०आर०-2]

New Delhi, the 18th March 1972

S.O. 2072.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Assam Railways and Trading Company Limited, Margherita, District Dibrugarh (Assam), and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act

SCHEDULE

"Whether the management of Messrs Assam Railways and Trading Company Limited, Margherita, having regard to their financial capacity, are justified in not implementing the Wage Board Recommendations in their three collieries namely Baragolai, Tipong and Ledo? If not, to what relief the workmen are entitled?"

[No. 6/62/59-LRII.]

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1972

का० आ० 2072.— यत : केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स असम रेलवेज एंड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड, मारघेरिता, जिला डिब्रूगढ़ (असम) के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यत : केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अत : , अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करता है ।

अनुसूची

"क्या मैसर्स असम रेलवेज एंड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड, मारघेरिता, के प्रबन्ध मंडल द्वारा अपनी वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए, अपनी तीन कोयला-खानों अर्थात् बार गोलाई, टिपांग और लीडो में मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित न करना न्यायोचित है । यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?"

[संख्या 6/62/69-एल० आर०-2]

New Delhi, the 21st March 1972

S.O. 2073.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers n relaton to the management of Pure Selected Tetulmari Colliery of Messrs Pure Selected Tetulmari Coal Company, Post Office Sijua, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 3), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Pure Selected Tetulmari Colliery of Messrs Pure Selected Tetulmari Coal Company, Post Office Sijua, District Dhanbad in stopping from work Shri Lal Mohan Bhattacharya, Electrician, with effect from the 30th September, 1971, is justified? If not to what relief is the concerned workman entitled?"

[No. L/20012/10/72-LRII.]

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1972

का० आ० 2073.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इस से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मसर्स प्योरे सिलेक्टेड टेटुलमारी कोल कम्पनी की प्योर सिलेक्टेड टेटुलमारी कोयला खान, डाकघर सिजुआ, जिला धनबाद के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यत : केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (संख्या-3), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या मैसर्स प्योरे सिलेक्टेड टेटुलमारी कोल कम्पनी की प्योर सिलेक्टेड टेटुलमारी कोयलाखान, डाकघर सिजुआ, जिला धनबाद के प्रबन्ध मण्डल की 30 सितम्बर, 1971 से श्री लाल मोहन भट्टाचार्य, बिजली मिस्त्री को काम से रोकने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबन्धित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल०-20012/10/72-एल०आर०2]

S.O. 2074.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of West Bokaro Colliery of Messrs West Bokaro Limited, Post Office Ghatotand, District Hazaribagh and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 1), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of West Bokaro Colliery of Messrs West Bokaro Limited, Post Office Ghatotand, District Hazaribagh, was justified in dismissing Shri Krishna Bahadur, Watchman from service with effect from the 9th October, 1971? If not, to what relief is the workman entitled?'

[No. L/20012/10/72-LRII.]

का० आ० 2074.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स वेस्ट बोकारो लिमिटेड की वेस्ट बोकारो कोलियरी, डाकघर घाटोटांड, जिला हजारीबाग के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947, का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, संख्या (1) धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या मैसर्स वेस्ट बोकारो लिमिटेड की वेस्ट बोकारो कोलियरी, डाकघर घाटोटांड, जिला हजारीबाग, के प्रबन्ध मंडल को, श्री कृष्ण बहादुर चौकीदार को 9 अक्टूबर, 1971 से पदच्युत करने की कार्यवाही न्यायोचित थी ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?"

[संख्या 20012/11/72-एल०आर०-II]

S.O. 2075.— Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of New Selected Dhori Colliery, Post Office Berno, District Hazaribagh, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 1), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of New Selected Dhori Colliery, Post Office Berno, District Hazaribagh

was justified in rendering idle the following 71 workmen for the period from the 7th June, 1971, to the 30th November, 1971 and in not paying them any wages or compensation for the said period of idleness ? If not, to what relief are the said workmen entitled ?

Sl. No.	Name of the workmen	Father's/husband's name
1.	Sri Lachman	S/o Jangi
2.	Srimati Mungeshwari	W/o Lachman
3.	Sri Padarath	S/o Dasai
4.	Srimati Dhanpatia	W/o Padareth
5.	Shrimati Sheopatia	W/o Nageshwar
6.	Sri Parmeshwar	S/o Ramkishun
7.	Sita Ram	S/o Rachhya
8.	Smt. Jirwa	W/o Parmeshwar
9.	Srimati Manwa	W/o Sita Ram
10.	Sri Brichh	S/o Brahmdeo
11.	Smt. Jaswa	W/o Brichh
12.	Sri Rajdeo II	S/o Deochand
13.	Sri Rambrichh	S/o Lachhman
14.	Smt. Fulbasia	W/o Rambrichh
15.	Sri Chalitar II	S/o Dasai
16.	Smt. Deobarti	W/o Jageshwar.
17.	Sri Gopichand	S/o Bijlal
18.	Smt. Jogeshwari	W/o Gopichand
19.	Smt. Parbalia	W/o Ram Prasad-II
20.	Sri Budhan	S/o Rati Ram
21.	Smt. Dukhani	W/o Budhan
22.	Sri Ramdeo	S/o Balchand
23.	Smt. Basmatia	W/o Ramdeo
24.	Smt. Kauleshwari	W/o Ram Prasad-I
25.	Sri Panchu	S/o Sukhan
26.	Smt. Mankuwari	W/o Panchu
27.	Smt. Nepuri	W/o Budhan
28.	Sri Lalpat	S/o Sheo Narai
29.	Sri Doman	S/o Jhauri
30.	Sri Dwarik	S/o Jogeshwar
31.	Smt. Jagawa	W/o Ramswaroop
32.	Sri Rambrichh	S/o Bishambhar
33.	Smt. Marchhi	W/o Rambrichh
34.	Sri Nathuni	S/o Dukhan
35.	Smt. Daulti	W/o Nathuni
36.	Sri Kailash	S/o Ramsaran
37.	Smt. Somari	W/o Kailash
38.	Sri Faguni	S/o Janki
39.	Smt. Jitni	W/o Janki
40.	Sri Janki	S/o Ramkishun
41.	Sri Rajdeo	S/o Pandit
42.	Smt. Jamuni	W/o Rajdeo
43.	Sri Deep	S/o Rainath
44.	Sri Charo	S/o Lenga
45.	Sri Ledwa	S/o Charo
46.	Smt. Mangani	W/o Karma
47.	Sri Ram	S/o Somar
48.	Smt. Lakhia	W/o Ram
49.	Sri Somara	S/o Adhir
50.	Smt. Sohagi	W/o Samara
51.	Sri Bandhu	S/o Guhila
52.	Smt. Birso	W/o Bandhu
53.	Sri Sukhram	S/o Bahadur
54.	Smt. Bachan	W/o Sukhram
55.	Smt. Etwari	W/o Prabhu
56.	Sri Bodhana	S/o Lachhman
57.	Smt. Mangari	W/o Bodhana
58.	Smt. Biglahi	W/o Lakhawa
59.	Sri Sanioharwa	S/o Gendra
60.	Smt. Mangari	W/o Mangara
61.	Smt. Mangari	W/o Jagdish
62.	Smt. Surjee	W/o Deep
63.	Sri Nanhu	S/o Ram Ratan
64.	Sri Gurucharan	S/o Deshwar
65.	Smt. Jirwa	W/o Shyam Lal
66.	Sri Mangara	S/o Bhalu
67.	Smt. Sibantin	W/o Sanicharwa
68.	Smt. Budhani	W/o Sree Nunia
69.	Smt. Jirwa	W/o Sree Ram Prasad
70.	Sri Sukhdeo	S/o Budhan
71.	Smt. Rukamania	W/o Sree Ram Lal."

[No. L/20012/193/71—LRII

का०आ० 2075.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में न्यू सिलेक्टेड धोरी कोलियरी, डाकघर बर्मो , जिला हजारीबाग, के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (संख्या 1), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या न्यू सिलेक्टेड धोरी कीलियरी, डाकघर बर्मो, जिला हजारीबाग के प्रबन्ध मंडल की, निम्नलिखित 71 कर्मकारों को, 7 जून , 1971 से 30 नवम्बर 1971 तक की अवधि के लिए बेकार बनाने और बेकारी की उक्त अवधि के लिए उन्हें कोई वेतन या प्रतिकार न देने की कार्यवाही न्यायोचित थी ? यदि, नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

आदेश

क्रमांक	कर्मकार का नाम	पिता / पति का नाम
1.	श्री लछमन	पुत्र जांगो
2.	श्रीमती मुंगेश्वरी	पत्नी लछमन
3.	श्री पदारथ	पुत्र दसाई
4.	श्रीमती धनपतिया	पत्नी पदारथ
5.	श्रीमती शिवपतिया	पत्नी नागेशवर
6.	श्री परमेश्वर	पुत्र रामकिशन
7.	श्री सीताराम	पुत्र रछैया
8.	श्रीमती जिवां	पत्नी परमेश्वर
9.	श्रीमती मन्वा	पत्नी सीताराम
10.	श्री बृच्छ	पुत्र ब्रह्मदेव
11.	श्रीमती जसवा	पत्नी बृच्छ
12.	श्री राजदेव 2	पुत्र देवचन्द
13.	श्री राम बृच्छ	पुत्र लछमन
14.	श्रीमती फुलबसिया	पत्नी रामबृच्छ
15.	श्री चालितर 2	पुत्र दसाई
16.	श्रीमती देवरती	पत्नी जगेश्वर
17.	श्री गोपीचन्द	पुत्र बिजलाल
18.	श्रीमतीजोगेश्वरी	पत्नी गोपीचंद

क्रमांक	कर्मकार का नाम	पिता / पति का नाम
19.	श्रीमती परबलिया	पत्नी रामप्रसाद 2
20.	श्री बुधन	पुत्र रती राम
21.	श्रीमती दुखनी	पत्नी बुधन
22.	श्री रामदेव	पुत्र बालचंद
23.	श्रीमती बासमतिया	पत्नी रामदेव
24.	श्रीमती कोलेश्वरी	पत्नी रामप्रसाद-1
25.	श्री पांचू	पुत्र सुखन
26.	श्रीमती मानकुंवरि	पत्नी पांचू
27.	श्रीमती नेपुरी	पत्नी बुधन
28.	श्री लालपत	पुत्र शिवनारायण
29.	श्री डोमन	पुत्र झौरी
30.	श्री कारिका	पुत्र जोगेश्वर
31.	श्रीमती जगवा	पत्नी रामस्वरुप
32.	श्री रामबृच्छ	पुत्र विशम्भर
33.	श्रीमती मारछी	पत्नी राम बृच्छ
34.	श्री नथुनी	पुत्र दुखन
35.	श्रीमती दौलती	पत्नी नथुनी
36.	श्री कैलाश	पुत्र रामसरन
37.	श्रीमती सोमारी	पत्नी कैलाश
38.	श्री फागुनी	पुत्र जानकी
39.	श्रीमती जितनी	पत्नी जानकी
40.	श्री जानकी	पुत्र रामकिशन
41.	श्री राजदेव	पुत्र पंडित
42.	श्रीमती जामुनी	पत्नी राजदेव
43.	श्री दीप	पुत्र राजनाथ
44.	श्री चारो	पुत्र लेंगा
45.	श्री लेदवा	पुत्र चारो
46.	श्रीमती मंगानी	पत्नी कर्मा
47.	श्री राम	पुत्र सोमर
48.	श्रीमती लखिया	पत्नी राम
49.	श्री सोमारा	पुत्र अधीर
50.	श्रीमती सोहागी	पत्नी सामारा
51.	श्री बन्धु	पुत्र गुहिला
52.	श्रीमती बिरसो	पत्नी बन्धु
53.	श्री सुखराम	पुत्र बहादुर
54.	श्रीमती बचन	पत्नी सुखराम
55.	श्रीमती एतवारी	पत्नी प्रभु
56.	श्री बोधाना	पुत्र लछमन
57.	श्रीमती मंगारी	पत्नी बोधाना
58.	श्रीमती बिगलाही	पत्नी लखावा
59.	श्री सनिचरवा	पुत्र गेन्द्रा
60.	श्रीमती मंगारी	पत्नी मंगारा
61.	श्रमती मंगारी	पत्नी जगदीश
62.	श्रीमती सुरजी	पत्नी दीप
63.	श्री नन्हू	पुत्र राम रतन
64.	श्री गुरुचरण	पुत्र देशवर
65.	श्रीमती जिखा	पत्नी श्याम लाल
66.	श्री मंगारा	पुत्र भालू
67.	श्रीमती सिबनतिन	पत्नी सनिचरवा
68.	श्रीमती बुधानी	पत्नी श्री नुनिया
69.	श्रीमती जीरवा	पत्नी श्री रामप्रसाद
70.	श्री सुखदेव	पुत्र बुधन
71.	श्रीमती रुकमनिया	पत्नी श्री रामलाल]

[संख्या एल०/20012/193/71-एल० आर० 2]

S.O. 2076.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Chinakuri Colliery No. 3 Pit of Messrs Bengal Coal Company Limited, Post Office Disergarh, District Burdwan and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Chinakuri Colliery No. 3 Pit of Messrs Bengal Coal Company Limited, Post Office Disergarh, District Burdwan in dismissing Sri Panchu Maj Dresser with effect from the 9th November 1971, is justified? If not, to what relief is the workman entitled."

[No. L/19012/2/72-LRII.]

का० आ० 2076.— यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इस से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स बंगाल कोल कम्पनी लिमिटेड की चिनाकुरी कोलियरी, पिट संख्या 3, डाकघर दिसेरगढ़, जिला बर्दवान के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्याय-निर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या मैसर्स बंगाल कोल कम्पनी लिमिटेड, की चिनाकुरी कोलियरी पिट संख्या 3, डाकघर दिसेरगढ़, जिला बर्दवान के

प्रबन्ध मण्डल की श्री पांच माजी ईसर को, 9 नवम्बर, 1971 से पदच्युत करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[संख्या एल०/19012/2/72-एल० आर०-2]

New Delhi, the 24th March 1972

S.O 2077.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Swang Colliery of National Coal Development Corporation Limited, Post Office Swang, District Hazaribagh and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 1), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the demand of the Colliery Mazdoor Sangh that Shri Mohammad Nazir Hussain, Overman, Sawang Colliery of Messrs National Coal Development Corporation Limited, Post Office Sawang, District Hazaribagh should be promoted as Senior Overman with retrospective effect, is justified? If so, to what relief is the workman concerned entitled and from what date?"

[No. L/2012/215/71-LRII.]

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1972

का०आ० 2077.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में नैशनल कोल डेवेलपमैंट कार्पोरेशन लिमिटेड की स्वांग कोलियरी, डाकघर स्वांग, जिला हजारी बाग के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (सं० 1), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या कोलियरी मजदूर संघ की यह मांग कि मैसर्स नेशनल कोल डेवेलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की स्वांग कोलियरी, डाकघर स्वांग, जिला हजारीबाग के श्री मोहम्मद नजीर हुसैन, ओवर मैन की ज्येष्ठ ओवरमैन के रूप में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की जानी चाहिए, न्यायोचित है ? यदि हां, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का और किस तारीख से हकदार है।"

[सं० एल०/2012/215/71-एल० आर०-2]

New Delhi, the 6th April 1972

S.O. 2078.—Whereas the employers in relation to the management of the Rashtriya Khadan Mazdoor Sahakari Samiti, Contractors, Kokan Mines, Post Office, Dalli-Rajhara, Durg (Madhya Pradesh) and their workmen represented by the Samyukta Khadan Mazdoor Sangh, Post Office Dalli-Rajhara, Durg (Madhya Pradesh) have jointly applied to the Central Government under sub-section (2) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), for reference of an Industrial dispute that exists between them to an Industrial Tribunal in respect of the matter set forth in the said application and reproduced in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government is satisfied that the persons applying represent the majority of each party;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the Rashtriya Khadan Mazdoor Sahakari Samiti, Post Office, Dalli-Rajhara, Durg (Madhya Pradesh) is justified in terminating the services of Shri Ram Prasad and Shrimati Janakibai, with effect from the 5th May, 1971? If not, to what relief are these workmen entitled?"

[No. L-26011(1)/72-LR-IV.]

BALWANT SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1972

का०आ० 2078.—यतः मैसर्स राष्ट्रीय खदान मजदूर सहकारी समिति, ठेकेदार, कोकान खान, डाकघर डाल्ली राजहारा, दुर्ग (मध्य प्रदेश) के प्रबन्ध से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों, जिनका प्रतिनिधित्व संयुक्त खदान मजदूर संघ, डाकघर डाल्ली—राजहारा, दुर्ग (मध्य प्रदेश) करता है, ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन संयुक्त रूप से केन्द्रीय सरकार को आवेदन किया है कि वह उनके बीच विद्यमान औद्योगिक विवाद को उक्त आवेदन में उपवर्णित और इस से उपाबद्ध अनुसूची में उद्धृत विषय के बारे में किसी औद्योगिक अधिकरन को निर्देशित करे।

और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि आवेदन करने वाले व्यक्ति प्रत्येक पक्ष के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या राष्ट्रीय खदान मजदूर सहकारी समिति, डाकघर डाल्ली-राजहारा, दुर्ग (मध्य प्रदेश) का 5 मई, 1971 से श्री राम प्रसाद श्रीमती जानकी बाई की सेवाएं समाप्त करना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो ये कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है ।"

[संख्या एल०-26011(1)/72- एल० आर०-4]

बलवन्त सिंह,
अवर सचिव ।

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 22nd July 1972

S.O. 2079.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Chowgule and Company Private Limited, Mormugao Harbour (Goa) and their workmen, which was received by the Central Government on the 18th July, 1972.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIIBUNAL NO. 2. BOMBAY

REFERENCE No. CGIT-2/9 OF 1971

Employers in relation to the management of Messrs Chodfule and Company Privates Limited, Mormugao Harbour (Goa).

AND

Their Workmen.

PRESENT:

Shri N. K. Vani, Presiding Officer.

APPEARANCES:

For the Employers.—Shri A. S. Devasthali, Labour Adviser.

For the Workmen.—Shri V. Venugopal (Self).

INDUSTRY: Iron ore Mines. STATE: Goa, Daman and Diu.

Bombay, dated the 4th July, 1972

AWARD

By order No. L-29012/30/71-LRIV, dated 6th November, 1971 the Central Govt. in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute existing between the employers in relation to the management of Messrs. Chowgule and Company Private Limited, Mormugao Harbour and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule as mentioned below:

"SCHEDULE

Whether the action of the management of Messrs. Chowgule and Company Private Limited, Mormugao Harbour (Goa) in treating the workman Shri V. Venugopalan, Plant Attendant, Palletisation plant, as having resigned with effect from 3rd June, 1971 based on the undated resignation alleged to have been received on 3rd June, 1971 was justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. After the receipt of this reference notices were issued to the parties. In pursuance of this notice M/s. Chowgule & Company Pvt., Ltd., (hereinafter referred to as 'the company') filed its written statement at Ex. 1/E.

3. According to the company,

(i) As the cause of Shri V. Venugopalan has not been espoused by any workmen employed in the company no industrial dispute exists. As Section 2A of the I.D. Act, 1947 is *ultra vires* the Constitution of India, reference is bad and not maintainable in law.

(ii) As Shri Venugopalan resigned from the service of the company, it was justified in accepting his resignation. It was justified in not permitting Shri Venugopalan to withdraw his resignation after it was accepted. In these circumstances, it was justified in treating Shri Venugopalan as having resigned from the service of the company, and he is not entitled to any relief.

4. The affected workman Shri Venugopalan had taken time for filing written statement. He was given time for filing written statement till 15th June, 1972. In the meanwhile both the parties entered into settlement. Settlement dated 13th June, 1972 signed by the parties and witnesses, Ex. 2/EW was sent to this Tribunal by post alongwith a letter, requesting the Tribunal to make award in terms of settlement.

5. On 29th June, 1972 Shri Venugopal was examined before me at Panaji. In his evidence he admits the settlement and to have received Rs. 490.96 in full and final settlement of all his claim with the company.

6. Shri Devasthali, Labour Adviser of the company also speaks about the settlement. He identifies the signatures on the settlement.

7. Having regard to the facts of this case and the evidence of the affected workman, I am of the view that the settlement arrived at between the parties is fair, reasonable and that it is in the interest of both the parties. I therefore accept the same. In the end I pass the following order.

ORDER

(i) Award is made in terms of settlement Ex. 2/EW.

(ii) Settlement Ex. 2/EW is to form part of the Award.

(iii) Parties to bear their own costs.

(Sd.) N. K. VANI,
Presiding Officer,
Central Govt. Industrial Tribunal
No. 2, Bombay.

Ex. 2|EW

BEFORE THE CENTRAL GOVRNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

REFERENCE No. CGIT-2/9 OF 1971

BETWEEN

Chowgule & Co. Private Ltd.

AND

Their Workmen.

May it please this honourable Tribunal:

The parties to the above Reference have arrived at a settlement and pray that an Award be made in terms thereof.

Terms of settlement

1. The Company has paid to Shri V. Venugopalan the following amounts:—

	Rs.
(a) Earned wages for the period 26th May, 1971 to 8th June, 1971.	119.00
(b) Encashment of 2½ days' privilege leave to Mr. V. Venugopalan's credit	21.96
(c) Ex-gratia amount without admission of liability.	350.00
Total	490.96

2. Mr. Venugopalan has accepted the aforesaid amount in full and final settlement of all his claims against the Company.

3. Mr. Venugopalan Confirms that he does not press his claim for reinstatement nor does he have any claim of whatsoever nature against the Company arising as a result of acceptance of his resignation by the Company.

Dated this 13th day of June, 1972.

For and on behalf of
Messrs. Chowgule & Co.,
Private Ltd.,
(Sd/-) Senior Manager.

The Workman.
(Sd.) V. VENUGOPALAN.

WITNESS:
(1) (Sd.)
(2) (Sd.)

WITNESS:
(1) (Sd.
(2) (Sd.)

[No. L-29012/30/71-LR-IV.]

S.O. 2080.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Industrial Tribunal, Rajasthan, Jaipur in the matter of an application under Section 33A of the said Act, filed by Shri Ramjeewan versus Shri Hamidullah Khan, Partner of Messrs Mohd. & Sons Gypsum Contractor to Associated Cement Company Limited, Jodhpur and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th July, 1972.

सैन्ट्रल इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल राजस्थान जयपुर

उपस्थित

श्री मोहम्मद याकूब खां

शिकायत नं० सी० आई टी०—2/70

श्री रामजीवन.....प्रार्थी

बनाम

श्री हमीददुल्ला खां मैसर्स मोहम्मद एण्ड सन्स जिप्सम कन्टक्टर जोधपुर व एक अन्य.....विपक्षी

अवार्ड

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 33(ए) दिनांक 7—12—70 के तहेत उपरोक्त विवाद को वास्ते निर्णय इस ट्रिब्यूनल को प्रेषित किया है ।

श्री भारत भूषण प्रार्थी की ओर से तथा श्री हमीद अल्ला खां कम्पनी की ओर से उपस्थित है ।

फरीकेन के प्रतिनिधियों का जाहिर करना है कि यूनियन और मेनेजमेन्ट के बीच एक बाहामी समझोता हो गया है उस समझौतों के हो जाने से

अब फरीकेन इस मामले में आगे कार्यवही नहीं चाहते हैं और आज एक दरखास्त के साथ एक समझोता भी पेश किया गया इस दरखास्त को तस्दीक दोनो पक्ष के प्रतिनिधियों ने इस अदालत के समक्ष की समझोता वैद्य व उचित मालुम होता है और दरखास्त पेश कर निवेदन किया गया है कि अब इस मामले में नो डिस्पूट अवार्ड पास कर दीया जावें ।

मिसल आज भारत सरकार की अधिसूचना के साथ प्राप्त हुई अतः 28—4—72 की फई अहकाम के मुताबिक इस मामले में समझौता के आधार पर अवार्ड पास किया जाता है जो भारत सरकार को वास्ते प्रकाशन प्रस्तुत किया जावें

मोहम्मद याकूब खां

26—6—72

सैन्ट्रल इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल राजस्थान जयपुर-।

[No. L-29011(30)/72-LR-IV.]

S.O. 2081.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Industrial Tribunal, Rajasthan, Jaipur in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Mohd. and sons Gypsum Contractors Merti, Silawatan, Jodhpur and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th July, 1972.

सैन्ट्रल इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल राजस्थान जयपुर

उपस्थित

श्री मोहम्मद याकूब खा

जज

मुकदमा न० सी० आई० टी—2/1972

जिप्सम माईन वरकर्स यूनियन भदवासी
खजान्ची बिल्डीग बीकानेर। .....प्रार्थी

बनाम

मोहम्मद एण्ड सन्स जिप्सम कन्डक्टर जोधपुर...विपक्षी

अवार्ड

भारत सरकार ने अपने नोटिफिकेशन संख्या एल०/25011/6/71 एल० आर० आई० दिनांक 6—4—72 के तहत उपरोक्त विवाद को वास्ते निर्णय इस ट्रिब्यूनल को प्रेषित किया है ।

Whether the action of the management of Messrs Mohammed and Sons, Gypsum Contractor Marti Silawathan, Jodhpur, in paying bonus not on full wages earned by the transporters during the year but on 40 per cent of the wages earned by them in a year is justified? If not, to what relief the transporters are entitled?

फरीकेन के निवेदन पर मिसल आज पेश हुई थी श्री भारत भूषण यूनियन की ओर से तथा श्री हम्मीद अल्लाह खां मेनेजमेंट की ओर से उपस्थित है ।

फरीकेन के लायक प्रतिनिधियों का जाहिर करना है कि यूनियन व मेनेजमेंट के बीच एक आम समझोता हो गया है जिसके तहेत यह केस भी निपटारा हो जाता है और आज पर दरखास्त के साथ एक समझोता भी पेश किया दरखास्त की तस्दीक इस अदालत के साक्ष दोनों पक्ष के प्रतिनिधियों ने की समझोता देखा गया जो सही है अतः समझौता हो जाने से इस मामले में निवेदनानुसा र से नो डिस्पूट अवार्ड पास किया जाता है जो शासन को प्रकाशन के लिये प्रस्तुत किया जावें ।

मोहम्मद याकूब खां

दिनांक 28-4-72

सैन्ट्रल इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल
राजस्थान जयपुर

[No. 25011(6)/71-LR-IV.]

S.O. 2082.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Industrial Tribunal, Rajasthan, Jaipur in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Jaipur Udyog Limited, Sawaimadhopur and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th July, 1972.

सन्ट्रल इन्डस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल राजस्थान जयपुर
उपस्थिति

श्री गोपाल नारायण शर्मा

मुकदमा नं० सी० आई० टी०-25/1969

सीमेंट वर्क्स कर्मचारी संघ सवाई माधोपुर . प्रार्थी

बनाम

जयपुर उद्योग लि० सवाई माधोपुर विपक्षी

अवार्ड

भारत सरकार ने अपने नोटिफिकेसन संख्या 36/65/68एल०आर० 1 दिनांक 10-10-69 के तहत उपरोक्त विवाद को वास्ते निर्णय इस ट्रिब्यूनल को प्रेषित किया है ?

"Whether the action of the management of the Jaipur Udhyog Limited, Sawaimadhopur in striking off the names of sarvasari Radhey Sham and Kanwar Pal Beldars from the rolls of the Company with effect from the 17th May, 1967 was legal and justified? If not, to what relief are the workmen entitled?"

श्री ब्रज सुन्दर शर्मा कर्मचारी संघ की ओर से तथा श्री सी० एन० शर्मा कम्पनी की ओर से उपस्थित हैं ?

फरीकन के लायक प्रतिनिधियों का कहना है कि कर्मचारी संघ व मैनेजमैन्ट के बीच एक बाहासी समझोता हो गया है इस लिए उन्होंने आज एक दरख्वास्त पश कर निवदन किया है कि इस मामले में श्री एन० के० जोशी लेबर कमिश्नर को पंच नियुक्त कर लिया है और उनका फैसला दोनों पक्ष को मान्य होगा इसलिए संघ अब इस मामले म आगे कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं । अतः समझौता हो जाने से व संघ द्वारा आगे कार्यवाही नहीं करने से इस मामले में नो डिस्पूट अवार्ड पास किया जाता है जो शासन को प्रकाशन के लिए प्रस्तुत किया जावें ।

गोपाल नारायण शर्मा

12-11-71

जज सैन्ट्रल इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल राजस्थान जयपुर

[No. 36(35)/68-LR-IV.]

New Delhi, the 25th July 1972

S.O. 2083.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Dhanbad, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of New Selected Dhori Colliery, Post Office Bermo, District Hazaribagh and their workmen, which was received by the Central Government on the 18th July, 1972.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

REFERENCE No. 9 OF 1972

PARTIES:

Employers in relation to the management of New Selected Dhori Colliery, P. O. Bermo, District Hazaribagh.

AND

Their Workmen.

PRESENT:

Shri A. C. Sen, Presiding Officer.

APPEARANCES:

For the Employer.—Shri S. S. Mukherjee, Advocate with Biswanath Nag, Manager.

For the Workmen.—Shri J. P. Singh, Azad, Secretary, Koyla Mazdoor Sabha.

STATE: Bihar. INDUSTRY: Coal.

Dhanbad, the 29th June 1972

AWARD

The present reference arises out of Order No. L/20012/193/71-LRII dated New Delhi, the 21st March, 1972 passed by the Central Government in respect of an industrial dispute between the parties mentioned above. The subject matter of the dispute has been specified in the schedule to the said order and the said schedule runs as follows:

"Whether the action of the management of New Selected Dhori Colliery, Post Office Bermo, District Hazaribagh was justified in rendering idle the following 71 workmen for the period from the 7th June, 1971, to the 30th November, 1971 and in not paying them any wages

or compensation for the said period of idleness? If not, to what relief are the said workmen entitled?"

S. No	Name of the Workmen	Father's /Husband's name
1	Shri Lachman	S/o Jangi
2	Shrimati Mangeshwari	W/o Lachman
3	Sri Padarath	S/o Dasai
4	Srimati Dhanpatia	W/o Padarcth
5	Shrimati Sheopatia	W/o Nageshwar
6	Shi Parmeshwar	S/o Ramkishun
7	Sita Ram	S/o Rachhya
8	Smt. Jirwa	W/o Parmeshwar
9	Srimati Manwa	W/o Sita Ram
10	Sri Brichh	S/o Brahmdeo
11	Smt. Jaswa	W/o Brichh
12	Sri Rajdeo II	S/o Deochand
13	Sri Rambrichh	S/o Lachhman
14	Smt. Fulbasia	W/o Ranbrichh
15	Sri Chalitar II	S/o Dasai
16	Smt. Deobarti	W/o Jageshwar
17	Sri Gopichand	S/o Brijlal
18	Smt. Jogeshwari	W/o Gopichand
19	Smt. Parbalia	W/o Ran Prasad II
20	Sri Budhan	S/o Rati Ram
21	Smt. Dukhani	W/o Budhan
22	Sri Ramdeo	S/o Balchand
23	Smt. Basmatia	W/o Ramdeo
24	Smt. Kauleshwari	W/o Ram Prasad I
25	Sri Panchu	S/o Sukhan
26	Smt. Mankuwari	W/o Panchu
27	Smt. Nepuri	W/o Budhan
28	Sri Lalpat	S/o Sheo Narain
29	Sri Doman	S/o Jhauri
30	Sri Dwarik	S/o Jogeshwar
31	Smt. Jagawa	W/o Ramswaroop
32	Sri Rambrichh	S/o Bishambhar
33	Smt. Marchhi	W/o Rambrichh
34	Sri Nathuni	S/o Dukhan
35	Smt. Daulti	W/o Nathuni
36	Sri Kailash	S/o Ramsaran
37	Smt. Somari	W/o Kailash
38	Sri Faguni	S/o Janki
39	Smt. Jitni	W/o Janki
40	Sri Janki	S/o Ramkishn
41	Sri Rajdeo	S/o Pandit
42	Smt. Jamuni	W/o Rajdeo
43	Sri Deep	S/o Rajnath
44	Sri Charo	S/l Lenga
45	Sri Ledwa	S/o Charo
46	Smt. Mangani	W/o Karma
47	Sri Ram	S/o Somar
48	Smt. Lakhia	W/o Ram
49	Sri Somara	S/o Adhir
50	Smt. Sohagi	S/o Samara
51	Sri Bandhu	S/o Guhila
52	Smt. Birso	W/o Baudhu
53	Sri Sukhram	S/o Bahadur
54	Smt. Bachan	W/o Sukhram
55	Smt. Etwari	W/o Prabhu
56	Sri Bodhana	S/o Lachman
57	Smt. Mangari	W/o Bodhana
58	Smt. Biglahi	W/o Lakhawa
59	Sri Sanicharwa	S/o Gendra
60	Smt. Mangari	W/o Mangara
61	Smt. Mangari	W/o Jagdish
62	Smt. Surjee	W/o Deep
63	Sri Nanhu	S/o Ram Ratan
64	Sri Gurucharan	S/o Deshwar
65	Smt. Jirwa	W/o Shyam Lal
66	Sri Mangara	S/o Bhalu
67	Smt. Sibantin	W/o Sanicharwa
68	Smt. Budhani	W/o Sree Nunia
69	Smt. Jirwa	W/o Sree RamPrasad
70	Sri Sukhdeo	S/o Budhan
71	Smt. Rukmania	W/o Sree Ram Lal

2. The dispute has been settled by the parties out of Court. A Memorandum of settlement dated 29th June, 1972 has been fixed today. I have gone through the terms of settlement and I find them quite fair and reasonable. There is no reason why an award should not be made on the terms and conditions laid down in the Memorandum of Settlement. I accept it and make an award accordingly. The memorandum of settlement shall form part of the award.

3. Let a copy of this award be sent to the Ministry as reuired under section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

A. C. SEN,
Presiding Officer.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL
NO. 1, DHANBAD

Reference No. 9 of 1972.

Parties: Employers in relation to the management of New Selected Dhori Colliery

AND

Their workmen.

That without prejudice to the respective contentions of the parties contend in their written statement the subject matter of dispute in the above reference has been amicably settled between the parties on the following terms:—

1. That the works of the river side quarry as per direction of the department of Mines will continue to remain suspended from 15th June to 31st October every year.

2. That the management will decide to observe immediately the workman employed at the riverside quarry in the same or similar work in other parts of the colliery for the period of 15th June to 31st October.

3. That during the above period the management will not employ any new workmen in the categories in preference to the workmen employed in the river side quarry.

4. That for the period of unemployment of the workmen during 7th June, 1971 to 30th November, 1971 on will be treated as if on leave without any wages for account of theh closure of theh riverside quarry they the purpose their continuity of service only.

5. That the parties will bear the respectives costs of the proceedings pending before the honourable Tribunal.

6. That the above terms of the settlement finally resolves all disputes pending before the honourable Tribunal in the above reference.

7. That the above terms of settlements are fair and reasonable and is in the best interest of the parties.

It is, therefore, humbly prayed that the above terms may kindly be accepted and award passed in terms of the settlement.

For the Workmen.

Secretary,
J. P. SINGH AZAD.
Koyla Mazdoor Sabha.

For theh Employer.

Manager
(1) BISWANATH NAG
(2) S. S. MUKHERJEE
Advocate

[No. L-2012/193/71-LRII.]

New Delhi, the 26th July 1972

S.O. 2084. -In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Damra Colliery of Messrs Katras Jherriah Coal Company Limited Post Office Kalipahari, District Burdwan and their workmen, which was received by the Central Government on the 18th July, 1972.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CULCUTTA.

REFERENCE No. 79 OF 1971

PARTIES:

Employers in relation to the management of Damra Colliery of Messrs Katras Jherriah Coal Company Limited,

AND

Their workmen.

PRESENT:

Sr Sl N. Bagchi, Presiding Officer.

On behalf of Employers.—

Shri D. Narsingh, Advocate.

On behalf of Workmen.—

Absent.

STATE: West Bengal.

INDUSTRY: Coal Mine.

AWARD

By Order No. L/1912/54/71-LRII, dated 17th June, 1971, the Government of India, in the Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation (Department of Labour and Employment), referred the following industrial dispute existing between the employers in relation to the management of Damra Colliery of Messrs Katras Jherriah Coal Company Limited and their workmen, to this Tribunal, for adjudication, namely:

"Whether the refusal of work to Shri Rambodh Ahir, Onsetter, from the 20th May, 1970 to the 29th June, 1970 by the management of Damra Colliery of Messrs Katras Jherriah Coal Company Limited, Post Office Kalipahari, District Burdwan is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. In this reference the management is present through Mr. D. Narsingh, Advocate. The union in spite of notice did not even file the written statement but the management did file their written statement as well as their documents. Notices were duly served on the union that espoused the cause of the workman in the dispute. To-day is fixed for positive hearing of the dispute but nobody appears on behalf of the workmen.

3. Accordingly the tribunal considers that there is no dispute now and renders this award as 'no-dispute' award.

Dated, 13th July, 1972.

(Sd.) S. N. BAGCHI,
Presiding Officer.

[No. L-1912/54/71-LR.II.]

S.O. 2085.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Hyderabad, in the industrial dispute between the employers in relation to the Sigareni Collieries Company, Limited, Post Office Kothagudem Collieries (Andhra Pradesh), and their workmen, which was received by the Central Government on the 15th July, 1972.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

PRESENT:

Sri P. S. Ananth, B.Sc., B.L., Chairman, Industrial Tribunal, Andhra Pradesh, Hyderabad.

INDUSTRIAL DISPUTE No. 11 OF 1971

BETWEEN

Workmen of Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli Division.

AND

Management of Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli Division.

APPEARANCES:

Sri M. Shyam Mohan, Personnel Officer, Singareni Collieries Company Limited, for Respondent.

None present for Petitioner.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) by its Order No. 7/12/70-LR.II, dated 10th December, 1970, referred the following dispute under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter referred to as the said Act) for adjudication by this Tribunal namely,

"Whether the action of the management of singareni Collieries Company Limited, in refusing to count the previous piece-rate services of Sarvashri 1. Dasari Ellaiah, 2. Musala Mallaiah, 3. Sunkari Posham. 4. Mudari Rajam, 5. Buddsrao Chandraiah, 6. Tombari Lachumaiah 7. Patha Odeloo, 8. Palle Rayamaloo and 9. Borlakunata Durgaiah, Bank Mazdoors and Sarvashri 1. Durgam Lingaiah, 2. Jotti Narsaiah and 3. Kha Jamiyya, Bank Muccadams of Morgans Pit for the purpose of granting service increments and for refixing wages at the time of the implementation of the recommendations of Wage Board, is justified? If not, to what relief are the workman entitled?"

This reference was taken on file as Industrial Dispute No. 11 of 1971 and notices were issued to the parties. For the purpose of convenience the Workmen of Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli Division are referred to as the Petitioners and the Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli Division is referred to as the respondent in the course of this award.

2. The Vice President of the Singareni Collieries Workers Union, Bellampalli Division filed a claims statement on behalf of the workmen contending that the claimants Sarvashri Dasari Ellaiah, 2. Measala Mallaiah, (3) Sunkari Posham, (4) Akudari Rajam, (5) Buddsrap Chandraiah, (6) Imbadi Chandraiah, (7) Patha Odellu, (8) Palle Rayamullu and (9) Borlakunta Durgaiah Bank Mazdoors and Sarvashri Durgam Lingaiah, (2) Getti Narsaiah and (3) Khajamiyya Bank Muccadams of Morgans Pit were appointed on 20th August 1957 as piece rated loading and unloading mazdoors, and they were converted into time rated bank mazdoors and bank muccadams with effect from 21st August 1961 and fixed in the old category of IV and VI respectively, that their fixation of wages in category IV and VI was much less than the average wages they were earning and so they raised a dispute and settlement was arrived at on 2nd September 1967 under which they were given three advance increments for their 3 years service in piece rate, that similar was the case with the time rated workers transferred from the piece rated fillers, that after the new Wage Board recommendations have come up the Management did

not count their piece rate service for granting service increments and so they raised a dispute, that though the Management granted correct number of service increments to time rated workers, who were previously working as piece rated fillers, they did not extend the benefits to the claimants and that they are eligible to get three service increments with effect from 15th August 1967 but they were paid only one service increment.

3. The Respondent in its counter contended that the claimants themselves admitted that they were piece rated loading and unloading mazdoors, that they were appointed as bank mazdoors and some were promoted as bank mazdoors in higher category, that the wage fixation in categories IV and VI was correctly done, that the circular issued by the Management made it clear that what applied to fillers is only between the categories I to V and without transfer as a daily rated man and that if filler is transferred to Category VI or category VI special as Coal Cutter or any other higher category, the service rendered by them as filler should not be taken into account, and that the respondent is justified in refusing to count the period of piece rated service.

4. The matter was adjourned from time to time at the request of the parties and finally on 2nd May 1972 a representation was made by the Vice President of the Union that talks of settlement were going on and so further time was granted to see whether the parties would settle the matter. On 28th June 1972 a joint memo of compromise was filed stating that an award may be passed in terms of compromise and the same was recorded. The claimants contention is that they should be given three service increments with effect from 15th August 1967 taking into consideration their piece rate service. Whereas the Management had given one service increment. The contention of the respondent is that the piece rated service cannot be counted for the purpose of service increments now. It is seen from the memo of compromise that it was agreed between the parties that the respondent should give one extra increment in their category so far as eight gang mazdoors are concerned and so far as three gang muccadams are concerned the parties had agreed that since their service of three years was already reckoned and since they were given one increment correctly there was no other relief that could be granted to them. I am satisfied that the compromise entered into between the parties is fair, considering the nature of the dispute.

5. In the result an award is passed in terms of the compromise and a copy of the memo of compromise shall be attached to the Award.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 1st day of July, 1972.

(Sd.) P. S. ANANTH,

Industrial Tribunal.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

Industrial Dispute No. 11/1971

The Workmen of Singareni Collieries Company Ltd., Bellampalli Division represented by the Vice President, Singareni Collieries Workers Union, Bellampalli.

Vs.

The Management of Singareni Collieries Company Ltd., Bellampalli Division.

Memo of Compromise.

Most respectfully sheweth:

That, without prejudice to the contentions made in the claim and counter statements, the parties have resolved the dispute amicably on the following lines:

(a) That the concerned 8 Bank Mazdoors will be given one extra increment in their category with effect from 15th August, 1967.

(b) That Borla Kunta Durgaiah is not in service and he is not eligible to draw any difference of amount.

(c) That the 3 Bank Muccadams, *viz.*, Durgam Lingaiah, jatti Narsaiah, Khaja Miya having been promoted with effect from 9th January, 1963 from the lower category and their service of 3 years is reckoned and they are given one increment correctly, there is no other relief to be shown to this category of Muccadams.

Under the above circumstances, asa special case the matter is fully and finally settled. The parties pray that an award may be passed in terms of compromise the Petitioners, therefore, humbly prey that an Award in terms of the settlement may be passed.

(Sd.) B. GANGARAM,	(Sd.) M. SHYAM MOHAN,
Vice-President,	Personnel Officer,
The Singareni Collieries	The S. C. Co. Ltd.,
Workers Union,	Bellampalli.
Bellampalli.	
WORKMEN.	MANAGEMENT.

WITNESSES:

(Sd.) * * * , AHC, Labour Office.

(Sd.) * * * , Steno, Labour Office.

Bellampalli, the 12th June, 1972.

(Sd.) P. S. ANANTH,
Industrial Tribunal.

[No. 7/12/70-LR.II.]

S.O. 2086.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the folowing award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bhowra Colliery of Messrs Oriental Coal Company Limited, Post Office Bhowra, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 18th July, 1972.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT:

Shri Nandagiri Venkata Rao, Presiding Officer.

REFERENCE No. 43 OF 1971.

In the matter of an industrial dispute under S.10(1) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

PARTIES:

Employers in relation to the management of Bhowra Colliery of Messrs Oriental Coal Company Limited, Post Office Bhowra, District Dhanbad.

AND

Their workmen.

APPEARANCES:

On behalf of the employers in relation to the management of Bhowra Colliery of Messrs Oriental Coal Company Limited.—Shri B. M. Lal, Personnel Officer.

On behalf of Bharat Coking Coal Ltd.—Shri S. S. Mukherjee Advocate.

On behalf of the workmen.—None.

State: Bihar. Industry: Coal.

Dhanbad, 15th July 1972

AWARD

The Central Government, being of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Bhowra Colliery of Messrs Oriental Coal Company Limited, Post Office Bhowra, District Dhanbad and their workmen, by its order No. 2/170/70-LR.II, dated 16th April 1971 referred to this Tribunal under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication the dispute in respect of the matters specified in the schedule annexed thereto. The schedule is extracted below:

SCHEDULE

(i) Whether the management of Bhowra Colliery of Messrs Oriental Coal Company Limited, Post Office Bhowra, District Dhanbad, was justified in refusing to pay Shri Bhola Nath Singh, Bleaching Power Mazdoor, the wages of Category-I as per recommendations of the Central Wage Board for Coal Mining Industry with effect from the 15th August, 1970, If not, to what relief is the workman entitled?

(ii) Whether the said management was justified in stopping the said workman from work with effect from the 11th September, 1970? If not, to what relief is he entitled "

2. Parties filed their statement of demands. Bharat Coking Coal Ltd. also filed their statement of demands.

3. On 15th June 1972 Shri B. M. Lal, Personnel Officer, Bhowra Colliery representing employers and Shri S. S. Mukherjee, Advocate representing Bharat Coking Coal Ltd. have filed a compromise memo and verified the contents as correct. The compromise memo was also signed by Shri Ram Mitra, Secretary, Bihar Koyala Mazdoor Sabha representing workmen and Shri B. M. Lal stated on oath that Shri Ram Mitra had signed the compromise memo in his presence and has also proved his signature. I consider the terms of compromise as favourable to the workmen in general and to the affected workman in particular. The compromise is, therefore, accepted and the award is made in terms of the compromise and submitted under S. 15 of the Industrial Disputes Act, 1947. The compromise memo is annexed herewith and is made part of the award.

(Sd.) N. VENKATA RAO,
Presiding Officer,
Central Govt. Industrial Tribunal,
(No. 2) Dhanbad.

BEFORE THE HON'BLE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. II) AT DHANBAD

In the matter of:—

REFERENCE No. 43 OF 1971.

PARTIES:

Employers in relation to Bhowra Colliery of Messrs Oriental Coal Co. Ltd.

AND

Their workmen.

Memorandum of Settlement

All the parties in the present proceedings have amicably settled the dispute involved in the present Reference on the terms hereinafter stated:—

(1) That Sri Bhola Nath Singh (Bleaching Powder Mazdoor) the workman concerned in the present Reference has already been reinstated as Bleaching Powder Supply Mazdoor with effect from the 17th March 1972 without back wages by the management of the Bhowra Colliery of Messrs Oriental Coal Company Limited. Since the said job did not involve eight hours daily duty, it was agreed by the concerned workman that he would also attend to some clerical job offered by the Manager/Agent for four hours every day in addition to the work of supplying Bleaching Powder daily at the Drinking Water Pump.

(2) That the period intervening from the date of refusal to pay wages (which gave rise to the present Reference) till the date of resumption of duty on 17th March 1972 shall, for the purpose of continuity of services, be treated as leave without pay, but the workman concerned will be eligible to proportionate leave or quarterly bonus provided he put in proportionate qualifying attendance during the remaining period of the current year or quarter ended 31st March 1972, as the case may be.

(3) That if there would be any vacancy in clerical cadre in future, the case of the concerned workman may be considered and he may be given first preference subject to his suitability for the clerical job so vacant.

(4) The above terms finally resolve the dispute between the parties and, therefore, there is no subsisting dispute for adjudication in the present Reference.

(5) The parties shall bear their own cost of proceedings.

It is, therefore, prayed that the Hon'ble Tribunal may be pleased to accept this Settlement and to give its Award in terms thereof.

For the Employers

(Sd.) N. K. SHARMA
Manager,
Bhowra Colliery.

(Sd.) Brij Mohanlall
Personnel Officer

For the Workmen

(Sd.) RAM MITRA,
Secretary,
Bihar Koyala Mazdoor Sabha.

Dated, 12th June, 1972.

For Bharat Coking Coal Ltd.
(Sd.) J. N. SAHI,
Labour & Law Adviser,
Bharat Coking Coal Ltd.

(Sd.) BHOLA NATH SINGH,
Mazdoor.
Bleeching Powder Supply Mazdoor
(Workman concerned).

(Sd.) Presiding Offier,
Central Govt. Industrial Tribunal (No.2)
Dhanbad.

N. VENKATA RAO,
[No. 2/170/70-LR.II.]

S.O. 2087.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Mahabir Colliery, Post Office Raniganj, District Burdwan and their workmen, which was received by the Central Government on the 14th July, 1972.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA.

REFERENCE No. 86 OF 1971

PARTIES:

Employers in relation to the management of Mahabir Colliery,

AND

Their workmen.

PRESENT:

Sri S. N. Bagchi .. ..Presiding Officer.

APPEARANCES:

On behalf of Employers Absent

On behalf of Workmen Absent

STATE: *West Bengal* INDUSTRY: *Coal Mine*

AWARD

By Order No. L-1912(65)/71-LRII, dated 29th June, 1971, the Government of India, in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), referred the following industrial dispute existing between the employers in relation to the management of Mahabir Colliery and their workmen, to this Tribunal, for adjudication, namely:

"Whether the action of the management of Mahabir Colliery, Post Office Raniganj, District Burdwan, in refusing employment to Sarvashri Gopal Hemram, Sankar Kajhi, Khepa Hemram, Sukhu Majhi, Badan Majhi and Lattu Hari, Pick-miners, with effect from 23rd February, 1971, 17th February, 1971, 23rd February, 1971, 15th February, 1971, 15th February, 1971, 15th February, 1971, respectively is justified. If not, to what relief are the workmen entitled?"

2. Nobody appears to-day either on behalf of the management or the workmen. The Union who raised the dispute was allowed to file written statement within 15 days from 15th June, 1972 when it appeared through one Mr. S. Mukherjee, Advocate. To-day none appears.

So I render a 'No-dispute' award in the matter.

S. N. BAGCHI, Presiding Officer.

[No. L-1912/65/71-DRII.]

S.O. 2088.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of East Chora Colliery, Post Office Bahula, District Burdwan and their workmen, which was received by the Central Government on the 14th July, 1972.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA.

REFERENCE NO. 89 OF 1971

PARTIES:

Employers in relation to the management of East Chora Colliery,

AND

Their workmen.

PRESENT:

Sri S. N. Bagchi ....Presiding Officer.

APPEARANCE:

On behalf of Employers Sri Monoj Kumar Mukherjee, Advocate.

On behalf of Workmen Sri Satyen Banerjee, Advocate.

STATE: West Bengal INDUSTRY: Coal Mines

AWARD

By Order No. L-1912/7/71-LR.II, dated 5th June, 1971 the Government of India, in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), referred the following industrial dispute existing between the management of East Chora Colliery and their workmen, to this Tribunal for adjudication, namely:

"Whether the management of East Chora Colliery, Post Office Bahula, District Burdwan are justified in stopping the work of Sarvashri Darshan Singh and Jaila Singh, Coal Cutting Machine Drivers with effect from the 16th August, 1969 and if not, to what relief the workmen are entitled?"

2. The management and workmen represented by their respective advocates signed a memorandum of compromise in this dispute and the dispute has been resolved in terms of the compromise. One of the workmen Sri Darshan Singh is present to-day. The terms of the compromise appear to be fair, equitable and beneficial to the interest of the workmen concerned. Accordingly, I record the terms of compromise and render an award in terms of the said compromise the memorandum of which shall form part of this award.

This is my award.

Dated 11-7-1972.

(Sd.) S. N. BAGCHI,
Presiding Officer.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA.

REFERENCE No. 98 OF 1972

Employers in relation to the management of East Chora Colliery;

AND

Their workmen.

The humble joint petition of the petitioners abovenamed

Most respectfully Sheweth:—

(1) That without going into the merits of their respective cases, the parties have amicably settled their disputes and differences giving rise to the instant reference on the following terms:—

(a) That the services of the concerned workmen shall be deemed to have been terminated with effect from 16th August, 1969, the date from which they left their employment.

(b) That the employers in consideration of such termination of employment, shall pay a sum of Rs. 2,000/-to Shri Darshan Singh who has put in a service of 2½ years (approximately) and a sum of Rs. 1,500/- to Shri Jaila Singh alias Jarnal Singh who has put in service of less than one year with the employers.

(c) That the concerned workmen have no other claim or claims against the employers.

(2) That the terms of compromise are fair, reasonable and equitable.

In the circumstances, the petitioners pray that the Hon'ble Tribunal may be pleased to pass an award in terms of the above compromise, treating this petition as a part of the award.

And as in duty bound, the petitioners shall ever pray.

(Sd.) S. N. RAM,

Dated 11-7-72 Add. Personnel Officer.

(Sd.) DARSHAN SINGH,

(Sd.) MONAJ KUMAR MUKHERJEE,

(Sd.) MAHENDRA NARAYAN SINGH Advocate.

(Sd.) S. N. BANERJEE, Advocate.

Representing the workmen. *Representing the employer.*

[No. L-1912/7/71-LR.II.]

New Delhi, the 27th July 1972

S.O. 2089.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of West Bokharo Colliery of Messrs West Bokharo Limited, Post Office Ghatotand,

District Hazaribagh and their workmen, which was received by the Central Government on the 18th July, 1972.

AWARD

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (No. 1), DHANBAD.

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

REFERENCE No. 73 OF 1971

PARTIES:

Employers in relation to the management of West Bokharo Colliery of Messrs West Bokharo Limited, Post Office Ghatotand, District Hazaribagh.

AND

Their Workmen.

PRESENT:

Shri A. C. Sen, Presiding Officer.

APPEARANCES:

For the Employers.—Shri S. S. Mukherjee, Advocate.

For the Workmen.—Shri S. Das Gupta, Advocate.

STATE: Bihar. INDUSTRY: Coal.

Dhanbad, dated the 5th July, 1972

AWARD

The present reference arises out of Order No. L/2012/145/71-LRII dated New Delhi, the 11th November, 1971 passed by the Central Government in respect of an industrial dispute between the parties mentioned above. The subject matter of the dispute has been specified in the schedule to the said order and the said schedule runs as follows:—

"Whether the employers in relation to West Bokharo Colliery of Messrs West Bokharo Limited, Post Office Ghatotand, District Hazaribagh, were justified in dismissing Shri A. K. Sarkar, Head Welder from services with effect from the 1st April, 1971? If not, to what relief the workmen is entitled?"

2. The concerned workmen has been dismissed from service on a charge of theft. According to the management, a steel wire rope of about 49 ft. was found missing in the morning of 15th February, 1971 from the ropeway haulage room and later it was found being used in the concerete mixure machine of M/s. Sons Construction Company, and on enquiry from one Jawahir Thakur, Machine Driver it was learnt that the steel rope was purchased from Shri A. K. Sarkar (workman concerned) on 14th February, 1971.

3. A chargesheet dated 18th February, 1971 was issued to the concerned workman charging him with stealing company's material and selling the same to Shri Jawahir Thakur. The concerned workman submitted his explanation dated 26th February, 1971 denying the charge.

4. A departmental enquiry was held in the presence of the concerned workmen who was given the opportunity of cross-examining the witnesses produced by the management and who, in fact, cross-examined many of them.

5. The Enquiry Officer found the concerned workman guilty of the charge levelled against him and submitted his report accordingly. The concerned workman was dismissed from service with effect from 1st April, 1971.

6. The validity of the dismissal has been challenged by the union on various grounds, one of them being that the charge could not be established against the workman concerned.

7. First of all I should like to consider whether the evidence before the domestic enquiry justifies the findings of the Enquiry Officer that the concerned workman is guilty of the misconduct alleged in the chargesheet. Altogether seven witnesses were examined on behalf of the management in support of the charge. Witness No. 7, Jawahir Thakur is the principal witness. Others deposed to what they had heard from witness No. 7, and, therefore, their evidence may be discribed as hearsay evidence.

8. The disputed steel rope was found in the possession of witness No. 7. According to the management this steel rope was stolen from the ropeway haulage room. It may be presumed that a man who is in possession of stolen goods soon after the theft is either the thief or has received the goods knowing them to be stolen, unless he can account for his possession. The theft is alleged to have been committed on 14th February, 1971 and the stolen property was found in the possession of witness No. 7 on 15th February, by witness No. 4, A preliminary enquiry on the spot took place on 16th February, 1971.

9. The explanation of witness No. 7 is that the steel rope in question was sold to him by the concerned workman at about 10 A.M. on 14th February, 1971, which was a Sunday. Witness No. 7 told witnesses Nos. 1 and 2 that he had paid Rs. 40/- to the concerned workman as the price of the steel rope. Witness No. 6 (six) also says that at the preliminary enquiry held on 16th February, 1971 witness No. 7 told to Mr. Banerjee who held the preliminary enquiry that the concerned workman had given him the rope on payment of Rs. 40. But in his examination in chief before the Enquiry Officer he said that the concerned workman asked Rs. 80 for the rope, that he paid Rs. 40 and promised to pay the balance of Rs. 40 on receiving receipt for the same. He is not consistent about the price. Moreover it is difficult to believe that he paid Rs. 40 to the concerned workman without taking any receipt.

10. At first he says that he could not give the concerned workman the price as Pantaki Babu was not at the site. Then he says, "At about 10 A.M. I gave Rs. 40 as price of the rope at that time and rest of Rs. 40 I promised to give him when he will give me the receipt for the same". He does not say from where he got the money to pay the price.

11. He has further said in his examination in chief that the concerned workman came to him at the site on 15th February, 1971 and asked for the balance of Rs. 40 when he told him that the loss of the steel rope had been detected by the company. But this fact he did not disclose to witness No. 1, Sri S. J. Banerjee when the latter held a preliminary enquiry on 16th February, 1971.

12. The above analysis of his evidence as to the payment of price makes it quite clear that he did not pay anything as the price of the steel rope.

13. In the beginning he has stated that when the concerned workman gave him the steel rope on 14th February, 1971 he told the latter not to give him stolen material. It seems he received the steel wire, knowing it to be stolen.

14. Witness No. 6 has told something very significant. I am quoting the relevant portion: "On 12th February, 1971 I was in II shift.....At about 7 P.M. I went to Gurubux Singh Tea Shop to take tea, while I was returning from the tea shop, the concerete Mixture Driver (Witness No. 7) asked me whether I will give him the rope which is lying in the haulage room. I told that it is not possible". So witness No. 7 had an eye on the steel rope in question even before the incident. Witness No. 5 also says that the witness No. 7 told something about Dichoo Orang.

15. It is clear that the conduct of witness No. 7 is not above suspicion. It is highly probable in the facts and

circumstances of the case that he did not dislose the real facts as to how the steel wire came into his possession. It is in evidence that he came to know the concerned workman, a welder, on the 10th or 11th of February, 1971 when he welded a spring. It is not unlikely that in order to save his skin he foisted the blame upon the concerned workman. In any event the Enquiry Officer was not justified in relying on the evidence of witness No. 7 whose conduct is not above suspicion.

16. According to witness No. 7, he got the steel rope from the concerned workman before 10 A.M. on 14th February, 1971 but he has not given the exact time. At the preliminary enquiry held on 16th February, 1971 he, however, stated that he got this rope from the concerned workman at about 10 A.M. on 14th February, 1971. Witness No. 1, S. J. Banerjee, Mechanical Engineer has stated in his cross-examination that the workman concerned did not go to the haulage room between 9 A.M. and 11 A.M. This witness has also stated that the concerned workman was engaged on 14th February, 1971 on welding job of the ropeway buckets between 9 A.M. to 11 A.M. and that once he went to take tea near the T.R.F. Site. He is not in a position to say how long he was away taking tea. Hence there is nothing on record to show that it was possible for the concerned workman to remove the steel wire from the haulage room and sell it to witness No. 7 at about 10 A.M. on 14th February, 1971.

17. The above discussion makes it abundantly clear that the evidence before the Enquiry Officer in support of the charge against the concerned workman was almost nil. I shall not be far wrong if I say that the finding of the Enquiry Officer is based on no evidence. Hence I regard it as perverse. The Enquiry Officer in his report has stated as follows: "M/s. Ramanathan, Gurubux, Gurdas Ram, Matin Ansary, Duchoo Oran and Sri Jawahir Thakur corroborated that the rope in question was missing from the haulage room and it has been sold to Shri Jawahir Thakur by Shri Sarkar as Shri Thakur admitted in their presence and also in the presence of Shri Sarkar that he had sold the steel rope to him". This finding is not worthy of consideration. The Enquiry Officer has no idea about corroboration, nor does he know when admission is relevant. The order of dismissal based on such perverse finding is liable to be set aside.

18. I accordingly find that the employers in relation to West Bokaro Colliery were not justified in dismissing Shri A. K. Sarkar, Head Welder from service with effect from the 1st April, 1971. He is entitled to be reinstated with back wages. I pass an award accordingly.

19. A copy of this award may be forwarded to the Central Government under section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

(Sd.) A. C. SEN, Presiding Officer.

[No. L/2012/145/71-LRII.]

New Delhi, the 28th July 1972

NOTIFICATION

S.O. 2090.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Buzdar Kajora Colliery, Post Office Kajoragram, District Burdwan and their workmen, which was received by the Central Government on the 24th July, 1972.

AWARD

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA.

REFERENCE No. 94 OF 1971

PARTIES:

Employers in relation to the management of Guzdar Kojra Colliery,

AND

Their workmen.

PRESENT:

Shri S. N. Bagchi, Presiding Officer.

APPEARANCES:

On behalf of Employers.—Shri Monoj Kumar Mukherjee, Advocate.

On behalf of Workmen.—Sri B. N. Bhattacharjee, Advocate.

STATE: West Bengal. INDUSTRY: Coal Mine.

AWARD

By Order No.L-1912/51/71-LR.II, dated 23rd July, 1971, the Government of India, in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), referred the following dispute existing between the employers in relation to the management of Guzdar Kajora Colliery and their workmen, to this Tribunal, for adjudication, namely:

"Whether the action of the management of Guzdar Kajora Colliery, Post Office Kajoragram, District Burdwan in retrenching Shri Ramashis Harijan, Loader with effect from 3rd July, 1970 is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The reference was registered on 2nd August, 1971. Notices calling upon the management and the union representing the workman to file their statement of demand regarding the issue under reference were served on the management on 9th August, 1971 and on the General Secretary of the union on 9th August, 1971. On 12th January, 1972, the management filed a written statement. 15th June, 1972 was fixed for fixing a date of hearing. On 15th June, 1972 the management appeared through its learned advocate Mr. Monoj Kumar Mukherjee and Mr. Sudhendu Mukherjee, Advocate appeared on behalf of the union. The management filed on 15th June, 1972 an additional written statement showing cause which was accepted. The union appearing through the learned Advocate Mr. S. Mukherjee filed no written statement but prayed for time for filing documents. On 15th June, 1972, in presence of the learned Advocate of the management and the union the hearing of the case was fixed positively on 17th July, 1972. The tribunal however directed that the union, if it liked might file its statement of case, serving an advance copy on the management within 10 days thereof with an endorsement to the effect that copy was served on the management. On 29th June, 1972 an aplication was forwarded to this Tribunal by the Union praying that the tribunal may call for certain documents from the management as mentioned in the application. The union was informed that as the union had not filed any written statement in the case so the question of calling for documents did not arise since it could not be decided without written statement as to the relevancy of the documents as prayed for to be called for at the instance of the union. So the prayer was rejected

3. On 17th July, 1972 when the case was called on for hearing the management appeared through its learned Advocate Mr. Monoj Kumar Mukherjee. Mr. B. N. Bhattacherjee, Advocate was authorised by the union to represent the case before this Tribunal. The case was opened. Mr. Mukherjee, the learned advocate for the management referring to the management's additional written statement which was filed in the presence of the learned Advocate of the union and was accepted without any objection on 15th June, 1972 submitted that as no demand in respect of the subject matter of the dispute having had been raised earlier by the workman or for the matter of that by the union with the employers before agitating the same with the Conciliation machinery, the present reference was bad in law, and submitted that on this preliminary point the reference ought to be rejected. The learned Advocate for the union Mr. Bhattacherjee submitted

that the union had not filed any written statement. To this Mr. Mukherjee submitted that the union had, therefore, admitted the management's case that no dispute was raised either by the workman or workmen or by the union representing the workman regarding the subject matter of the dispute before the management at any time, and that the union approached the Conciliation officer without first raising the dispute before the management which did not convert the alleged dispute into an industrial dispute in view of the decision in the case of Sindhu Resettlement Corporation Ltd., and Industrial Tribunal, Gujarat & Ors., reported in 1968 I LLJ p.834 and Fedders Lloyd Corporation Private Ltd. and Lt. Governor, Delhi and Ors., reported in F.L.R. 1970 (20) p 343, former by the Supreme Court of India and the latter by the Delhi High Court. The learned advocate, Mr. Bhatlacherjee, for the Union submitted that the workman was present at the Tribunal room and that he would counter the statement of the management by making a statement before the Tribunal. To this Mr. Mukherjee submitted that Rule 10B of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957 would not permit the workman to make out any case for the first time on witness box countering the management's case on the point. Rule 10B(1) reads as follows:

> "Where the Central Government refers any industrial dispute for adjudication to a Labour Court, Tribunal or National Tribunal, within two weeks of the date of receipt of the order of reference, the party representing workmen (or in the case of individual workman, the workman himself) and the employer involved in the dispute shall file with the Labour Court, Tribunal or National Tribunal, as the case may be, a statement of the demands relating only to the issues as are included in the order of reference and shall also forward a copy of such statement to each one of the opposite parties involved in the said dispute."

Referring to this rule Mr. Mukherjee submitted that the union representing the workman was bound to file under the rules a statement of case as the management did. After the management had filed its statement of case which was not traversed by any written statement filed by the union, the management filed an additional written statement which also was not countered by the union by filing a rejoinder. Mr. Mukherjee further submitted that the tribunal itself on 15th June, 1972 allowed the union *suo moto* to file its statement of case within 25th June, 1972 but the union did not take any step for filing the statement although on 15th June, 1972 in presence of the learned Advocate representing the union, the additional written statement of the management was accepted wherein it was specifically stated that before raising the dispute with the Conciliation officer neither the workman or the workmen nor the union representing the workman approached the management with the dispute relating to the subject matter under reference wherefor the dispute could not be considered in law as an industrial dispute. It is clear from sub-rule (1) of rule 10B of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957 that so soon as the union got the order of reference in this case (independent of the notice calling upon it to file its statement of demand relating to the dispute under reference), the union was required to file its written statement. It did not take any step on 15th June, 1972, 25th June, 1972 and 29th June, 1972 to file any statement of case with the clear knowledge of the contention raised by the management in its additional written statement. The rule, being obligatory, upon the union to file its statement of demand with an advance copy duly served on the management, the union cannot on the date of hearing, without disclosing its case produce the workman, and through him, make out a case for the first time without any previous notice of such case to the management. Both the management and the union are required under Sub-rule (1) of Rule 10B to file their statement of demand relating to the issue under reference before the tribunal within two weeks from the date of receipt of the order of reference forwarding a copy of such statement to each one of the opposite parties involved in the dispute i.e. the management on the union and the union on the management. Sub-rule (2) of the Rule 10B further says that after the statement by the management and the union are filed with the Tribunal, either of the parties may file rejoinder to counter the statement of either of the parties as the case may be and that also within two weeks from the date of the filing of the statement before the tribunal by the parties concerned. These rules are mandatory and are part of the law as has been laid down by their Lordships of the Supreme Court in the case of Delhi Cloth & General Mills Ltd., *vs* their workmen, reported in 1972 I LLJ p.99. The rules must, therefore, be obeyed and violation of the rule would be illegal. Therefore, the union had no right at this stage to produce the workman, and through him to make out a case to counter the case of the management orally on the witness box for the first time without any previous notice as to what the case of the union would be in opposition to the case as stated in the additional written statement filed by the management in presence of the lawyer representing the union without any objection, and accepted by the tribunal. Therefore, as contended by Mr. Mukherjee for the management, the management's case in the additional written statement must be accepted as has not been denied by the union representing the workman inspite of tribunal's direction given to the union on 15th June, 1972 to file its statement of case when the additional written statement of the management was accepted in presence of the learned Advocate representing the union. Accordingly, this tribunal holds that neither the workman nor the union representing the workman raised any dispute relating to the subject matter under reference with the management before approaching the Conciliation Officer *i.e.* the Government with the dispute which on failure of conciliation has been referred to this tribunal by the Government as an industrial dispute for adjudication. In view of the law which is now settled by the decisions of the Supreme Court to which Mr. Mukherjee made a reference, the dispute in question referred to for adjudication is not an industrial dispute under Section 2(k) of the Industrial Disputes Act. Accordingly, this tribunal cannot entertain the dispute under reference as an industrial dispute and cannot adjudicate upon it. The reference is, therefore, rejected.

This is my award.

(Sd.) S. N. BAGCHI,
Presiding Officer.

Dated the 19th July, 1972.

[No. L/19012/51/71-LRII.]

S.O. 2091.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Hyderabad, in a Petition filed under Section 33A of the Act by Shri Adguri Mallaiah, G. No. 1, Shanti Khani, Bellampalli, against the management of Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli Division, which was received by the Central Government on the 13th July, 1972.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD.

PRESENT:

Shri P. S. Ananth, B.Sc. B.L., Chairman, Industrial Tribunal (C), Andhra Pradesh, Hyderabad.

MISCELLANEOUS PETITION NO. 65 OF 1972

IN

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 30 OF 1967

BETWEEN

Adguri Mallaiah, C. No. 1, Shanti Khani, Bellampalli.—*Petitioner.*

AND

Management of Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli Division.—*Respondent.*

APPEARANCES:

Sri Adguri Mallaiah (himself) *for petitioner.*
Sri M. Shyam Mohan, Personnel Officer, *for respondent.*

AWARD

This is a petition filed under Section 33A of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter referred to as the said Act) for directing the respondent to reinstate the petitioner with back wages from 23rd December, 1971.

2. The petitioner in his petition contended as follows: The Management dismissed the petitioner without conducting proper enquiry. Fair opportunity was not given to him to produce the witnesses to defend his case and the Management has dismissed the petitioner with a grudge that he is an active worker of Sigareni Collieries Workers' Union. There is no proof that the petitioner deliberately obstructed the fillers of machine No. 2 from going to 43 dip, which is the main charge against the petitioner. The management issued charge sheet to six fillers including the petitioner but it had taken action only against two fillers including the petitioner, which is nothing but discrimination. The enquiry is not fair and the enquiry officer put leading questions and cross examined the petitioner and the enquiry officer wrote wrong things which the petitioner never stated. The action of the Management in dismissing the petitioner is wrongful, illegal and against the principles of natural justice and so the petitioner should be reinstated with back wages.

3. The respondent in its counter contended that the petitioner fully participated in the enquiry, that full opportunity was given to him, that the enquiry officer after carefully going through the matter submitted his report, that there has been no breach of principles of natural justice and victimisation and that the petition filed by the respondent under Section 33(2)(b) of the said Act may be heard in the first instance.

4. After the filing of the counter the petition was posted for enquiry to 5th July, 1972. On that date a petition was filed by the petitioner through the Vice-President of Singareni Collieries Workers' Union, who had attested the petition, requesting for permission to withdraw the petition filed by the petitioner. In the petition it is stated that the Menagement considered his case sympathetically and that the Management had agreed to take him on his previous job as filler and that there is also no claim for arrears of wages and so he may be permitted to withdraw the petition. In view of the reasons urged in the present petition filed for permission to withdraw the petition, the petitioner is permitted to withdraw the main petition.

Award is passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 6th day of July, 1972.

(Sd.) P. S. ANANTH,
Industrial Tribunal.

APPENDIX OF EVIDENCE
Nil.

[No. 7/21/67-LR.II(i).]

S.O. 2092.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Hyderabad, in a petition filed under Section 33A of the Act by Shri Kasarla Mallaiah, G. No. 1, Shanti Khani, Bellampalli, against the management of Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli, which was received by the Central Government on the 13th July, 1972.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

PRESENT:

Sri P. S. Ananth, B.Sc.,B.L., Chairman, Industrial Tribunal (C), Andhra Pradesh, Hyderabad.

MISCELLANEOUS PETIOTION No. 66 OF 1972

IN

INDUSTRIAL DISPUTE No. 30 OF 1967

BETWEEN:

Kasarla Mallaiah, G. No. 1, Shanti Khani, Bellampalli.—*Petitioner.*

AND

The Management, Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli.—*Respondent.*

APPEARANCES:

Sri Kasarla Mallaiah (himself) *for Petitioner.*
Sri M. Syam Mohan, Personnel Officer, *for respondent.*

AWARD

This is a petition filed under Section 33A of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter referred to as the said Act) for directing the respondent to reinstate the petitioner with back wages from 23rd December, 1971.

2. The petitioner in his petition contended as follows: The Management dismissed the petitioner without conducting proper enquiry. Fair opportunity was not given to him to produce the witnesses to defend his case and the Management has dismissed the petitioner with a grudge that he is an active worker of Singareni Collieries Workers' Union. There is no proof that the petitioner deliberately obstructed the fillers of machine No. 2 from going to 43 dip, which is the main charge against the petitioner. The Management issued charge sheet to six fillers including the petitioner but it had taken action only against two fillers including the petitioner, which is nothing but discrimination. The enquiry is not fair and the enquiry officer put leading questions and cross examined the petitioner and the enquiry officer wrote wrong things which the petitioner never stated. The action of the management in dismissing the petitioner is wrongful, illegal and against the principles of natural justice and so the petitioner should be reinstated with back wages.

3. The respondent in its counter contended that the petitioner fully participated in the enquiry that full opportunity was given to him, that the enquiry officer after carefully going through the matter submitted his report, that there has been no breach of principles of natural justice and victimisation and that the petition filed by the respondent under Section 33(2)(b) of the said Act may be heard in the first instance.

4. After the filing of the counter, the petition was posted for enquiry to 5th July, 1972. On that date a petition was filed by the petitioner through the Vice-President of Singareni Collieries Workers' Union, who had attested the petition, requesting for permission to withdraw the petition filed by the petitioner. In the petition it is stated that the Management considered his case sympathetically and that the Management had agreed to take him on his previous job as filler and that there is also no claim for arrears of wages and so he may be permitted to withdraw the petition. In view of the reasons urged in the present petition filed for permission to withdraw the petition, the petitioner is permitted to withdraw the main petition.

Award is passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal this the 6th day of July, 1972.

(Sd.) P. S. ANANTH,
Industrial Tribunal.

APPENDIX OF EVIDENCE

Nil.

Industrial Tribunal.

[No. 7/21/67-LR.II-(ii).]

ORDERS

New Delhi, the 6th April 1972

S.O. 2093.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of North East Salanpur Colliery, Post Office Samdi, District Burdwan and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of North East Salanpur Colliery, Post Office Samdi, District Burdwan, in dismissing from service Shri Charu Chandra Mahata, Mining Sirdar, with effect from the 4th December 1971, is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

[No. L/19012/18/72-LRII.]

(श्रम और रोजगार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 अप्रैल 1972

का० आ० 2093.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध, अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में नार्थ ईस्ट सालनपुर कोलयरी, डाकखाना समदी, जिला वर्दवान के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्याय-निणयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या नार्थ ईस्ट सालनपुर कोलयरी, डाकखाना समदी, जिला वर्दवान के प्रबन्ध मण्डल के श्री चारू चन्द्रा महाता, खनन सरदार को 4 दिसम्बर, 1971 से पदच्युत करने को कायम्राही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[सं० एल०/19012/18/72-एल०आर०-2]

New Delhi, the 13th April 1972

S.O. 2094.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of South Jhagrakhand Colliery of Messrs Jhagrakhand Collieries Private Limited, Post Office Jhagrakhand Colliery, District Surguja (Madhya Pradesh), and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the demand of the Madhya Pradesh Colliery Workers Federation for placing Shri Jugal Kishore, Fitter, in Category V as per the recommendations of the Central Wage Board for Coal Mining Industry is justified? If so, to what relief is the workman entitled?"

[No. L/22011/11/71-LRII.]

नई दिल्ली, 13 अप्रैल 1972

का० आ० 2094.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मसर्स झागरखण्ड कोलियरी प्राईवेट लिमिटेड की दक्षिण झागराखण्ड कोलियरी, डाकघर झागराखण्ड कोलियरी, जिला सरगूजा (मध्य प्रदेश) के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जबलपुर, को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या मध्य प्रदेश कोलियरी कर्मकार संघ की कोयला खनन उद्योग के केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार श्री जुगलकिशोर, फिटर, को प्रवर्ग-5 में रखने की मांग न्यायोचित है ? यदि हां, तो वह कर्मकार किस अनुतोष, का हकदार है ?"

[संख्या एल०/22011/11/71-एल०आर०-

New Delhi, the 17th April 1972

S.O. 2095.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Junewani Manganese Mine of Messrs Khandelwal Ferro Alloys Limited, Post Office Junewani, District Nagpur, and their workmen, in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication, to the Central Government Industrial Tribunal, (No. 2), Bombay, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the Management of Junewani Manganese Mine of Messrs Khandelwal Ferro Alloys Limited, Post Office Junewani, District Nagpur, in terminating the services of Shri Ram Lal, Son of Shri Talkul, Labourer, with effect from the 11th June, 1971, is jusitified? If not, to what relief is he entitled?"

[No. L/27012/1/12-LRIV.]

नई दिल्ली, 17 अप्रैल 1972

का०आ० 2095.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स खांडेलवाल फैरो एलाएज़ लिमिटेड कीं जूनेवानी मेंगनीज़ माइन, डाकघर, जूनेबानी, जिला नागपुर के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1957 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (संख्या 2) मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या मैसर्स खांडेलवाल फैरो एलाएज़ लिमिटेड की जूनेवानी मेंगनीज़ माइन, डाकघर जूनेबानी, जिला नागपुर के प्रबन्ध मण्डल की श्री तालकुल के पुत्र श्री रामलाल श्रमिक, की सेवाओं को 11 जून, 1971 से समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो वह किस अनुतोष का हकदार है ?"

[संख्या एल०-27012/1/72-एल०आर० 4]

New Delhi, the 18th April 1972

S.O. 2096.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Victory Colliery (G.L. Group) of Messrs Coal Products Private Limited, Post Office Gogla, District Burdwan and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the management of Victory Colliery (G.L. Group) of Messrs Coal Products Private Limited, Post Office Gogla, District Burdwan, are justified in stopping Shri Marman Turi, Surface Trammer, from work with effect from the 29th June, 1971? If not, to what relief is the workman entitled?'

[No. L/19012/5/72-LRII.]

नई दिल्ली, 18 अप्रैल 1972

का० आ० 2096.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध, अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स कोल प्रॉडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड की विक्टरी कोलियरी (जी० एल० ग्रुप), डाकघर गोगला, जिला बर्दवान के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या मैसर्स कोल प्रॉडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड की विक्टरी कोलियरी (जी० एल० ग्रुप) डाकघर गोगला, जिला बर्दवान के प्रबन्धमण्डल का, श्री मारमन तुरी, सरफेस ट्रैमर को, 29 जून, 1971 से काम करने से रोकना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[सं० एल०/19012/5/72-एल०आर०-2]

S.O. 2097.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Kumardihi Colliery (Kumardihi Coal Company), Post Office Ukhra, District Burdwan and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Kumardihi Colliery,, Kumardihi Coal Company

Post Office Ukhra, District Burdwan in suspending Shri Nani Gopal Mukherjee, Mining Sirdar with effect from the 7th October, 1970 and subsequently terminating his services with effect from the 20th October, 1970 is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

[No. L/19012/7/72-LRII.]

का० आ० 2097.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में कुमारडही कोलियरी (कुमारडही कोल कम्पनी), डाकघर उखरा, जिला बर्दवान के प्रबन्ध से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या कुमराडाही कोलियरी कुमारडीही कोल कम्पनी, डाकघर उखरा, जिला बर्दवान के प्रबन्ध मण्डल को, श्री नानो गोपाल मुखर्जी, माईनिंग सरदार को 7 अक्टूबर, 1970 से मुअत्तल करने और तत्पश्चात 20 अक्टूबर, 1970 से उसकी सेवाएँ समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो वह कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल/19012/7/72-एल० आर० 2]

S.O. 2098.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Bankola Colliery of Messrs Burrakur Coal Company Limited, Post Office Ukhra, District Burdwan and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Bankola Colliery of Messrs Burrakur Coal Company Limited, Post Office Ukhra, District Burdwan, in suspending Shri Parsuram Sharma, Chaprasi, with effect from the 11th October, 1971 to the 21st October, 1971 is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

[No. L/19012/3/72-LRII.]

का० आ० 2098.—यतः केन्द्रीय सरकार की रायहै कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स बुर्राकूर कोल कम्पनी लिमिटेड को बंकोला कोलियरी, डाकघर उखरा जिला बर्दवान के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है :

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या मैसर्स बुर्राकुर कोल कम्पनी लिमिटेड, की बंकोला कोलियरी, डाकघर उखरा, जिला बर्दवान के प्रबन्धमण्डल की श्री परसुराम शर्मा, चपरासी को 11 अक्टूबर, 1971 से 21 अक्टूबर, 1971 तक मुअत्तल करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो वह कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[संख्या एल०/19012/3/72-एल० आर० 2]

New Delhi, the 20th April 1972

S.O. 2099.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Ganhoodih Colliery of Messrs The East Ganhoodih Colliery Company Private Limited, Post Office Jharia, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Infustrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 1), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Ganhoodih Colliery of Messrs The East Ganhoodih Colliery Company Private Limited, Post Office Jharia, District Dhanbad in dismissing Shri B. N. Tewary, Lamp Charger with effect from the 12th June, 1971, is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

[No. L/2012/222/71-LRII.]

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1972

का० आ० 2099.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स ईस्ट गनहूडीह कोलियरी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड को गनहूडीह कोलियरी, डाकघर झरिया, जिला धनबाद, के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (संख्या 1), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या मैसर्स ईस्ट गनहूडीह कोलियरी कम्पनी कोल प्राइवेट लिमिटेड की गनहूडीह कोलियरी, डाकघर झरिया, जिला धनबाद के प्रबन्ध मण्डल की श्री बी०एन० तिवारी, लैंप चार्जर को 12 जून, 1971 से पदच्युत करने की कार्रवाही न्यायोचित है? यदि नहीं, तो वह कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?"

[संख्या एल० 2012/222/71-एल० आर० 2]

New Delhi, the 22nd April 1972

S.O. 2100.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Geodetic Coal Company, Managing Contractor of Block No. 1, Kedla Colliery, Post Office Kedla, District Hazaribagh and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 1), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

1. "Whether the lay-off of the following eight workmen declared from the 7th January, 1972 by the management of Messrs Geodetic Coal Company, Managing Contractors of Block No. 1 of Kedla Colliery, Post Office Kedla, District Hazaribagh is justified? If not, to what relief are the said workmen entitled?

   1. Shri Mangal Singh,
   2. Shri Nityanand Singh,
   3. Shri Promod Misra,
   4. Shri Raghunath Pramanik,
   5. Shri Anirudh Singh,
   6. Shri Muhammad Jamiruddin,
   7. Shri Jafirul Husan, and
   8. Shri Prabhu Narain Singh."

2. Whether the stoppage from the 1st July, 1971 from work of Shri Sachidanand Singh employed as Cashier by the management of Messrs Geodetic Coal Company, Managing Contractor, Block No. 1 of Kedla Colliery, Post Office Kedla Colliery, District Hazaribagh is justified? If not to what relief is he entitled?"

[No. L/20012/19/72-LRII.]

KARNAIL SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1972

[का० आ० 2100.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स जिओडटिक कोल कम्पनी, ब्लाक संख्या—1 का प्रबन्ध ठेकेदार, केदला कोलियरी, डाकघर केदला, जिला हजारी बाग के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्याय निर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (संख्या 1), धनबाद को न्याय निर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

1 "क्या मैसर्स जिओडटिक कोल कम्पनी, केदला कोलियरी खान के ब्लाक संख्या—1 के प्रबन्ध ठेकेदार, डाकघर केदला, जिला हजारी बाग के प्रबन्ध मण्डल द्वारा निम्नलिखित आठ कर्मकारों की 7 जनवरी, 1972 से घोषित की गई कामबन्दी न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है ?

   1. श्री मंगल सिंह,
   2. श्री नित्यानन्द सिंह,
   3. श्री प्रोमोद मिश्र
   4. श्री रघुनाथ प्रमाणिक,
   5. श्री अनिरुद्ध सिंह,
   6. श्री मुहम्मद जमीरुद्दीन,
   7. श्री जफीरुल हसन, और
   8. श्री प्रभु नारायण सिंह ।

2. "क्या मैसर्स जिओडटिक कोल कम्पनी, केदला कोलियरी के ब्लाक संख्या—1 के प्रबन्ध ठेकेदार, डाकघर केदला, जिला हजारी बाग के प्रबन्ध मण्डल द्वारा रोकड़िया के रूप में नियोजित श्री सच्चिदानन्द सिंह को 1 जुलाई, 1971 से कार्य करने से रोकना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो वह किस अनुतोष का हकदार है ?"

[संख्या एल०/20012/19/72—एल० आर०—2]

करनैल सिंह, अवर सचिव ।

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 24th July 1972

S.O. 2101.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the Eagle Star Insurance Company, Limited and their workman, which was received by the Central Government on the 15th July, 1972.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

REFERENCE No. CGIT-2/3 OF 1971

Employers in Relation to the Eagle Star Insurance Company Limited.

AND

Their Workmen.

PRESENT:

Shri N. K. Vani, Presiding Officer.

APPEARANCES:

For the Employers.—(1) Shri S. V. Mokashi, Labour Adviser.

(2) Shri M. A. Mitha, Secretary.

For the Workmen.—Shri J. G. Gadkari, Advocate.

STATE: Maharashtra. INDUSTRY: General Insurance.

Bombay, the 21st June, 1972

AWARD

By order No. L.17012/4/71-LR.I dated 27th March, 1971 the Central Government in the Ministry of Labour Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 10 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947) referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute existing between the employers in relation to the Eagle Star Insurance Company Limited, Bombay and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule as mentioned below:—

SCHEDULE

"Whether Eagle Star Insurance Company Limited, was justified in retrenching Shri A. A. Anjilla, Driver with effect from the 31st January, 1969 (correct date 31-1-70). If not, to what relief is he entitled?"

2. The facts giving rise to this reference are as follows:—

(i) The Eagle Star Insurance Company Limited (hereinafter referred to as 'the company') decided to discontinue the facility of the use of the company's car to the Junior Executives. On account of the discontinuance of the facility to the Junior Executives one car was disposed of by the company on 30th January, 1970 and the Driver Shri A. A. Anjilla, who was the Junior most in the category of Drivers was retrenched by the Company after following the procedure laid down in the Industrial Disputes Act, 1947, with effect from 31-1-1970.

(ii) The General Insurance Employees Union, Bombay raised an industrial dispute in connection with the retrenchment of Shri Anjilla. As the matter could not be settled in joint negotiations, both the parties made an application to the Govt. of India to refer the dispute for adjudication of an Industrial Tribunal. On account of this Government of India refered this dispute to this Tribunal.

3. The company has filed written statement at Ex. 1/E.

4. According to the company,

(i) It appointed Shri Anjilla as a Driver on 16th May, 1967. He was retrenched from service of the company on 31st January, 1970.

(ii) As it decided to discontinue the facility of the use of company's car to the Junior Executives one car was disposed of and the Driver Shri Anjilla who was the junior most in the category of Drivers, was retrenched by the company after following the procedure laid down in the I.D.Act, 1947.

(iii) As Shri Anjilla was the Junior-most Driver in its service, he was served with a letter terminating his service with effect from 31st January,1970 after working hours. He was tendered notice pay of Rs. 324 and retrenchment compensation of Rs. 486 on 31st January, 1970, but he did not accept the same.

(iv) As there was no work to offer to him after disposal of car No. MRC 5707, which was driven by him, he was retrenched. It followed the principle of 'last come first go'. His retrenchment was proper and for bonafide reasons. Since the retrenchment of Shri Anjilla, it has not appointed any other driven in their service. As Shri Anjilla was found surplus to the requirements of the company, there is no case for his reinstatement and for granting any relief.

5. The General Secretary of the General Insurance Employees Union, Western Zone, Bombay (hereinafter referred to as 'the Union') has filed written statement at Ex. 2/W.

6. According to the Union,

(i) The company is a company under writing general insurance business and employs about 134 workmen in the City of Bombay.

(ii) The company had eight Motor cars utilised by its officers at Bombay office and five drivers employed for the same purpose. In the month of January, 1970 the company in order to rationalise its working force, disposed of one car and retrenched one Driver under false pretext that the said driver had become surplus due to the disposal of the car. In fact the said car was sold after the said driver was allegedly retrenched from the employment of the company.

(iii) Shri Anjilla was in the employment of the company from 16th May, 1967 and was removed from service on 31st January, 1970.

(iv) Shri Anjilla was in the employment of the company had increased the workload on the drivers and retrenched Shri Anjilla with a malafide motive of illegally, improperly and unfairly increasing the workload on the other drivers.

(v) The Company's action in removing Shri Anjilla on the ground that it discontinued the facility of use of company's car to the Junior Executive and because on account of this one car was disposed of amounts to rationalisation. Such rationalisaton leads to retrenchment and further reduction in the number of the persons employed in the occupation of Drivers. This amounts to change in the service conditions of the Drivers. It was therefore necessary for the company to give Notice of change as required under Section 9 of the I.D. Act, 1947. As it illegal and invalid.

(vi) After the retrenchment of Shri Anjilla, another Driver Shri C. Fernandes went on long sick leave due to some acute sickness. The vacancy arisen therefrom was filled in by the company by employing a fresh hand without giving an opportunity to Shri Anjilla for re-employment. This action of the company is in violation of Section 25(II) of the I.D. Act, 1947. It makes the continued non-employment of Shri Anjilla by the company illegal and improper. Shri Anjilla's retrenchment be held illegal and improper and he be reinstated with full back wages.

7. The company has filed rejoinder at Ex. 3/E.

8. According to the company,

(i) In the month of January, 1970 the company used 8 cars. The company provided the facility of drivers in respect of certain cars used by the officers. In some cases though the cars were owned by the company, no Driver was provided by the company but these cars used to be driven by the officers concerned.

(ii) It is not true that in order to rationalise its working forces it disposed of one car driver under false pretext that he had become surplus due to disposal of the car, the reasons for retrenchment of the driver was that the company decided to discontinue the facility of the use of company's car to the Junior Executives. Due to discontinuance of this facility for the Junior Executives one car was disposed of by the company and the Driver Shri Anjilla who was the junior-most in the category of drivers was retrenched with effect from 31st January, 1970, and not 31st January, January, 1969 as stated by the Govt. in the terms of reference. It sold the car No. MRC 5707 driven by Shri Anjilla on 30th January, 1970 and retrenched the said driver with effect from 31st January, 1970. It is not correct that the car was sold after the Driver was retrenched.

(iii) It is not correct that Shri Anjilla was retrenched with a malafide motive and as a result the workload on other drivers has increased. The Drivers were and are working for their normal duty hours and the question of increase in the workload does not arise.

(iv) Car No. MRC 5707 was used by two Junior Executives, *viz.*, S/shri Gumaste and Mitha. Shri Gumaste was transferred to U. K. on December 1969 and thereafter the company decided not to continue the facility of free use of the company's car available to one remaining Junior Executive. It was within its discretion to discontinue the free use of the company's car to one of the Junior Officers. As the car was disposed of by it, it was necessary to retrench one driver.

(v) Provisions of Section 9A of the Industrial Disputes Act, 1947 are not attracted as retrenchment of a workman does not amount to change in the conditions of service. The retrenchment of Shri Anjilla was not illegal and invalid.

(vi) Shri C. Fernandes who used to drive the car of Shri M. P. Lala proceeded on privilege leave on 15th December, 1970 for a month. Thereafter he applied for sick leave for one month which was granted. Hence a driver on temporary basis was appointed. Shri Fernandes extended leave from time to time upto 15th May, 1971 with the result that the temporary appointment of the driver has to be continued during the period 15th December, 1970 to 15th May, 1971. The service of the temporary Driver who was appointed in his place during the period of his sickness has been terminated on 15th May, 1971. It had learned realiably through a member of the staff that Shri Anjilla has already secured employment elsewhere and was not available for temporary work. Its action of retrenching Shri Anjilla be upheld and his demands be rejected.

9. Shri Anjilla has given evidence at Ex. 14/W. He has examined one witness Shri Andrew P. Serrao at Ex. 4/W on his behalf.

10. Shri M. Mitha, Secretary and staff officer of the Company has given evidence at Ex. 15/E on behalf of the company. The company has produced documents at Ex. 5/E to 13/E.

11. From the pleadings and documents on record the following points arise for decision in this dispute.

(i) Whether Eagle Star Insurance Company Limited, Bombay was justified in retrenching Shri A. A. Anjilla, Driver from service with effect from 31st January, 1970?

(ii) If not, to what relief is he entitled?

(iii) What order?

12. My findings are as follows:—

(i) Yes.

(ii) Not entitled to any relief.

(iii) As per order.

REASONS

13. In January, 1970 or thereabout the company had cars as mentioned below.

Office Cars

car No.	Used by	Driven by
1. MRY-5738	Shri S. R. Mody (Manager for India)	Driver, for
2. MRC-7045	Shri S.R. Sanjana (Sr. Executive)	Driver
3. MRY-5494	Shri P.B. Mehta (City Manager)	Driver
4. MRC-5707	Shri M. A. Mitha and Shri D.B. Gumaste (Jr. Executives)	Driver
5. MRD-4043	Shri N. H. Lalwani (Agency Manager)	Self Driven
6. MRY-2084	Shri K.J. Mehta (Development Officer)	Self Driven
7. MRW-5820	Shri N.A. Nathani (Executive)	Self Driven
	PERSONAL CAR	
8. BMZ-3492	Sri M.P. Lala (Agency Manager)	Car is personal but driver is provided by the company
9. MRZ-3500	Shri N.L. Deruce (Sr. Executive)	Personal and self driven car.

14. Out of the above mentioned cars, there were five cars which were driven by the company's drivers.

15. It appears that car No. MRC 5707 belonging to the company was allowed to be used by two Junior Executives viz. S/Shri M. A. Mitha and D. G. Gumaste. This car used to be driven by Shri Anjilla, as disposed by Shri M. A. Mitha at Ex. 15/E. Shri Anjilla also

admits in his evidence Ex. 14/W that he was attached to car No. MRC 5707 which was used by S/Shri Mitha and Gumaste. There can be therefore no doubt that Shri Anjilla was driving car No. MRC 5707 allowed to be used by S/shri Mitha and Gumaste Junior Executives, by the company.

15. Shri Mitha Ex. 15/E states on oath that one of the two Junior Executives namely Shri Gumaste was transferred to U.K. in December, 1969 and as only one Junior executive remained with the company, it did not think fit to give the facility of the car to the remaining one Junior Executive only. His evidence further shows that in January 1970 he was informed by the company that the facility of the car to the Junior Executive would be discontinued.

16. Shri Anjilla's witness Shri Andrew P. Serrao, Ex 4/W says in his evidence that the Junior Executive whose car facility was discontinued was given conveyance allowance.

16. From the evidence on record it is clear that the car No. MRC-5707 driven by Shri Anjilla and allowed to be used by two Junior Executives *viz.* S/shri Mitha and Gumaste was sold on 30th January, 1970 because Shri Gumaste was transferred to U.K. and because the company discontinued the facility of the use of car by the remaining one Junior Executive, giving him conveyance allowance.

17. In January, 1970 or thereabout the company had 5 Drivers for driving 5 cars as mentioned below:—

S. No.	Name	Date of joining	Category
1	Shri M. S. Naik	1-4-1962	Driver
2	Shri R.M. Solanki	1-1-1964	Driver
3	Shri C.I. Fernandes	1-8-1964	Driver
4	G.K. Manchekar	1-1-1965	Driver
5	Shri A.A. Anjilla	16-5-1967	Driver

18. There can be no doubt from the above mentioned seniority list of the Drivers that at the material time Shri Anjilla was the junior most driver.

19. As the company sold one of its cars driven by Shri Anjilla it retrenched the junior most driver namely Shri Anjilla with effect from 31st January, 1970, tendering him retrenchment compensation and notice pay, which he refused to accept.

20. It is clear from the record that Shri Anjilla was retrenched from service because he was the junior most driver. In retrenching him, the company has followed the principle of 'last come first go'. It has also complied with the provisions of Section 25F of the I.D. Act, 1947. It cannot be therefore said that provisions of Section 25F and Section 25G of the I.D. Act were not complied with in this case and that Shri Anjilla's retrenchment is invalid.

21. The Union contends in its written statement Ex. 2/W para. 6 that the company's intention in retrenching Shri Anjilla from service was malafide and that this can be seen from the facts that though Shri Fernandes, Driver went on long leave. Shri Anjilla was not given re-employment in his vacancy. It is contended that this violates Section 25H of the I.D. Act, 1947.

22. Shri Mitha, Ex. 15/E speaks about Shri Fernandes proceeding on leave in December, 1970. According to him, Shri Fernandes proceeded on one month's leave in December 1970. He then extended the leave from time to time. Applications for leave given by Shri Fernandes are produced at Ex. 7/E to 13/E. Shri Fernandes resumed his duty in May, 1971. The company has not employed any new permanent driver after May, 1971.

23. Shri Anjilla was retrenched in January, 1970. Shri Fernandes proceeded on leave in December, 1970, after about 11 months. Shri Anjilla in his evidence Ex. 14/E says that he was getting some badli work in Hindustan Lever Bros. There is nothing on record to show that Shri Anjilla was without employment during the leave vacancy of Shri Fernandes and that he was interested in getting that vacancy. The company's rejoinder Ex. 3/E shows that it has received reliable information that Shri Anjilla has secured employment elsewhere and was not available for temporary work. Shri Anjilla has not denied this allegation. Taking this fact into consideration, it does not appear to me that the company had any malafide intention in retrenching Shri Anjilla and that it violated the provisions of Section 25H.

24. It is not the case of Shri Anjilla that the company's intention in retrenching him was to victimise him. He has not adduced any evidence to show that any authority in the company had any grudge or enmity with him and that on account of this he was retrenched with a view to victimise him. Hence it cannot be said in this case that retrenchment of Shri Anjilla was malafide or with view to victimise him.

25. Shri Gadkari for the Union submits before me that the intention of the company in retrenching Shri Anjilla Driver was to reduce the expenditure and that on account of this the company was bound to give notice of change as required under Section 9A of the I. D. Act, 1947. As such notice was not given in this case, the action of the company in rationalising the working force of drivers amounts to illegal change and the retrenchment arising on account of illegal change is itself illegal.

26. In support of the contention raised by Shri Gadkari in his arguments as well as in the written statement he relies on Section 9A of the I.D. Act, 1947 read with items 10 and 11 in Fourth Schedule to the Act.

27. Section 9A of the I. D. Act, 1947 is as follows:—

"9-A. *Notice of change*—No employer, who proposes to effect any change in the conditions of service applicable to any workmen in respect of any matter specified in the Fourth Schedule shall effect such change—

(a) without giving to the workmen likely to be affected by such change a notice in the prescribed manner of the nature of the change proposed to be effected, or

(b) within twenty-one days of giving such notice provided that no notice shall be required for effecting any such change.

(a) where the change is effected in pursuance of any settlement, award or decision of the Appellate Tribunal constituted under the Industrial Disputes (Appellate Tribunal Act, 48 of 1950; or

(b) where the workmen likely to be affected by the change are person to whom the Funlamental and Supplementary Rules Civil Services (Classification, control an Appeal) Rules, Civil Service Regulation Civilians in Defence Services, (Classification, Control Appeal) Rules or the India Railway Establishment Code or any other rules or regulations that may be notified in this behalf by the appropriate Government in the Official Gazette apply."

28. Fourth Schedule relates to conditions of Service for change of which Notice is to be given. Item 10 and 11 are as follows:—

"10. *Rationalisations.*—standardisation or improvement of plant or technique which is likely to lead to retrenchment of workmen.;

11. Any increases or reduction (other than casual) in the number of persons employed or to be employed in any occupation or process or department or shift not occasioned by circumstances over which the employer has no control."

29. The definition of 'rationalisation' given in Oxford Illustrated Dictionery is as follows:—

"*Rationalize*—Reorganize (industry etc) on scientific lines, with elimination of waste of labour, time, and materials and reduction of other costs."

30. On reading Section 9A of the I. D. Act, referred to above it is clear that notice of change would be required in this case if the retrenchment of Shri Anjilla on the ground that he became surplus as one of the cars which he was driving was disposed of, amounts to change in the conditions of his service.

31. Shri Mokeshi for the company contends that fourth schedule has to be read alongwith Section 9A and not independently. He further submits that as the car driven by Shri Anjilla was sold on 30th January, 1970 and as Shri Anjilla became surplus and as he was retrenched on this account on 31st January, 1970, it cannot be said that this amounts to change in the conditions of service. He further submits that Section 9A does not apply to the present case as there is no change in the conditions of service of other persons. In suport of this he relies on the ruling reported in 1970, II,LLJ, Page 611 between L. M. Thapar and others and State of Bihar.

32. The ruling referred to above lays down as follows:—

"In the instant case the petitioners were prosecuted under S.31(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 for the alleged violation of S. 33(1)(a) of the Industrial Disputes Act on the allegation that during the pendency of conciliation proceedings before the conciliation officer, the petitioners retrenched 276 workmen thereby altering the conditions of service of the workmen.

Allowing the writ petition and quashing the prosecution, held that in the Industrial Disputes Act there is nothing that fetters the right to retrench and it is for the management to decide the strength of its labour force, for the number of workmen required to carry out efficiently the work involved in the industrial undertaking of any employer has to be determined by the management in its discretion and when there is an occasion when the number of employees has exceeded the reasonable and legitimate requirements of the undertaking and if some workmen become surplus it is open to the management to retrench them on the terms and conditons as provided by S. 25F, of the Act. Retrenchment cannot ordinarily amount to an alternation in the conditions of service. The expression 'conditions of service' really implied the actual continuance of the relationship of employer and employees and once the service of a particular employee is terminated there is no question of alteration in the conditions of service. It is not necessary to discuss S. 33(1)(b) as it has no application in present case; retrenchment is not discharge or dismissal within the meaning of this subsection. That being so on a plain reading of the language of S. 33(1)(a) it cannot be reasonably held that the employers by their act of retrenchment of 276 workers contravened the provisions of S.33(1)(a) as could justify the filing of a petition of complaint and consequent taking of cognizance on that basis under S34 of the Act.

Dealing with the scope of S.31(1) of the Act held that an enquiry into the BONA FIDES of retrenchment in such cases will be beyond the jurisdiction of the criminal court as it has no power under the Industrial Disputes Act to look into the validity or otherwise of the retrenchment by the management. Specific power for the purpose has been given to the Industrial Tribunal in a reference made under S. 10 of the Act. If the termination of service was a colourable exercise of the power or was a result of victimization or unfair labour practice it was for the Industrial Tribunal which would have the jurisdiction to intervene and set aside such termination."

33. There can be no doubt from the above mentioned ruling that the retrenchment cannot ordinarily amount to an alteration in the conditions of service, and that the expression 'conditions of service' really implied the actual continuance of the relationship of the employer and employee and once the service of a particular employee is terminated there is no question of alteration in the conditions of service.

34. In the present case after the services of Shri Anjilla was retrenched, the relationship of employer and employee did not continue and there was no question of alteration in the conditions of his service. This ruling clearly supports the contention of Shri Mokashi.

35. The learned Advocate Shri Gadkari contends that the reduction in the number of cars of the company for saving expenditure has resulted in the retrenchment of Shri Anjilla and that this amounts to rationalisation within the meaning of item 10 in the fourth Schedule. He therefore submits that such charge requires a notice under Section 9A to be given. I am unable to accept this contention. If we read the whole expression given in item No. 10 it means rationalisation of plant or technique which is likely to lead to retrenchment of workmen. What I understand from this is that if computer is used in any office and on account of this the workmen are likely to be reduced it would amount to change in service conditions of the employees. Hence notice in such case required, and not in the case which I am deciding. By retrenching Shri Anjilla the services conditions of other employees have not been affected.

36. The learned Advocate Shri Gadkari contends that on account of retrenchment of Shri Anjilla, the number of drivers employed or to be employed in the occupation of the company was reduced, and that this reduction was not occasioned by circumstances over which the employer has no control. He therefore contends that the present case falls under item 11 of the Fourth Schedule and that on account of this it amounts to change in conditions of service of other employees. This item number 11 has to be read with Section 9A. It cannot be read independently of Section 9A of the I.D. Act, 1947.

37, Requirement of notice to workmen would arise only if they are likely to be affected prejudically. Change in the conditions of service contemplated in the Section should be understood in that sence. The expression condition of service really implies the actual continuance of the relationship of employer and employee. It would not cover the case of wrongful discharge or termination of service.

37.A. If we read Section 9A of the I.D. Act, 1947 and item 11 in fourth schedule in the light of the judgement relied upon by Shri Mokashi referred to above, it will be clear that it cannot be said in this case that on account of retrenchment of Shri Anjilla other workmen were likely to be affected prejudicially. Hence in the present case it cannot be said that there was any change in the service conditions of the employees, on account of reduction in the number of the employees employed or to be employed by the company and that notice under Section 9A read with item 11 of the fourth schedule was necessary.

38. The learned Advocate Shri Gadkari for the Union contends that after the retrechment of Shri Anjilla the workload of other Drivers had increased and that on account of this the service conditions of other Drivers were changed. This contention cannot be also accepted.

39. Shri Andrew P. Serrao, Ex. 4/W is the Head Clerk in Eagle Star Insurance Co. Ltd., Bombay. He is an office bearer of the General Insurance Employees Union. His evidence shows that one Driver out of four made complaint to the Union that the workload had increased What he wants to say is that on account of retrenchment of Shri Anjilla the remaining four drivers in the company had to do more work and on account of this there was change in the service conditions of other employees.

40. In his cross-examination he says as follows:—

> "I am the Vice-President of the Union. I am group Secretary of the Eagle Star Unit. The complaint regarding workload was made in writing to the Union, some time in 1970. I did not make written representation to the company but I made oral representation."

41. In the first place the Union has not produced the written complaint made to it in 1970 on record. In the absence of this written complaint alleged to have been received by the Union, it is difficult to attach any weight to the testimony of this witness when he says that the complaint regarding workload was made in writing to the Union some time in 1970. If the Union would have received written complaint from the Drivers regarding increase in the workload on account of retrenchment of Shri Anjilla, the Union would not have failed to make written representation to the company in this respect. In the absence of written grievance to the company, no weight can be attached to the testimony of the witness that he made oral representation to the company regarding increase in the workload for other drivers.

42. It is not also undestood as to why the Drivers who made oral complain to this witness were not examined in this case. In the absence of their evidence there is no corroboration to the testimony of this witness when he speaks about the complaint received from the Driver.

43. It is contended in the rejoinder Ex. 3/E, para. 4 that the Drivers were and are working for their normal duty hours. What this means is that the remaining Drivers with the company were not required to put additional work beyond their normal duty hours, even after the retrenchment of Shri anjilla. As Shri Anjilla was retrenched on account of sale of one car driven by him, there could not have been any occasion for the remaining Drivers, to do more work on the car on which Shri Anjilla was working. I am therefore unable to accept the Union's contention that there was increase in the workload of other Drivers with the company, after the retrenchment of Shri Anjilla. Hence it cannot be said that there was any change in the service conditions of other Drivers on account of retrenchment of Shri Anjilla.

44. *In short, it will be clear from the above discussions* that Shri Anjilla was retrenched by the company because he was found surplus after the sale of the car No. MRC-5707 and that his retrenchment was proper and legal.

45. As the action of the company in retrenching Shri Anjilla was justified, Shri Anjilla is not entitled to any relief. Hence my findings on point numbers i and ii are as above.

Point No. iii

46. In view of the above findings, I pass the following order:

ORDER

(i) It is hereby declared that Eagle Star Insurance Company Limited was justified in retrenching Shri A. A. Anjilla, Driver with effect from 31st January, 1970 and that Shri Anjilla is not entitled to any relief.

(ii) Award is made accordingly.

(iii) No order as costs.

(Sd.) N. K. VANI,
Presiding Officer,
Central Government Tribunal No. 2,
Bombay.
21-6-72.

[No. F. L.17012/4/71-LR.I.]

ORDERS

New Delhi, the 22nd April 1972

S.O. 2102.—Whereas the Central Goverment is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Dehri Rohtas Light Railway Company Limited, Dalmianagar and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal (No. 1), Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

> "Whether the management of Messrs Dehri Rohtas Light Railway Company Limited, Dalmianagar is justified in refusing to designate Shri B. P. Gupta as time keeper and fix the prescribed pay scale of time-keeper? If not, to what relief is the workman entitled and from which date?"

[No. L.41011/30/71/LRIII.]

(श्रम और रोजगार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1972

का० आ० 2102.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स डेहरी रोहतास लाइट रेलवे कम्पनी लिमिटेड, डालमियानगर के प्रबंध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण (सं0 1) धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या मैसर्स डेहरी रोहतास लाइट रेलवे कम्पनी लिमिटेड, डालमियानगर के प्रबंधमण्डल का श्री बी0 पी0 गुप्ता को समयपाल के रूप में पदभिहित करने और समयपाल का विहित वेतनमान नियत करने से इन्कार करना न्यायोचित है ? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का और किस तारीख से हकदार है ।

[सं० एल० 41011/30/71-एल० आर० III]

New Delhi, the 25th April, 1972

S.O. 2103.—Whereas the industrial dispute specified in the Schedule hereto annexed is pending before Thiru K. Seetharama Rao, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Madras;

And whereas, the services of Thiru K. Seetharama Rao have ceased to be available;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby withdraws the proceedings in relating to the said dispute from Thiru K. Seetharama Rao, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Madras and transfers, the same to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta constituted under section 7A of the said Act, and directs that the said Tribunal shall proceed with the said proceedings from the stage at which they are transferred to it and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

Serial No.	Parties to the dispute	Order No. and date.	S. No. of Gazette and year of publication
1.	National and Grindlays Bank Limited and their workmen.	23/106/70/LRIII dated the 10th December, 1970.	4067 of 1970.
		Subsequent Order No. 23/106/70/LRIII dated the 3rd July, 1971.	3834 of 1971

[No. 23/106/70/LRIII]

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1972

का० आ० 2103.—यतः इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद थिरु के० सीथारामाराव, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, मद्रास के समक्ष लम्बित है ;

और यतः थिरु के सीथारामाराव की सेवाएं अब उपलब्ध नहीं रही है ;

अत : अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 33 ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवादों से सम्बद्ध कार्यवाहियों को थिरु के० सीथारामाव, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरणरती मद्रास से वापस लेकर उसे उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को अन्तरित क है और निदेश देती है कि उक्त अधिकरण उक्त कार्यवाहियों पर उसी प्रक्रम से कार्यवाही करेगा जिस पर वे उसे अन्तरित की गई है और विधि के अनुसार उसका निपटान करेगा ।

अनुसूची

क्रम सं०	विवाद के पक्षकार	आदेश सं० और तारीख	राजपत्र की का० आ० सं० और प्रकाशन का वर्ष
1	नेशनल एंड ग्रिण्डलेज बैंक लिमिटेड और उनके कर्मकार	23/196/70/एल आरIII तारीख 10 दिसम्बर 1970	1970 का 4067
		पश्चात्वर्ती आदेश सं० 23/106/70/एल आर III तारीख 3 जुलाई 1971	1971 का 3834

[सं० 23/106/70/एल० आर० III]

New Delhi, the 28th April, 1972

S.O. 2104.—Whereas the industrial dispute specified in the Schedule hereto annexed is pending before Shri Gopal Narain Sharma, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Jaipur;

And, whereas, the services of Shri Gopal Narain Sharma have ceased to be available;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and sub-section (1) of section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri Mohammed Yaqoob Khan as the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur, withdraws the proceedings in relation to the said dispute pending before Shri Gopal Narain Sharma and transfers the same to the said Industrial Trbiunal, Jaipur constituted with Shri Mohammed Yaqoob Khan as Presiding Officer thereof and directs that the said Tribunal shall proceed wtih the proceedings from the stage at which they are transferred to it and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

Parties to the dispute.	Order No. and date.	S.O. No. of Gazette and year of publication.
Punjab National Bank and their workmen. . . .	23-/38/70/LRIII dated the 29th August, 1970	3104/70

[No. 23/38/70-LRIII]

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1972

का० आ० 2104.—यतः इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद श्री गोपाल नारायण शर्मा, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, जयपुर, के समक्ष लम्बित है ;

और यत : श्री गोपाल नारायण शर्मा की सेवायें अब उपलब्ध नहीं रहीं हैं;

अतः, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और 33 ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री मोहम्मद याकूब खां होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर ; होगा, श्री गोपाल नारायण शर्मा के समक्ष लम्बित उक्त विवाद से सम्बद्ध कार्यवाहियों को वापस लेती है और उसे उक्त औद्योगिक अधिकरण जयपुर को, जो श्री मोहम्मद याकूब खां को उसका पीठासीन अधिकारी बनाते हुए गठित किया गया है, अन्तरित करती है और निदेश देती है कि उक्त अधिकरण उक्त कार्यवाहियों पर उसी प्रक्रम से कार्यवाही करेगा जिस पर वह उसे अन्तरित की गई है और विधि के अनुसार उसका निपटान करेगा ।

अनुसूची

विवाद के पक्षकार	आदेश सं० और तारीख	राजपत्र की का० आ० सं० और प्रकाशन का वर्ष
पंजाब नेशनल बैंक और उससे कर्मकार	23/38/70—एल आर III तारीख 29 अगस्त 1970	3104/70

[सं० 23/38/70-एल० आर० III]

New Delhi, the 22nd May 1972

S.O. 2105.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Engineer Stores Depot, Panagar and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

(1) Whether the action of the Officer Commanding, Engineer Stores Depot, Panagar in terminating the services of Sarvashri B. R. Ganguly, S. Roy and Kashi Prasad, IMEs with effect from the 15th Novmeber, 1971 is justified? If not, to what relief are the workmen entitled?

(2) Whether the action of the Officer Commanding, Panagar in transferring Sarvashri N. C. Chakraborty and A. K. Ghatak Joint Secretary and Treasurer respectively of the Military Engineer Workers Union, Engineer Stores Depot, Panagar from Panagar is justified? If not, to what relief are the workmen entitled?

[No. L.14011/2/71-LR.I.]

नई दिल्ली, 22 मई, 1972

का० आ० 2105.— यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में इंजीनियर स्टोर्स डिपो, पानागढ़ के प्रबंध से सम्बद्ध नियोजकों और उन के कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यत : केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अत : अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

(1) क्या अफसर कमांण्डिंग इंजीनियर स्टोर डिपो, पानागढ़ की सर्वश्री बी० आर० गांगुली एस० राय और काशी प्रसाद, ई० एम० ई० की सेवाओं 15 नवम्बर 1971 से समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

(2) क्या अफसर कमांडिंग, पानागढ़ की सर्वश्री एन० ई० चक्रवर्ती और ए० के० घटक मिलिट्री इंजीनियर वर्कर्स यूनियन, इंजीनियर स्टोर्स डिपो, पानागढ़ के क्रमश : संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष का बाहर के स्थान को स्थानान्तरण करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार

[सं० एल/14011/2/81-एल आर I]

New Delhi, the 24th July 1972

S.O. 2106.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to Food Corporation of India, and its workmen represented by Food Corporation of India Workers' Union, Calcutta;

And, whereas the Said employers and workmen have, by a written agreement, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to arbitration by the person specified therein, and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement which was received by it on the 11th July, 1972.

Agreement

(Under Section 10A of the Industrial Disputes Act 1947).

BETWEEN

Name of the Parties

Representing Employers.—Sri S. B. Mazumder, Regional Manager, Food Corporation of India West Bengal, 11/A, Mirza Ghalib Street, Calcutta-16.

2. Sri G. K. Chugani, Joint Manager (Port Operation), Food Corporation of India, 4 Mangoe Lane, Calcutta.

3. Sri B. K. Singh, Regional Manager, Food Corporation of India, Sinha Library Road, Patna (Bihar).

Representing workmen.—1. Sri H. P. Singh, General Secretary, Food Corporation of India Workers' Union, 58, Diamond Harbour Road, Calcutta-23.

2. Sri G. S. Jena, Joint Secretary, Food Corporation of India Workers' Union, 58, Diamond Harbour Road, Calcutta-23.

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration Sri R.J.T.D'Mello, Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi.

(i) Specific matters in dispute.—"Whether the demand of the departmentalised labourers of the Food Corporation of India, Eastern Zone for wages for the period from 11th February 1972 to 14th February 1972, when they were on strike is justified; if so, what relief they are entitled to".

(ii) Details of the parties to the dispute, including the names and address of the establishments.—1. Regional Manager, Food Corporation of India, West Bengal, 11/A, Mirza Ghalib Street, Calcutta-16.

2. Joint Manager (Port Operation) Food Corporation of India, 4, Mangoe Lane, Calcutta.-1.

3. Regional Manager, Food Corporation of India, Sinha Library Road, Patna (Bihar).

(iii) Name of the workmen in case he himself is involved in the dispute or the name of the Union, if any, representing the workman in question.—Food Corporation of India Workers' Union, 58, Diamond Harbour Road, Calcutta-23

(iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected.—3,000 (Appxly.).

(v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute.—3,000 (Appxly.).

We further agree that the majority decisions of the arbitrator be binding on us.

The arbitrator shall make his award within a period of 3 months (three months) here specify the period agreed upon by the parties) or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Signature of the parties

Representing Employers:
(Sd.) S. B. MAZUMDER I.A.S.
Regional Manager,
Food Corporation of India
Calcutta Region.

(Sd.) G.K.CHUNGANI,
Joint Manager (P.O.),
Food Corporation of India.
Calcutta.

Representing Workmen:
(Sd) H. P. SINGH.

(Sd.) G. S. JENA,
Food Corporation of India
Worker's Union
58, Diamond Harbour Road,
Calcutta-23.

(Sd.) B. K. SINGH.

WITNESSES:
1. (Sd.) B. R. GHOSH.
2. (Sd.) U. N. BHAR.

[No. L.42013/1/72/LRIII.]
S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1972

का० आ० 2106.—यतः भारत के खाद्य निगम के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संघ, कलकत्ता करता है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः उक्त नियोजकों और कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें वर्णित व्यक्ति के माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ;

अतः अब औद्योगिक अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त मध्यस्थम करार जो उसे 11 जुलाई 1972 को मिला था, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है ।

करार

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन)

बीच

पक्षकारों के नाम :

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले

1. श्री एस० बी मजूमदार, क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारत का खाद्य निगम, पश्चिम बंगाल, 11/ए, मिर्जा गालिब स्ट्रीट, कलकत्ता-16।
2. श्री जो० के० चुगानो, संयुक्त प्रबन्धक (पत्तन कार्य), भारत का खाद्य निगम, 4 मैंगो लेन, कलकत्ता-1 ।
3. श्री बो० के० सिंह, क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारत का खाद्य निगम, सिन्हा लाइब्रेरी रोड, पटना (बिहार) ।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले :

1. श्री एच० पी० सिंह, प्रधान सचिव, भारत खाद्य निगम श्रमिक संघ, 58 डायमण्ड हारबर रोड कलकत्ता-23 ।
2. श्री जी० एस० जेना संयुक्त सचिव, भारत खाद्य, निगम श्रमिक संघ, 58, डायमण्ड हारबर रोड, कलकत्ता-23 ।

पक्षोंकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री आर० जे० टी० डोमेलो, मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली के मध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का एतद्द्वारा करार किया गया है

(i) विनिर्दिष्ट विवाद ग्रस्त विषय :

"क्या भारत के खाद्य निगम पूर्वी क्षेत्र के विभागीकृत श्रमिकों की 11-2-1972 से 14-2-1972 की समयावधि जब कि वे हड़ताल पर थे, की मजदूरियों की मांग न्यायोचित है । यदि हां, तो वे किस अनुतोष के हकदार हैं ।"

(ii) विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिसमें अंतर्वलित प्रतिष्ठानों का नाम और पता भी सम्मिलित है ।

1. क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारत का खाद्य निगम, पश्चिम बंगाल 11/ए, मिर्जागालिब स्ट्रीट, कलकत्ता-16 ।
2. संयुक्त प्रबन्धक (पत्तन कार्य), भारत का खाद्य निगम, 4 मैंगो लेन, कलकत्ता-1 ।
3. क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारत का खाद्य निगम, सिन्हा लाइब्रेरी रोड, पटना (बिहार)

(iii) कर्मकार का नाम यदि वह स्वय विवाद में अन्तर्वलित है अथवा उस संघ में यदि कोई हो, का नाम जो सम्बन्धित कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो ।	भारत खाद्य निगम श्रमिक संघ, 58, डायमण्ड हारबर रोड, कलकत्ता-23
(iv) प्रभावित उपक्रम मे नियोजितकर्मकारोंकी संख्या ।	3000 (लगभग)
(v) विवाद द्वारा प्रभावित या सम्भवयत: प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या ।	3000 (लगभग)

हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थ के बहुमत विनिश्चय हम पर आबद्धकर होगा ।

मध्यस्थ अपना पंचाट 3 मास (तीन मास) की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, देगा । यदि पूर्व वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम के लिए आदेश स्वत: रद्द हो जाएगा और हम नए माध्यस्थम् के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे ।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले :	कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले
	ह०/– एम० पी० सिंह
ह०/– एस० बी० मजूमदार, आई० ए० एस० क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारत का खाद्य निगम, कलकत्ता क्षेत्र ।	ह०/– जी एम० जेना भारत खाद्य निगम श्रमिक संघ, 58, डायमण्ड हरबर रोड, कलकत्ता–23 ।

ह०/– जी० के० चुगानी,
संयुक्त प्रबन्ध, (पी० ओ०)
भारत का खाद्य निगम
कलकत्ता ।

ह०/– बी० के० सिंह ।

साक्षी :

1. ह०/– बी० आर० घोष
2. ह० /– यू० एन० भर

[संख्या एल–42013/1/72–एल०आर० 3]

एस० एस० सहस्रानामन, अवर सचिव ।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 25th July 1972

S.O. 2107.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8D of the Wakf Act, 1954 (29 of 1954), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Wakf Council Rules, 1965, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Wakf Council (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Wakf Council Rules, 1965(hereinafter referred to as the said rules), in rule 8, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(3) The Chairman may, at his discretion, grant travelling allowance and daily allowance to any special invitee to any meeting of the Council or its Committee or Sub-Committee at the rate admissible to a member."

3. In rule 9 of the said rules, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(3) (a) A member, resident at a place here the meeting of the Council is held, will not be entitled to travelling allowance and daily allowance for attending the meeting of the Council, but only to actual cost of conveyance hired subject to a maximum of ten rupees per day.

(b) The controlling officer shall verify the claim and satisfy himself that the actual expenditure was not less than the amount claimed. Where the controlling officer is not satisfied with the details, he may, at his discretion, limit the cost of conveyance hired to road milage.

(c) If the member uses his own car, he will be granted milage allowance at the rates admissible to an official of the first grade subject to a maximum of ten rupees per day."

4. In rule 11 of the said rules, after sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

"(2A) The appointing authority of the employees of the Council shall be the disciplinary authority and shall be competent to impose all kinds of punishments including dismissal.

(2B) In cases of disciplinary proceedings against the employees of the Council, where the disciplinary authority is the Chairman, the Council shall be the appellate authority and where the disciplinary authority is the Secretary, the Chairman shall be the appellate authority.

(2C) The Secretary shall be competent to make appointment in regard to the post of Lower Division Clerk and he shall also be the authority competent to order removal of, or impose punishment on a person holding such post."

5. After rule 12 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:—

"12A. *Sanction of expenditure by Chairman and Secretary.*—(1) Subject to the provisions of the budget,—

(a) the Chairman shall sanction a recurring expenditure upto one thousand rupees, and a non-recurring expenditure of two thousand rupees, on each item per annum.

(b) the Secretary shall sanction a recurring expenditure upto hundred and fifty rupees, and a non-recrurring expenditure up to five hundred rupees, on each item per annum.

(2) The Secretary or in his absence the Administrative Officer, if any, shall draw cheques for the sanctioned expenditure. The Administrative Officer shall supervise the maintenance of all the account registers to be maintained in the Council Office and shall certify the entries made there in."

6. After rule 13 of the said rules, the following rules shall be inserted, namely:—

"14. *Powers of Secretary as respects staff.*—The Secretary shall, in respect of all the staff of the Council under his control and supervision, have the power to sanction,—

(a) increment;

(b) leave (except earned leave in the case of Ad-Ministrative Officer);

(c) allowances and advances as admissible;

(d) expenditure up to one hundred rupees for repairs of furniture, typewriter, bicycle, clock, water coolers, electric heater, which or on the stock register of the Council Office and an expenditure upto twenty-five rupees if any of the aforesaid articles needs servicing;

(e) expenditure up to two hundred rupees for arranging, with the approval of the Chairman, entertainment such as dinner, lunch or at-home for members and special invitees of the Council or its Committee of Sub-Committee.

15. *Additional qualifications for appointment to posts in Council.*—In addition to the qualifications required of a person under the rules for the time being in force in the Central Government for appointment to the posts sanctioned for the Council, a candidate shall have a working knowledge of Urdu and shall be able to read Persian and Arabic. In the case of persons to be appointed to the lower division or upper division grade, a knowledge of typing in Urdu shall be necessary.

16. *Exemption from recruitment through Employment Exchange.*—Where persons having the requisite qualifications are not available through Employment Exchange for appointment to the posts of staff of the Council, then direct recruitment to the staff of the Council may be made from outside.".

[No. 8(5)/70-Waqf.]

E. VENKATESWARAN, Dy. Secy.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1972

का०आ० 2107.—वक्फ अधिनियम, 1954 (1954 का 29) की धारा 8 घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय वक्फ परिषद् नियम, 1965 को संशोधित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है ; अर्थात्

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय वक्फ परिषद्, (संशोधन) नियम, 1972 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय वक्फ परिषद नियम, 1965 के (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है। नियम 8 में, उपनियम (2)के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3) अध्यक्ष, स्वविवेकानुसार, परिषद् या उसकी समिति या उपसमिति की किसी बैठक में किसी विशेष आमन्त्रित व्यक्ति को, किसी सदस्य को अनुज्ञेय दर से, यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता अनुदत्त कर सकेगा।"

3. उक्त नियम के नियम 9 में उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3) (क) कोई सदस्य, जो उस स्थान का निवासी हो जहां परिषद् की बैठक हुई हो, परिषद् की बैठक में उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का हकदार नहीं होगा किन्तु वह प्रतिवदन अधिक से अधिक दस रुपए तक भाड़े पर ली गई सवारी केवल वास्तविक व्यय का हकदार होगा ।

(ख) नियंत्रक अधिकारी दावे को सत्यापित करेगा और इस बारे में अपना समाधान करेगा कि वास्तविक व्यय दावा की गई रकम से कम नहीं है । जहां नियंत्रक अधिकारी का उस विवरण से समाधान न हो सके वहां वह, स्वविवेकानुसार, भाड़े पर ली गई सवारी के खर्च को सड़क मील भत्ते तक सीमित कर सकेगा ।

(ग) यदि सदस्य अपनी कार का प्रयोग करता है तो प्रतिदिन अधिक से अधिक दस रुपए तक, उसे प्रथम ग्रेड के अधिकारी को अनुज्ञेय दर से, मील भत्ता अनुदत्त किया जायगा ।"

4. उक्त नियम के नियम 11 में उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किए जायेंगे, अर्थात् :—

"(2क) परिषद् के कर्मचारियों का नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासन प्राधिकारी होगा और पदच्युत करने के साथ वह सभी प्रकार के दण्ड अधिरोपित करने के लिए सक्षम होगा ।

(2ख) जहां परिषद् के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों के मामलों के अध्यक्ष अनुशासनिक प्राधिकारी भी है वहां परिषद् अपील प्राधिकारी होगी और जहां सचिव अनुशासनिक प्राधिकारी है वहां अध्यक्ष अपील प्राधिकारी होगा ।

(2ग) सचिव निम्न श्रेणी लिपिक के पद के सम्बन्ध में नियुक्ति करने के लिए सक्षम होगा और वह ऐसा

पद धारण करने वाले व्यक्ति को उस पद पर से हटाए जाने का आदेश देने या कोई दण्ड अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।"

5. उक्त नियम के नियम 12 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा ; अर्थात् :—

"12 क. **अध्यक्ष और सचिव द्वारा व्यय की मंजूरी**:—

(1) बजट के उपबंधों के अधीन रहते हुए ;—

(क) अध्यक्ष प्रत्यक मद पर एक हजार रुपए प्रतिवर्ष तक का आवर्ती व्यय और दो हजार रुपए प्रतिवर्ष तक का अनावर्ती व्यय मन्जूर करेगा ;

(ख) सचिव प्रत्येक मद पर ढाई सौ रुपए प्रतिवर्ष तक का आवर्ती व्यय और पांच सौ रुपए प्रतिवर्ष तक का अनावर्ती व्यय मन्जूर करेगा ;

(2) सचिव या उसकी अनुपस्थिति में प्रशासनिक अधिकारी, यदि कोई हो, मंजूर किए गए व्यय के लिए चैक काटेगा। प्रशासनिक अधिकारी परिषद् के कार्यालय में रख गए सभी लेखा रजिस्टरों की देखभाल रखेगा और उनमें की गई प्रविष्टियों को प्रमाणित करेगा।"

6. उक्त नियम के नियम 13 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तस्थापित किए जायेंगे अर्थात् :—

"14—**कर्मचारिवृन्द के सम्बन्ध में सचिव की शक्तियां**.—सचिव को, उसके नियंत्रक और पर्यवेक्षण के अधीन परिषद् के सभी कर्मचारिवृन्द के सम्बन्ध में निम्नलिखित मन्जूर करने की शक्ति होगी,—

(क) वेतन वृद्धि;

(ख) छुट्टी (प्रशासनिक अधिकारी की दशा में अर्जित छुट्टी के सिवाय) ;

(ग) यथा अनुज्ञेय भत्ते और अग्रिम ;

(घ) फर्नीचर, टाईपराइटर साइकिल, घड़ी, वाटर कूलर विद्युत हीटर की जो परिषद् के कार्यालय के स्टाक रजिस्टर में दर्ज हों, मरम्मत के लिए सौ रुपए तक का व्यय और यदि उपरोक्त वस्तुओं में से किसी की सर्विस करने की आवश्यकता हो तो उसके लिए पच्चीस रुपए तक का व्यय;

(ङ) अध्यक्ष के अनुमोदन के परिषद् या उसकी समिति या उपसमिति के सदस्यों और विशेष आमन्त्रित व्यक्तियों के लिए रात्रि-भोजन, मध्यान्ह-भोजन या जलपान आदि आतिथ्य सत्कार का प्रबन्धक करने के लिए दो सौ रुपए तक का व्यय।

15. **परिषद के पद पर नियुक्ति के लिए अतिरिक्त अर्हतायें**:—परिषद् के लिए मंजूर किए गए पदों पर नियुक्ति के लिए, केन्द्रीय सरकार में तत्समय प्रवृत्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति की अपेक्षित अर्हताओं के अतिरिक्त, अभ्यर्थी को उर्दू में काम करने योग्य ज्ञान होना चाहिए तथा फारसी और अरबी पढ़ने की योग्यता होनी चाहिए। निम्न-श्रेणी या उच्च-श्रेणी (ग्रेड) में नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उर्दू में टंकण का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

16. **रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती करने से छूट**:—जहां परिषद् के कर्मचारिवृन्द के पदों पर नियुक्ति के लिए रोजगार कार्यालय के माध्यम से अपेक्षित अर्हता रखने वाले व्यक्ति उपलब्ध न हों, वहां परिषद् के कर्मचारिवृन्द के लिए सीधी भर्ती बाहर से की जा सकती है।"

[सं० 8(5)/70—वक्फ]

ई० वेंकटेश्वरन, उप सचिव।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

INCOME-TAX

New Delhi, the 11th July 1972

S.O. 2108.—In exercise of the powers conferred by clause (43 B) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of all the previous orders on the subject, the Central Government hereby authorises the Commissioners of Income-tax and the Addl. Commissioners of Income-tax, specified in the Table appended to this Notification, to exercise the powers of Tax Recovery Commissioners.

TABLE

S. No.	*Designation of Officer*
1.	Commissioner of Income-tax (Recovery), Delhi.
2.	Commissioner of Income-tax (Recovery), Cochin.
3.	Commissioner of Income-tax (Recovery), Nagpur.
4.	Commissioner of Income-tax (Recovery), Madras.
5.	Commissioner of Income-tax (Central), Calcutta.
6.	Commissioner of Income-tax (Recovery), Calcutta.
7.	Additional Commissioner of Income-tax (Recovery I), Calcutta.
8.	Additional Commissioner of Income-tax (Recovery II) Calcutta.
9.	Additional Commissioner of Income-tax (Recovery), Hyderabad.
10.	Additional Commissioner of Income-tax (Recovery), Shillong.
11.	Additional Commissioner of Income-tax (Recovery), Patna.
12.	Additional Commissioner of Income-tax (Recovery I), Bombay.
13.	Additional Commissioner of Income-tax (Recovery II), Bombay.

S. No.	Designation of Officer
14.	Additional Commissioner of Income-tax (Recovery), Ahmedabad.
15.	Additional Commissioner of Income-tax (Recovery), Poona.
16.	Additional Commissioner of Income-tax (Recovery), Patiala.
17.	Additional Commissioner of Income-tax (Recovery), Jaipur.
18.	Additional Commissioner of Income-tax, Lucknow.
19.	Additional Commissioner of Income-tax, Kanpur.

[No. 136 (F. No. 404/220/72-ITCC).]

A. K. NASTA, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

आयकर

नई दिल्ली, 11 जुलाई 1972

एस०ओ० 2108.—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (43ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय से संबंधित सभी पूर्व आदेशों को अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस अधिसूचना से संलग्न सारणी में विनिर्दिष्ट आयकर आयुक्तों और अपर आयकर आयुक्तों को, कर वसूली आयुक्तों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है ।

सारणी

क्रम सं०	अधिकारी का पदाभिदान
1.	आयकर आयुक्त (वसूली), दिल्ली ।
2.	आयकर आयुक्त (वसूली), कोचिन ।
3.	आयकर आयुक्त (वसूली), नागपुर ।
4.	आयकर आयुक्त (वसूली), मद्रास ।
5.	आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), कलकत्ता ।
6.	आयकर आयुक्त (वसूली), कलकत्ता ।
7.	अपर आयकर आयुक्त (वसूली–I), कलकत्ता ।
8.	अपर आयकर आयुक्त (वसूली–II), कलकत्ता ।
9.	अपर आयकर आयुक्त (वसूली), हैदराबाद ।
10.	अपर आयकर आयुक्त (वसूली), शिलांग ।
11.	अपर आयकर आयुक्त (वसूली), पटना ।
12.	अपर आयकर आयुक्त (वसूली–I), मुम्बई ।
13.	अपर आयकर आयुक्त (वसूली–II), मुम्बई ।
14.	अपर आयकर आयुक्त (वसूली), अहमदाबाद ।
15.	अपर आयकर आयुक्त (वसूली), पूना ।
16.	अपर आयकर आयुक्त (वसूली), पटियाला ।
17.	अपर आयकर आयुक्त (वसूली), जयपुर ।
18.	अपर आयकर आयुक्त, लखनऊ ।
19.	अपर आयकर आयुक्त, कानपुर ।

[सं० 136 (फा० सं० 404/220/72–आई० टी० सी०]

ए० के० नास्ता, अवर सचिव ।

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

CORRIGENDUM

New Delhi, the 18th March, 1972

S.O. 2109.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf, then Central Board of Direct Taxes, hereby directs that the following correction shall be made in its Notification No. 54 (F.No. 261/1/72-ITJ), dated 6th March, 1972.

In the last line of the Notification, 'for 6th March, 1972' read '9th March, 1972'.

[No. 61 (F.No. 261/1/72-ITJ.]

P. K. SHARAN, Under Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1972

एस० ओ० 2109.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और उस निमित्त उसको समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्द्वारा निदेश देता है कि उसकी अधिसूचना सं० 54 (फा० सं० 261/1/72-आई०टी० जे०) तारीख 6 मार्च, 1972 में निम्नलिखित शुद्धि की जाएगी :

अधिसूचना की अंतिम पंक्ति में, '6-3-1972' के स्थान पर '9-3-1972' पढ़ा जाए ।

[सं० 61 फा० सं० 261/1/72-आई०टी०जे०]

पी० के० शरण, अवर सचिव ।

MINISTRY OF COMMUNICATION

(P. & T. Board)

New Delhi, the 26th July 1972

S.O. 2110.—In pursuance of para (a) of section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as intro-

duced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1st September, 1972 as the date on which the Measured Rate Syetem will be introduced in PALI MARWAR Telephone Exchange, Rajasthan Circle.

[No. 5-40/72-PHB(7).]

संचार विभाग

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1972

एस० ओ० 2110.—स्थाई आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने पाली मारवाड टेलीफोन केन्द्र मे दिनांक 1-9-72 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं० 5-40/72-पी०एच बी(7)]

New Delhi, the 27th July 1972

S.O. 2111.—In pursuance of para (a) of section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1st September, 1972 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in VISNAGAR Telephone Exchange, Gujarat Circle.

[No. 5-6/72-PHB(20).]

H. C. MATHUR, Director of Phones (E).

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1972

एस० ओ० 2111.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने विसनगर टेलीफोन केन्द्र मे दिनांक 1-9-1972 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं० 5-6/72-पी० एच० बी(20)]

एच० सी० माथुर,

निदेशक फोन्स (ई)।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972